हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

27/3/2017/1400/RKS/AG/1

<u>प्रश्न संख्याः 3899</u>

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें कौन सी ऐसी सूचना है जिसको एकत्रित करने के लिए ज्यादा समय लग रहा है? अगर प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा जाए तो इसमें बड़ा स्पेसिफिक सा लिखा है। वैसे मैंने पिछली सूचना भी लेनी थी लेकिन इसमें तो केवल मात्र इस साल की ही सूचना मांगी गई है। इसी सदन के बीच में, मनरेगा से संबंधित मेरे द्वारा पूछा गया एक प्रश्न लगा था, जिसमें आपने पिछले तीन वर्ष की सूचना दी हुई है। आपने पिछेल तीन साल की सूचना दी है, लेकिन जो एक वर्ष की सूचना है, जो वर्ष चला हुआ है इसकी सूचना को एकत्रित करने में, मैं नहीं समझता कि ज्यादा समय लगना चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस सत्र के जो शेष दिन बचे हैं उसमें इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के दौरान यह नहीं हो पाएगा क्योंकि विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सूचना उपलब्ध हो जाएगी तो उसके बाद माननीय सदस्य को बता दिया जाएगा।

27/3/2017/1400/RKS/AG/2

<u>प्रश्न संख्याः 3900</u>

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन सैशन्ज़ से एक ही सड़क का प्रश्न बार-बार पूछ रही हूं। पिछली बार आपने कहा था कि फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए जंगलात को पेपर भेज दिए गए हैं। तब भी मैंने पूछा था कि किस स्तर पर फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए

ये पेपर गए हैं? क्योंकि इसका हम देखें तो 9-10 और 12-13 इतनी पुरानी सड़क है जिसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हो पा रही है, तो इसका काम आगे कैस बढ़ पाएगा? मैं जानना चाहूंगी कि फोरैस्ट क्लीयरैंस के पेपर कहां हैं, डी.पी. आर्ज. कहां है, किस स्तर पर डी.पी. आर्ज. पड़ी है और किस स्तर पर फोरैस्ट क्लीयरैंस के पेपर हैं?

मुख्य **मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, जहां तक फोरैस्ट क्लीयरैंस की बात है the matter is still pending with the Forest Office in Dehradun, I presume. It has been sent for approval.

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि वे पेपर फोरैस्ट विभाग, हिमाचल प्रदेश के पास हैं या सैंटर गवर्नमैंट को भेज दिए गए हैं। यह छोटी सी बात है। पिछले तीन सैशन्ज़ से लगातार मैं एक ही प्रश्न पूछ रही हूं। जब हमारी सरकार के समय की ही डी.पी.आर्ज नहीं बनी हैं तो इन पांच वर्षों में कोई और डी.पी. आर्ज. नहीं बनी होंगी? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि डी.पी. आर्ज. किस स्तर पर पेंडिंग है और फोरैस्ट के पेपर कहां हैं?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.03.2017/1405/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3900 ...क्रमागत

Chief Minister: Speaker, Sir, I will read with entire reply for the benefit of the Hon'ble Member. There are two link roads, namely, Laletta to Banu Mahadev and Boh to Gargoon. They are appearing as MLA priority works. The DPR of Boh to Gargoon road stands prepared and sanctioned amounting to Rs. 374 lacs including a bridge under NABARD. यह सूचना मैं आपके ही प्रश्न के उत्तर में दे रहा हूं।...(व्यवधान)...ठीक है।

श्रीमती सरवीन चौधरी : जो आप धडकू की सूचना दे रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने इसमें नहीं पूछा है। मैंने सिर्फ़ ललेटा बणु महादेव के बारे में ही पूछा है।

मुख्य मंत्री : आपके जितने भी रोड्ज़ हैं, मैं उन सबका ज़िक्र कर रहा था ताकि आपको और सप्लीमैंटरी न पूछना पड़े। अगर आप एक का ही उत्तर चाहती हैं तो जहां तक ललेटा बणु महादेव रोड का प्रश्न है, it will be submitted to Forest Department after getting FRA certificate from Deputy Commissioner of Kangra. Gharohgarh-Sera-Nohra road is not under Public Works Department.

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मैंने जो सप्लीमैंटरी पूछा है उसके उत्तर की तैयारी नहीं है। मैंने इसमें केवल ललेटा बणु महादेव के बारे में पूछा है। जहां तक धरोह गढ़-सेरा नौरा का सवाल है, ये लोक निर्माण विभाग की सड़क नहीं है बल्कि आई.पी.एच. की स्कीम है। इसे कहीं गलती से मेरे प्रश्न में क्लब कर दिया गया है। मैंने इसमें इतना ही पूछा था कि डी.पी.आर. कहां हैं। पिछले तीन सैशन्ज से मैंने लगातार फोरैस्ट की ही बात पूछी थी। इसलिए न तो सरकार काम कर रही है, न फोरैस्ट डिपार्टमैंट और न विभाग ने कोई तैयारी करके आपको इसकी सूचना दी है।

मुख्य मंत्री : मैंने तो पूरी तैयारी की है। मगर जो जवाब मेरे पास आया है, मैं उसके मुताबिक उत्तर दे रहा हूं। यह जो आपकी सड़क है, it is pending at present with Deputy Commissioner, Kangra.

27.03.2017/1405/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 3901

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं इसके दृष्टिगत माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो क्रशर यहां पर दर्शाए गए हैं, क्या इनके अतिरिक्त भी विभाग के पास कोई नए क्रशर लगाने बारे आवेदन आए हैं? मैं

यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहां पर मामलों की बात की गई है, जिन मामलों में विभाग और पुलिस के द्वारा चालान किए गए हैं जो कि कोर्ट में भी चले हुए हैं, इसका मुख्य यह लाभ हुआ है कि सरकार ने जो फ़ैसला लिया था कि जो दरिया, नाले या खड्डें सरकारी हैं, जिनको आपने ऑक्शन किया था, उससे अब पिछले साल की तुलना में काफी कम मामले हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माइनिंग का अधिकतर स्कोप है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई ऐसा निर्णय करेगी कि जो बाकी का एरिया बचा हुआ है,

जारी..श्री गर्ग जी

27/03/2017/1410/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3901--क्रमागत

श्री यादविन्द्र गोमा---क्रमागत

उसको भी क्या नीलाम किया जाएगा? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस तरह हाइड्रो प्रोजैक्ट्स में 'कैट' प्लान के अन्तर्गत कुछ बजट रखा जाता है और जो वहां के प्रभावित क्षेत्र या गांव होते हैं वहां पर डवलपमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको बजट खर्च किया जाता है, तो क्या खनन विभाग भी क्रैशर वालों के ऊपर कोई 'सेस' लगाएगा ताकि संबंधित प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कोई पैसा खर्च कर सके?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने प्रिंसीपल डिसीजन लिया है कि सरकारी जमीन को क्रैशर्ज के लिए या खनन के दूसरे कार्य के लिए नहीं देंगे और वहां पर सिर्फ नीलामी की जाएगी और निजी भूमि पर कोई भी व्यक्ति अपनी मंजूरियां हासिल कर सकता है। इसलिए सरकारी भूमि पर तो हम बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो पिछली बार का बजट भाषण था उसमें यह मंशा जताई गई थी इसलिए उसके मुताबिक सरकारी भूमि पर हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने पूछा है कि नए एल.ओ.आईज. विभाग के पास लोगों ने मांगे हैं, तो जो मंजूरशुदा क्रैशर्ज हैं, वे इनके क्षेत्र में अभी तक सात हैं। कोई पाईप-लाईन्ज में होंगे, जो क्लीयरैन्ज की स्टेज में होंगे, तो मैं इनको उनकी सूचना अलग से दे दूंगा।_इसके अलावा

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि जहां क्रैशर्ज लगते हैं वहां स्थानीय पंचायत पर क्रैशर्ज पर 'सैस' लगा दिया जाए, तो यह नीतिगत मसला है और विभाग में इस पर चर्चा करने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है।

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह नीतिगत फैसला है, तो क्या सरकार इस नीतिगत फैसले के बारे में विचार करेगी? मेरा एक और भी प्रश्न था कि जो रिवर बेड से हटकर छोटी पहाड़ियां हैं, क्या सरकार उन पर भी फैसला करेगी और वहां पर एल.ओ.आइज़. और क्रैशर्ज लगाने की अनुमति देगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा में सरकारी भूमि की प्री-ऑक्शन पहले से ही चल रही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इनके चुनाव क्षेत्र में भी कुछ स्थान हैं जिनको ऑक्शन कर दिया जाए। तो हम यह प्लान मंगवा देंगे। क्योंकि कांगड़ा,

27/03/2017/1410/RG/AS/2

सिरमौर एवं हमीरपुर में सरकारी भूमि पर अब ऑक्शन चल रहा है, वैसे तो पूरे प्रदेश में ही सरकारी भूमि पर ऑक्शन होनी है_और सबके प्लान बन रहे हैं। अगर माननीय सदस्य हमें बताएंगे कि किस क्षेत्र को ये उपयुक्त समझते हैं कि उस क्षेत्र को खनन के लिए दिया जाए, तो हम वह भी ऑक्शन करवा देंगे।

27/03/2017/1410/RG/AS/3

प्रश्न सं. 3902

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार हुई, कितने परिवारों ने इसके लिए अप्लाई किया और कितने परिवारों को इससे लाभ हुआ?

Speaker: Hon'ble Minister, have you got some information?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास है, इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

27/03/2017/1415/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3902 क्रमागत----

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो एस0सी0 सब-प्लान के तहत आप पंचायतों को कुछ सोलर लाइट्स फ्री में देते हैं उनकी संख्या बहुत कम हैं और एक चुनाव क्षेत्र को लगभग 10 सोलर लाइट्स देते हैं। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में हरिजनों की 100 बस्तियां हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि एस0सी0 सब-प्लान में जो पैसा दिया जाता है क्या आप इसको थोड़ा बढ़ाने की कृपा करेंगे? दूसरे, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो नेशनल सोलर मिशन के तहत दिया जाता था, वह बन्द हो गया है। यह वास्तव में बड़ी लोकप्रिय स्कीम है इसलिए क्या आप इसको स्टेट फण्डिंग से देना शुरू करेंगे? तीसरे, जो रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने हैं और केन्द्र सरकार ने इसके लिए 70 प्रतिशत की सब्सिडी रखी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रदेश में कितने प्लांट चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या आपने केन्द्र को इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट्स भेजी हैं या नहीं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसके लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार देती है और बाकी का पैसा जिस आदमी ने यह काम करना है उसी ने खर्च करना है। जो मैंने आपको 54 करोड़ रुपया बताया है इससे हमने बहुत सारी स्कीमों पर काम किया है। अगर मैं इन सबको पढ़कर सुनाने लगूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये 25-30 के लगभग स्कीमें हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी, जो महेश्वर सिंह जी पूछना चाह रहे हैं, -(व्यवधान)-ये यह पूछना चाह रहे हैं कि जो हम सोलर लाइट्स देते हैं।

श्री महेश्वर सिंहः मैंने तो कुछ बोला ही नहीं।

27/03/2017/1415/MS/AS/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अगर मेरा कहा गलत निकले तो आपने कहना क्योंकि मैं तो आपके ह्रदय में बसता हूं। जो हम सोलर लाइट्स दे रहे हैं, उसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त हम बहुत कम सोलर लाइट्स दे रहे हैं। ये यह भी जानना चाह रहे हैं कि विधायक विकास निधि से क्या हम सोलर लाइट्स खरीदकर अपनी पंचायत के लोगों को दे सकते हैं या नहीं? मैं बताना चाहता हूं कि हां, दे सकते हैं।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा और चाहूंगा कि सरकार इस पर एक निर्णय ले कि सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव पहले था परन्तु अभी शायद नहीं है और अभी कुछ पैसा भी इसके लिए है तथा प्राइवेट पार्टी से भी एल0ओ0आई0 विभाग कर रहा है। क्योंकि मेरे कुसुम्पटी चुनाव क्षेत्र में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पूरा दिन धूप आती है और वे बहुत गर्म क्षेत्र हैं। यहां भूमि भी उपलब्ध है जोकि बंजर भूमि है और जहां खेती-बाड़ी भी नहीं हो सकती है। वह वन विभाग की भूमि है इसलिए उसका एफ0सी0ए0 के तहत केस बनाकर यहां पर सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार भेजे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः जहां तक सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की बात है इसको वहां सरकार स्थापित नहीं करेगी। जैसे हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करते हैं वैसे ही हम सोलर पार्क के रूप में उस एरिये को विकसित कर देंगे। वहां पर बाकी जो काम है अगर किसी ने भी वह लगाना है तो प्राइवेट सैक्टर वाला आदमी लगा ले।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक तथ्य जानना चाहूंगा क्या उनके ध्यान में यह बात है कि भारत सरकार ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत की है जिसका नाम "नेशनल सोलर मिशन" है और यह योजना आपके हिम ऊर्जा के पास आ चुकी है जिसके अंतर्गत 90 प्रतिशत सब्सिडी है और कन्ज्यूमर्ज को केवल 10 प्रतिशत पैसा देना है?

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

27.03.2017/1420/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3902:------**जारी**-------

श्री महेश्वर सिंहः-----**जारी**--------

फलस्वरूप यह पैसा लोगों से मांगा जा रहा है, जो साधन-सम्पन्न लोग हैं, उन्हीं को ये लाईटें मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे कि मंत्री जी ने यहां पर विधायक विकास निधि की बात की है, उस योजना के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी से बात करके आप यह प्रावधान करते हैं तो जो उसका सब्सिडी पार्ट 2200/- रूपया है उसको हम विधायक निधि से जमा करेंगे तो फिर गांवों में भी और शहरों में उपयुक्त स्थानों पर सोलर लाइट्स लग सकेगी? क्या आप इसके प्रावधान के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से विधायक विकास निधि योजना के अन्तर्गत बात करेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय सदस्य यह तो जरूर मानते होंगे कि मैं आपके दिल की बात जानता हूं। यह तो मैंने पहले ही कह दिया है। मुख्य मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी लेकिन इस वक्त तो बात नहीं होगी। आप मेरे कमरे में आएं, हम माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जाएंगे और इस बारे में बात कर लेंगे।

27.03.2017/1420/जेके/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 3903

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर यहां पर आया है उसमें विधायक विकास निधि से 2 करोड़ 17 लाख रूपया दिया गया है और खर्च केवल 1 करोड़ 42 लाख रूपया

हुआ है और कुल कार्य योजना 239 है उनमें से 74 ऐसी योजनाएं हैं जिनके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह जो इतना पैसा पड़ा है और जो योजनाएं हैं इनमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो विधायक विकास निधि के अन्तर्गत पहले व दूसरे साल मिला है उनके ऊपर भी काम शुरू नहीं हुआ है। क्या मुख्य मंत्री महोदय आश्वस्त करेंगे कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाएगा? जिन पंचायतों के अन्दर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, क्या वहां पर जो काम करवाने वाले सचिव हैं, बाकी पंचायत के लोग हैं, उनको ऐसी हिदायतें देंगे कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए? जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहां पर विस्तृत सूचना दी है इस सूचना में से 10 प्रतिशत सूचना गलत है। जो काम पूरे हो गए हैं वे लिखे हैं, जो शुरू ही नहीं हुए हैं, उनको लिख दिया गया है कि काम पूरे हो गए हैं। ये तीन-चार काम मैंने यहां पर निकाले हैं इसका ज़वाब मुझे अभी-अभी मिला है। एक काम बाड़ी पंचायत में हैं, गंगोट पंचायत में है , यहां पर काम पूरा हो गया है और आपके उत्तर में लिखा गया है कि काम शुरू होना है।

दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सोलर लाइट्स के बारे में ज़वाब आया है कि अभी तक हिम ऊर्जा के पास सोलर लाइट्स नहीं है। मैंने जिलाधीश महोदय से भी निवेदन किया था। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर लाइट्स अगर हिम ऊर्जा के पास नहीं है तो आपने पूरे हिमाचल प्रदेश के अन्दर बहुत सी कम्पनीज़ के रेट कॉंट्रेक्ट सोलर लाइट्स के लिए किए हैं तो वे बी0डी0ओ0 ऑफिस में आ जाएं वहां पर वे टेण्डर भरें और जिसका टेण्डर निकलता है वह

27.03.2017/1420/जेके/डीसी/3

सोलर लाईट्स लगाएं। हिम ऊर्जा के पास तीन-तीन सालों से पैसे जमा है, लेकिन हिम ऊर्जा के पास सोलर लाईट्स देने के लिए नहीं है, जैसे कि आपके उत्तर में भी दिया गया है। तो कृपया इस बारे में बताएंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने उत्तर दिया है, वह मेरी सूचना के मुताबिक है। जहां तक सोलर लाइइट्स कहां से उपलब्ध होती है वह तो हमारे बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी उत्तर देंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो विकास के कार्य हैं एक तो वे हैं जो सरकारी बजट के मुताबिक है, दूसरे वे हैं जो विधायक विकास निधि के मुताबिक हैं। इन सब की सूचना आपको दे दी गई है। मैंने इसको बड़े गौर से पढ़ा। मुझे खुशी है कि आपका अधिकांश काम या तो पूरा हो गया है या पूरा होने की स्थिति में है और जो शेष कार्य है उनको बड़ी तेजी के साथ किया जाएगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

27.03.2017/1425/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3903 क्रमागत

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जैसे बोला गया कि कुछ काम शुरू नहीं हो रहे हैं और अभी जब राज्यपाल जी का धन्यवाद प्रस्ताव आया था तो उसमें मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि आपने एक नई नोटिफिकेशन कर दी है, उस नोटिफिकेशन में आपने कहा है कि जो विकास का काम जिसमें एम0एल0ए0 या एम0पी0 लैड लगेगा, वह मलकीयत जमीन पर तभी लगेगा अगर मलकीयत जमीन का मालिक उसकी रजिस्ट्री पंचायती राज के नाम कर देता है। कुछ काम तो पिछले दो-तीन महीनों से इसलिए रूक गए हैं। हमने निवेदन किया था कि अगर आप ऐसी नोटिफिकेशन करेंगे तो

कौन अपनी मलकीयत जमीन पंचायती राज के नाम देगा? वे एफिडेविट देते हैं और पहले भी आप एफिडेविट लेते हैं। अगर वह नोटिफिकेशन रद्द हो जाए तो मुझे लगता है कि काम जल्दी हो जायेंगे।

मुख्य मंत्रीः मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। **मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि आपकी कांस्टीचुऐंसी उन विधान सभा क्षेत्रों में से एक है जहां कि अधिकांश काम हो चुके हैं और कुछ काम बाकी हैं उनको भी जल्दी से किया जायेगा। आपने एक अड़चन यानी किसी नोटिफिकेशन का ज़िक्र किया उस पर विचार किया जायेगा।**

प्रश्न समाप्त

27.03.2017/1425/SS-DC/2

प्रश्न संख्याः 3904

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने सूचना सभापटल पर रखी है उसके मुताबिक 663 बीघा लैंड नालागढ़ के नज़दीक आइडेंटीफाई कर दी है और केस कंसर्नड डिप्टी कमिश्नर को भेज दिया गया है। इसमें मेरी एक-दो क्वैरीज़ हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके नज़दीक नालागढ़ में मौजा कौन-कौन से हैं और उनकी कितनी-कितनी जमीन है?

दूसरा, जो डिप्टी कमिश्नर को 28.10.2016 को लिखा, उसमें पांच महीने पूरे हो गए हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह लैंड एक महीने, दो महीने या कितने समय में ट्रांसफर हो जायेगी? क्या यह लैंड इसी सरकार के समय में ट्रांसफर हो जायेगी? ये दो प्रश्न बड़े रैलेवैंट हैं।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्री अनंत कुमार जी जोकि कैमिकल एंड फर्टिलाईजर मंत्री हैं, वे पिछले दिनों बद्दी में एक समारोह में आए थे और उनके समक्ष यह बल्क ड्रग पार्क की मांग रखी गई थी। उनके आगे हमने यह प्रस्ताव रखा और बताया कि बद्दी में बड़े स्तर पर फार्मा काम कर रहा है और एशिया की 35 परसैंट ड्रग्ज़ हम

मैनुफैक्चर कर रहे हैं और अगर बल्क ड्रग पार्क मिल जाए तो हम दूसरी स्टेट्स को कम्पीट कर सकेंगे। तो उन्होंने मौके पर इसकी घोषणा कर दी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर यह कहा कि वे दो ड्रग पार्कस दे रहे हैं उसमें से एक हिमाचल को देना है। उन्होंने इन प्रिंसीपल इस बात की घोषणा की है लेकिन अभी तक हमें उनका फाइनल पत्र नहीं आया है जो उनकी घोषणा के अनुरूप प्रदेश सरकार को स्वीकृति पत्र आना है। हमने in the meantime लैंड आइडेंटीफिकेशन का काम शुरू कर दिया और 663.11 बीघा लैंड नालागढ़ में आइडेंटीफाई की है। इसमें से काफी लैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही थी। हमने उन लोगों से बात की और कहा कि या तो हमें आपका पट्टा रद्द करना पड़ेगा या आप इस लैंड में से मैजोरिटी लैंड सरकार को रिटर्न कर दें। वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अगर यहां पर बल्क ड्रग पार्क आ रहा है तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं।

27.03.2017/1425/SS-DC/3

अब हमने यह प्रॉपोजल डिप्टी कमिश्नर को भेज दी है। लेकिन माननीय सदस्य इसको इस ढंग से प्रैजेंट कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत पुराना मसला था और डिपार्टमैंट कुछ नहीं कर रहा है। --(व्यवधान)--अभी तो माननीय सदस्य केन्द्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने घोषणा की है और उनकी घोषणा के अनुरूप हमें पत्र तो आ जाए, बाकी काम हम सब करवा लेंगे। (व्यवधान)--लेकिन हम केन्द्रीय मंत्री के आभारी हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2017/1430/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3904 जारी...

उद्योग मंत्री जारी----

कि उन्होंने आ कर घोषणा की। उनका स्वीकृति पत्र हमें आ जाए, अन्तिम स्वीकृति हमें आ जाए, बाकी जो लैंड ट्रांसफर होगी, सब हो जाएगा।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा था कि कौन-कौन सी मौजा में कितनी-कितनी जमीन है? मैंने तो स्पैसिफिक पूछा था । नालागढ़ के पास मौजा का बता दीजिए कि कौन-कौन से गांव हैं जो आइडैंटिफाई किए हैं? यह तो कॉंफिडैंशियल नहीं है कि किसी को न बताया जाए इसलिए कृपया गांव बता दीजिए?

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्य, आपने जिस टोन में बात की, मैं तो उसकी बात कर रहा था बाकी तो कृपालपुर और मंझौली क्षेत्र में लैंड हमने आईडैंटिफाई की है लेकिन अभी तक केन्द्र से पत्र तो आने दो।

27.03.2017/1430/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3905

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दिनाकः 15 फरवरी, 2017 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 2,27,845 किसानों की भूमि का बीमा किया गया और भूमि 84,814 हैक्टेयर है। सूचना का जिलावार विवरण अनुबन्ध-"क" पर संलग्न है। क्योंकि कुल कृषक 2,27,845 हैं इसलिए इतनी संख्या होने के कारण इनके नाम नहीं दिए जा सकते।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है और किसानों के हक की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो अभी खरीफ़ की फसल हुई है, क्योंकि दो उत्पाद जौ और गन्दम का ही बीमा करवाया जाता है। क्या मंत्री महोदय के पास जानकारी है कि ये जो दो फसलें हैं,

जिसमें 36 रुपये गेहूं का और 30 रुपये जौ का होता है, उसके अनुसार कितना बीमा प्रदेश में एकत्रित हुआ है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, 15 फरवरी, 2017 तक की फीगर्ज़ मैंने दी है। अभी मेरे पास अलग-अलग सूचना नहीं है कि गेहूं का कितना और जौ का कितना बीमा है?

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः मंत्री जी, प्रति बीघा होता है । हैक्टेयर के मुताबिक तो किसानों के पास जमीन ही नहीं होती।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः प्रति बीघा होता है परन्तु हमने हैक्टेयर के हिसाब से टोटल सूचना दी है। तीन-चार किसानों को मिलाकर हैक्टेयर का लेते हैं। कई किसान 50-50 हैक्टेयर वाले भी हैं। टोटल किसान 2,27,845 है और भूमि 84,814 हैक्टेयर है। अगर आपको अलग-अलग सूचना चाहिए तो वह भी हम मंगवा लेते हैं।

27.03.2017/1430/केएस/एजी/3

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो सूचना हमें दी गई है उसमें तो लिखा है, कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" लेकिन माननीय मंत्री जी के पास अगर आंकड़ों की सूचना भी है तो कृपया जिला हमीरपुर में कितने किसानों का बीमा हुआ, वह बता दें?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें किसान का नहीं लेकिन टोटल जोड़ जमीन का दिया है कि कितनी है। वह 14588.07 हैक्टेयर है जिसका बीमा हुआ है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.3.2017/1435/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 3905---------- क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री---------- जारी

(---व्यवधान---) जिलावार तो मैं आपको वैसे ही दे देता हूं। (---व्यवधान---) यह आपको उपलब्ध करवाये गये उत्तर में है। (---व्यवधान---) जिला बिलासपुर में 9422.68 हैक्टेयर, चम्बा में 2759.65 हैक्टेयर, हमीरपुर में 14588.07 हैक्टेयर, कांगड़ा में 26759.19 हैक्टेयर, किन्नौर में 24 हैक्टेयर, कुल्लू में 83.10 हैक्टेयर, मण्डी में 18607.51 हैक्टेयर, शिमला में 187.67 हैक्टेयर, सिरमौर में 2842.91 हैक्टेयर, सोलन में 3410.39 हैक्टेयर और ऊना में 6075.92 हैक्टेयर है। मेरे पास जो टोटल है (---व्यवधान---) यह हो सकता है कि दो-तीन साल का इकट्ठा हो। (---व्यवधान---) यह तो इसी साल का है बाकी वर्ष 2016-17 का भी है। (---व्यवधान---) आपके पास अगर नहीं है तो यह सूचना आपको दे देंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान गन्दम का 35 रुपये प्रति बीघा और जौ का 30 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दे रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय इस सदन को अवगत करवायेंगे कि अगर किसान की फसल ओलावृष्टि, बरसात या गर्मी की वजह से पूरी तरह नष्ट हो जाती है तो उसकी एवज में आप प्रत्येक किसान को प्रति बीघा के हिसाब से कितना मुआवजा देंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि, बरसात या दूसरे किसी भी कारण से गेहूं और जौ का सौ प्रतिशत लोस कभी नहीं होता।

समाप्त

27.3.2017/1435/av/ag/2

<u>प्रश्न संख्या : 3906</u>

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके आधार पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में शैड्यूल कास्ट कम्पोनैंट प्लान के अंतर्गत 16 सड़कों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इन 16 सड़कों के लिए वर्ष 2016-17 में 105.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान था जिसके विरुद्ध केवल 32.86 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 16 सड़कों के लिए जो बजट में 105.50 लाख रुपये का प्रावधान था तो उसके अगेंस्ट केवल 32.86 लाख रुपये ही खर्च क्यों हुए? दूसरा, मेरा इस प्रश्न को पूछने का मूल अभिप्राय इस बात से है कि शैड्यूल कास्ट कम्पोनैंट प्लान के अंतर्गत किसी सड़क को बजट में डालने का मापदण्ड क्या है?

मुख्य मंत्री :अं अगली टर्न में ----- हिन्दी श्री वर्मा द्वारा जारी

27/03/2017/1440/टी0सी0वी0-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या 3906..... क्रमागत

Chief Minister: Speaker, Sir, Assisting Roads under Seraj Constituency have been included under SCSP Scheme during the financial year 2016-2017. During 2016-2017, there is a Budget provision of Rs. 105.50 Lakhs under this Head. Till date Rs. 32.86 Lakhs have been booked as expenditure during 2016-2017 under SCSP in his Constituency.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, ये तो लिखित रूप में जवाब आया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह पढ़ा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि शड्यूल कॉस्ट कंपोनेंट के अंतर्गत जो प्रावधान करते हैं, उसको डालने का क्राइटेरिया क्या है?

दूसरा, पिछले साल आपने एक करोड़ पांच लाख रूपये का प्रावधान किया था, लेकिन खर्च मात्र 32 लाख रूपये हुआ है। ये बहुत कम राशि खर्च हुई है। मैं इसकी वज़ह जानना चाहता हूं। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो बजट प्रावधान शड्यूल कॉस्ट कंपोनेंट के अन्तर्गत होता है, वह मात्र एक वर्ष के लिए होता है या एक बार जो सड़क शड्यूल कॉस्ट कंपोनेंट के अन्तर्गत आ जाती है, क्या उसके बाद हमेशा उसके निर्माण/रिपेयर का काम इसी के अन्तर्गत जारी रहेगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सड़क इस स्कीम के अंतर्गत दी जाती है, उसके लिए पर्टीकुलर फाईनेंशियल ईयर में कुछ रकम अलॉटिड होती है। अगर वह सड़क पूरी न हो, तो अगले फाईनेंशियल ईयर में जो स्कीम अधूरी पड़ी है पहले उसका काम पूरा करने के लिए पैसा खर्च कर दिया जाता है। बाकी इसके मापदण्ड का तो सबको पता है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारी सड़कें हैं, प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति की बहुत घनी-घनी आबादी वाले गांवों इसमें नहीं आ पाये। छोटे-छोटे गांव इसमें डाल दिए गये, जिनकी आबादी कम हैं। मेरा उसमें विरोध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता आबादी के आधार पर दी जानी चाहिए थी। इसलिए मुझे इसमें कंफियुज़न हो रहा है।

27/03/2017/1440/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

मुख्य मंत्रीः मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके जो फण्डज़ होते है, Budget is allocated by the Welfare Department and Public Works Department only implements it.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके लिए पैसा वैलफेयर डिपार्टमेंट से आता है और लोक निर्माण विभाग इसको एग्जिक्यूट करता है। मेरे

विधान सभा क्षेत्र की 16 सड़कें इसमें डाली गई हैं। इन 16 सड़कों को इसमें डालने का मापदण्ड क्या है? इससे अनुसूचित जाति के जो बड़े-बड़े गांव हैं, वह छूट गए हैं।

मुख्य मंत्रीः मापदण्ड ये हैं कि जिस गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 परसेंट या इससे अधिक होती है, उसको अलोट किया जाता है, लेकिन अलोट भी वैलफेयर डिपार्टमेंट करता है। ---(व्यवधान)---

Speaker: Hon'ble Member, how many supplementary would you like? You have already availed above four supplementary. पूरा जवाब दे दिया है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक बात इसमें कही गई है कि इसका मापदण्ड पॉपूलेशन बेस्ड होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव इस पॉपूलेशन के अन्तर्गत जो हायर साइड में हैं, वे छूटे हुए है।

श्रीमती एन.एस. ....द्वारा जारी।

27/03/2017/1445/ एन0एस0/ए0एस0 **/1**

प्रश्न संख्याः 3906 -- क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर ----- जारी

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां पर जो अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियां हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने का प्रयास करेंगे? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो राशि दी गई थी, उसमें से बहुत कम पैसा खर्च किया गया है। 1 करोड़, 5 लाख रूपये का बजट प्रावधान था लेकिन खर्च मात्र 32 लाख रूपये किये गये हैं। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। हमारी प्राथमिकता के अनुसार अनुसूचित जाति के वर्ग को

सड़क की सुविधा होनी चाहिए लेकिन यह सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। बजट प्रावधान होने के बावजूद भी विभाग उस राशि को खर्च नहीं कर पा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो एलोकेशन होती है वह वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। उसमें ऐसा है कि जहां पर 40 प्रतिशत पॉपुलेशन हो और कम-से-कम 90 परिवार वहां पर अनुसूचित जाति के होने चाहिए। That is given priority. The population should be 40% or there should be 90 families of Scheduled Caste beneficiaries, in a particular village, they are given priority. On these basis the money allocated by the Welfare Department.

27/03/2017/1445/ एन0एस0/ए0एस0 /2

प्रश्न संख्याः -3907

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1 सितम्बर, 2011 को जो तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के प्रशासनिक ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है उसके निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है और यह कब तक पूरा हो जाएगा, क्या इसका काम शुरू हो गया है? पिछले सत्र में भी यह बताया गया था कि तकनीकी विश्वविद्यालय में कैम्पस भी बनाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस कैम्पस को बनाने के लिए कितना समय लेगी और उसके लिए क्या योजना बनाई गई है तथा उसके लिए बजट का क्या प्रावधान है?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने 8.11 करोड़ रूपये की ब्याज मुक्त राशि स्वीकृत की है। इसमें से 5.61 करोड़ रूपये की राशि तकनीकी विश्वविद्यालय को प्रदान कर दी गई है। उसमें से विश्वविद्यालय ने 3.74 करोड़ की राशि सरकार को वापिस कर दी है। पहले यह राशि लोक निर्माण विभाग को दी गई थी। यह

पैसा स्टेट की एजैंसी को दिया गया था। उनके यूजर चार्जिज 9 प्रतिशत थे। उनके यूजर चार्जिज ज्यादा थे इसलिए बाद में इसको बदल दिया गया और यह कार्य सी0पी0डब्लयू0डी0 को दे दिया गया क्योंकि उनके यूजर चार्जिज लगभग 5 प्रतिशत के आसपास हैं। इस पर कुल 40 करोड़ रूपये की राशि खर्च होनी है। इसके दोनों ब्लॉक्स का काम शुरू हो गया है। पहले इस विश्वविद्यालय को जगह की प्रॉब्लम की वजह से पुराने एस0डी0एम0 ऑफिस में खोला गया था इसलिए जो ग्रांट यू0जी0सी0 से आनी थी वह अभी तक नहीं मिल पाई है। अब जैसे ही ये ब्लॉक्स बनेंगे, आपकी मन्शा के मुताबिक इसको एक्सिपडाइट करवाया जाएगा।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

27/3/2017/1450/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3907... जारी

श्री नरेन्द्र ठाकुरः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसके फाउंडेशन स्टोन को रखे हुए लगभग 6 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। इन्होंने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें यह कहा गया है कि सरकार ने इसके ऊपर कोई पैसा खर्च करने का प्रावधान नहीं किया है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इसको बनाने के लिए गंभीर है? सरकार ने 6 वर्षों में इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को बनाने के लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं करवाया है। इसके निर्माण में कुल 40 करोड़ रुपये का खर्चा आना है। वहां पर जो काम शुरू हुआ है, वह काम टैक्निकल यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सिज़ से करवा रही है। सरकार की तरफ से कोई भी इनिशीएटिव नहीं लिया गया है। क्या सरकार इसको बनाने में रुचि रखती है, इसका स्पैसिफिक उत्तर दिया जाए?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 8.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। उसमें से उन्होंने 5.61

करोड़ रुपये की ही राशि ली है और 3.74 करोड़ रुपये की राशि वापिस भी कर दी गई है। उनके पास भवन/एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या एकेडेमिक ब्लॉक बनाने के लिए बहुत राशि है। उनके अपने रिसोर्सिज़ में 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। पैसा वहां दिया जाता है, जहां पैसा न हो। उनके पास पैसा उपलब्ध है। हम इसको एक्सिपडाइट करवाएंगे। वहां पर काम शुरू हो गया है। पहले इस काम को पी.डब्ल्यू.डी. को करना था परन्तु अब यह तय हो गया है कि इस काम को सी.पी.डब्ल्यू.डी. करेगा। उनके यूज़र चार्ज़िज़ कम हैं और यूनिवर्सिटी ने पाया कि हमें यह काम सी.पी.डब्ल्यू.डी. से करवाने में थोड़ा चीपर रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि जो प्रदेश सरकार ने पैसा दिया था, उस पैसे को भी वे वापिस कर रहे हैं।

27/3/2017/1450/RKS/DC/2

प्रश्न संख्याः 3908

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, पहले तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने चम्बा शहर में स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये और शूटिंग रेंज के लिए 5 लाख रुपये उपलब्ध करवाए हैं। मगर अध्यक्ष महोदय, दो साल बीत चुके हैं परन्तु लैंड के ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। जो पुलिस ग्राउंड है, उसके साथ पुलिस की जो लैंड है, क्योंकि शूटिंग रेंज पुलिस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वहां बनाने का फैसला था और वहीं पर स्पोर्ट्स काम्पलैक्स भी बनाने का फैसला था। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को एक्सिपडाइट करवाएंगे कि जो लैंड पुलिस डिपार्टमैंट के पास है, स्पौर्ट्स कॉम्पलैक्स इन्हीं के एरिया में बनाकर, वहीं पर शूटिंग रेंज भी बनाया जाए ताकि जो चम्बा के लोगों को पैसा दिया गया है वह उनके काम आ सके।

Chief Minister: The Hon'ble Member has given a suggestion for action and we will certainly consider it.

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सुझाव नहीं है। यह लैंड, डिपार्टमैंट ने खुद आइडंटिफाई की है। पुलिस डिपार्टमैंट के साथ उनका एम.ओ.यू. नहीं हो पा रहा है। पुलिस डिपार्टमैंट यह कहता है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनेगा वह उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा और स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट यह कहता है कि हम इसे बना देंगे परन्तु यह हमारे ही सुपुर्द रहना चाहिए। इस वजह से यह नहीं हो पा रहा है। वहां पर भूमि उपलब्ध है। अगर मेरा कोई सुझाव है तो वह यह है कि डिप्टी कमिश्नर और एस.पी. की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और यह सबके लिए काम आएगा। पुलिस वाले भी इसे यूज़ करेंगे और स्थानीय लोग भी इसे यूज़ करेंगे परन्तु यह बन तो जाए।

Chief Minister: We will look into this matter.

27/3/2017/1450/RKS/DC/3

प्रश्न संख्या: 3909

श्री बलदेव सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने 'क' भाग के जवाब में कहा है कि 35 गांव में अभी वोल्टेज की समस्या है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी वोल्टेज़ की समस्या है। 'ख' भाग के जवाब में आपने लिखा है कि हम 15 गांव के लिए 25 के.वी. के तीन नए ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी गांव बचे हैं उनमें कब नए टांसफॉर्मर लगेंगे और उनकी लॉ वोल्टेज की समस्या कब तक पूरी होगी जबकि

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.03.2017/1455/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 3909 ...क्रमागत

श्री बलदेव सिंह तोमर ...जारी

आपने एक अतारांकित प्रश्न संख्या : 1677 के उत्तर में कहा है कि पिछले 4 सालों में शिलाई विधान सभा क्षेत्र में 52 नए ट्रांसफार्मज़ लगाए गए हैं। उसके बावजूद भी वहां बहुत सारे गांव लो-बोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या कब तक हल होगी?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि यहां पर कुछ गांवों के ही नाम दिए गए हैं; बाकी भी बहुत से गांव हैं जहां पर लो-बोल्टेज की समस्या है। आप मुझे उन गांवों की सूची दे दें, उनकी लो-बोल्टेज की समस्या हल की जाएगी।

27.03.2017/1455/SLS-DC-2

प्रश्न संख्या : 3910

डॉ० राजीव सैजल : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके मुताबिक बताया गया है कि इस सड़क को पक्का करने का काम 15.05.2012 को शुरू हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो यह सड़क पक्की की गई है, जो ढढियारघाट से लुग्गुपुल तक यह सड़क पक्की हुई थी, उसका अधिकांश भाग उखड़ चुका है। वर्तमान में इसकी हालत कच्ची सड़क से भी बदतर है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सड़क में जो घटिया काम हुआ है, क्या आप उसकी जांच करवाएंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में इस सड़क की पूरी स्थिति के बारे में ज़िक्र किया है। मैं इस सूचना को माननीय सदन में पढ़ना चाहूंगा। भोजनगर मल्ला सड़क का कार्य दिनांक 12.12.2008 को प्रारंभ हुआ तथा इसको पक्का करने का कार्य दिनांक

15.05.2012 को शुरू हुआ। इस सड़क का कि.मी.13/0 से 23/600 का भाग पक्का हो चुका है। शेष 3.85 कि.मी. भाग को ठेकेदार ने पक्का नहीं किया व कार्य अधूरा छोड़कर arbitration में चला गया। विभाग ने ठेकेदार पर 20.64 लाख रुपये के liquidated damages लगाए हैं। इस मामले को अब समझौता वार्ता से सुलझाने के प्रयास जारी हैं। शेष कार्य जल्दी शुरू करवाने की कोशिश जारी है। यह मैं अपने लिखित उत्तर में भी कहा चुका हूं। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, इसका भी यही उत्तर है।

डॉ0 राजीव सैजल : अध्यक्ष महोदय, यह अधिकांश सड़क उखड़ चुकी है। जो इस सड़क की वर्तमान स्थिति है, क्या आप इसकी जांच करवाएंगे?

मुख्य मंत्री : <u>आप जो कह रहे हैं उसकी हम जांच करवा देंगे और आप जो कह रहे हैं, उसके आधार पर ही जांच की जाएगी।</u>

प्रश्न काल समाप्त

अगली मद..श्री गर्ग जी

27/03/2017/1500/RG/AG/1

<u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है :-

सोमवार	दि. 27 मार्च, 2017	1. शासकीय/विधायी कार्य 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
मंगलवार	दि. 28 मार्च, 2017	1. शासकीय/विधायी कार्य, 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
बुधवार	दि. 29 मार्च, 2017	1. शासकीय/विधायी कार्य, 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
वीरवार	दि. 30 मार्च, 2017	1. शासकीय/विधायी कार्य, 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 i. मांगों पर चर्चा एवं मतदान। ii. विनियोग विधेयक, पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।
शुक्रवार	दि. 31 मार्च, 2017	1. शासकीय/विधायी कार्य,

27/03/2017/1500/RG/AG/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे</u>

अध्यक्ष : अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 तथा वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;

ii. नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16; और

iii. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0एफ0(1)-3/2013-II दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15. 03.2017 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16;

27/03/2017/1500/RG/AG/3

(iii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रीलिंग डेमॅन्स्ट्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-1/2012 दिनांक 3.6.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19. 07.2016 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, माली/बेलदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-3/2016 दिनांक 24.01.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15. 02.2017 को प्रकाशित; और

(vi) खान और खनिज(विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 15(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-बी-एफ-(6) - 31/2016-Vol-I दिनांक 22.08.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.08.2016 को प्रकाशित ।

27/03/2017/1500/RG/AG/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **171वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;
ii. समिति का **172वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और
iii. समिति का **173वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम जी, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2016-17) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **35वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:31 **जनजातीय विकास विभाग** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता।

27/03/2017/1500/RG/AG/5

अध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः6 के अन्तर्गत **आबकारी एवं कराधान विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

ii. समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः7 के अन्तर्गत **गृह विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी, सभापति, मानव विकास समिति **(वर्ष 2016-17)** के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **24वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः24 के अन्तर्गत **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **25वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः30 के अन्तर्गत **खेल एवं युवा सेवायें विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

27/03/2017/1500/RG/AG/6

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज जी, सभापति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति का **21वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः13 के अन्तर्गत **सिंचाई एवं जन**

स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी जी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2016-17) समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

Smt. Asha Kumari : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy of the Reports of the Rural Planning Committee :

i. समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
ii. समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः16 के अन्तर्गत **वन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

एम.एस. द्वारा अगली मद शुरू

27/03/2017/1505/MS/AG/1

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, की ओर से क्या सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझूं?

मुख्य मंत्रीः जी, प्रस्तुत हुआ समझा जाए।

अध्यक्षः सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी गईं जोकि इस प्रकार से हैंः-

Demand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly ₹
1	2		3
1	Vidhan Sabha	(Revenue) (Capital)	30,84,01,000 2,65,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	15,30,73,000
3	Administration of Justice	(Revenue) (Capital)	1,51,37,68,000 14,58,00,000
4	General Administration	(Revenue) (Capital)	1,72,98,34,000 1,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue) (Capital)	6,16,48,87,000 15,00,00,000
6	Excise and Taxation	(Revenue) (Capital)	67,18,43,000 4,00,00,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue) (Capital)	11,11,98,66,000 45,35,00,000
8	Education	(Revenue) (Capital)	53,91,89,95,000 61,29,02,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue) (Capital)	16,01,65,30,000 67,28,00,000
10	Public Works- Roads, Bridges and Buildings	(Revenue) (Capital)	28,39,11,81,000 10,62,12,10,000
11	Agriculture	(Revenue) (Capital)	3,49,51,41,000 61,95,35,000
12	Horticulture	(Revenue) (Capital)	3,03,13,49,000 14,60,54,000
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue) (Capital)	22,60,77,70,000 4,89,66,16,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue) (Capital)	3,46,17,02,000 7,27,54,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	73,34,43,000 2,44,82,00,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue) (Capital)	4,52,32,05,000 9,26,00,000

17	Election	(Revenue)	39,52,40,000
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Revenue) (Capital)	1,00,32,31,000 62,40,00,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue) (Capital)	7,29,59,61,000 9,75,00,000
20	Rural Development	(Revenue) (Capital)	12,93,33,77,000 2,39,00,000
21	Co-operation	(Revenue)	29,62,81,000
22	Food and Civil Supplies	(Revenue) (Capital)	2,39,70,03,000 1,97,00,000
23	Power Development	(Revenue) (Capital)	4,99,14,93,000 4,10,10,01,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	26,28,74,000
25	Road and Water Transport	(Revenue) (Capital)	2,28,52,52,000 44,89,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue) (Capital)	71,62,08,000 4,50,00,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue) (Capital)	3,96,23,85,000 70,87,01,000
28	Urban Development, Town and Country Planning and Housing	(Revenue) (Capital)	3,41,26,77,000 21,06,00,000
29	Finance	(Revenue) (Capital)	50,33,64,43,000 12,77,50,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue) (Capital)	80,46,58,000 47,53,53,000
31	Tribal Development	(Revenue) (Capital)	11,45,98,41,000 2,93,79,40,000
32	Scheduled Castes Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	12,64,17,05,000 8,96,45,20,000
	Total	**(Revenue)**	**2,73,03,56,17,000**
		(Capital)	**39,78,33,37,000**
		Grand Total	**3,12,81,89,54,000**

27/03/2017/1505/MS/AG/2

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्राथमिकताओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप मैं इनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा। इससे पूर्व कि अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा अनुदान मांगों पर विचार हो सके।

<u>मांग संख्या-7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन</u>

अब सर्वप्रथम मैं मांग संख्या-7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन को चर्चा एवं मतदान हेतु सभा में प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अंतर्गत राजस्व व पूंजी के निमित मु011,11,98,66,000/-रुपये(राजस्व) एवं मु045,35,00,000/-रुपये (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर माननीय सदस्यों सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, डॉ0 राजीव बिन्दल, रिखी राम कौंडल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर तथा वीरेन्द्र कंवर की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या आप इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं इन्हें प्रस्तुत हुआ समझूं?

सदस्यगणः अध्यक्ष जी, आप इन्हें प्रस्तुत हुआ समझें।

अध्यक्षः माननीय सदस्यों की ओर से प्राप्त हुए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जोकि इस प्रकार हैंः-

27/03/2017/1505/MS/AG/3

मांग संख्याः 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्याः

नीति का अननुमोदन 7

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

च्पुलिस और सम्बद्ध संगठनछ

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
डॉ0 राजीव बिन्दल,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान अग्नि से संरक्षण तथा नियन्त्रण नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की गृह रक्षकों की वर्तमान नीति का अननुमोदन।

27/03/2017/1505/MS/AG/4

अध्यक्षः मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं।

अब माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी मांग संख्या-7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन पर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मांग संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन, पर हम विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के आज प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बन गया है यानी सरकार नाम की कोई चीज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम जब ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर जो कानून की व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से चरमरा गई है। एक ऐसी स्थिति कि जिन परियोजनाओं की शिलान्यास पट्टिकाएं जो शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में हैं, विपक्ष या पूर्व सरकार द्वारा जब वे पट्टिकाएं लगी थीं यानी जब वे काम शुरू हुए थे और सम्पूर्ण हुए, उन पट्टिकाओं को अगर पूरे प्रदेश के अंदर गिना जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 से 80 प्रतिशत पट्टिकाएं तोड़ दी गई हैं। इस सदन के बीच में भी हमने बार-बार कहा है कि

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

27.03.2017/1510/जेके/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंहः----**जारी**---------

उन शरारती तत्वों के खिलाफ प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की सरकार कदम उठाए लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरे, प्रदेश के अन्दर अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण

किया जा रहा है। उसमें बड़े पैमाने पर स्थानांतरण माफिया सभी विभागों में, विशेषकर मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में बहुत बुरी तरह से सक्रिय हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऑफिस से डी0ओ0 नोट तक चुराए गए हैं। एक-एक आदमी 400-500 स्थानांतरण प्रदेश के अन्दर करवा रहा है। अखबारों व विभिन्न समाचार पत्रों में बार-बार आया। हमने इस बारे में विधान सभा में भी चर्चा की और विधान सभा में चर्चा करने के उपरान्त एक एन0एस0यू0आई0 नौज़वान उसमें संलिप्त पाया गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि स्थानांतरण माफिया पूरे प्रदेश में हावी है। उसके खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वह आज तक नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर तो माफियों का राज है। शराब माफिया है। शराब की वर्ष 2015-16 में निलामी हुई, वर्ष 2016-17 में निलामी हुई। आज भी मेरा प्रश्न लगा हुआ था उसमें जिस प्रकार से वर्ष 2016-17 की निलामी हुई है उसमें गुड़गांव का शराब माफिया यहां पर लाया गया। हमारे यहां पर एल-1 और एल-बी थे जो शराब के थोक विक्रेता थे उनकी बजाय बाहर का गुड़गांव का ठेकेदार यहां पर ला करके यहां हिमाचल प्रदेश बेवरिज़ कॉर्पोरेशन बनाई गई। उसने केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में तीन महीने तक शराब दी। उसके बाद फिर एक L-1 A उनके ऊपर बिठा दिया गया। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर शराब माफिया का राज खत्म होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पड़ौसी राज्य में ड्रग माफिया सक्रिय था उसी प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश में भी वहीं स्थिति पैदा हो चुकी है। अध्यक्ष जी, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजिज़ हैं, जितने भी दूसरे संस्थान हैं उन संस्थानों के इर्द-

27.03.2017/1510/जेके/एएस/2

गिर्द छोटे-छोटे खोखों में या दुकानों में ड्रग माफिया बहुत बुरी तरह से सक्रिय है। पुलिस उस ड्रग माफिया को पकड़ने में पूर्ण रूप से नाकामयाब रह रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी,

जहां खनन माफिया की बात आती है तो खनन माफिया भी पूरे प्रदेश के अन्दर हावी है। बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस को जब सूचना दी जाती है कि फलां जगह खनन माफिया की जे0सी0बी0 खनन कर रही है। पुलिस कहती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन जब उसी पुलिस को खनन माफिया टेलिफोन करता है कि वहां पर खच्चरों के माध्यम से रेत-बजरी उठाया जा रहा है, ट्रैक्टर रेत-बजरी उठा करके ले जा रहे हैं तो पुलिस वहां पर तुरन्त पहुंचती है। यहां पर बड़े-बड़े खनन माफिया है उनका पूरा वर्चस्व पुलिस विभाग के ऊपर बना हुआ है जो कि एक चिन्ता का विषय है। इस प्रदेश के अन्दर जो हिमाचल प्रदेश में हाईडल प्रोजैक्ट्स लगने चाहिए थे उनको लगाने के लिए जो कम्पनीज़ पहले यहां पर आई थी जिनको बहुत प्रोजैक्ट्स अलॉट किए गए थे, उसमें हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि जो अलॉटिड प्रोजैक्ट्स थे उन पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि एक हाईडल प्रोजैक्ट माफिया भी हिमाचल प्रदेश के अन्दर बहुत बुरी तरह से सक्रिय हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आज हिमाचल प्रदेश से लगभग 1500-2000 के बीच लोग लापता हुए हैं। उन लापता लोगों की पूरी सूचना, उनका पता करने के लिए पुलिस को चाहिए था कि वे उनका पता करते लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

27.03.2017/1515/SS-AS/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

आज एक ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हो रही है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी अलग-अलग जगह पर पुलिस चौकियों/पुलिस थानों की घोषणा कर रहे हैं लेकिन इनको खोलने

से क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर सुधर जायेगा? जिस अनुपात में हमारी आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में अगर पुलिस की भर्ती नहीं की जायेगी तो निश्चित तौर पर उस लॉ एंड ऑर्डर का मैंटेन करना पुलिस के बस का रोग नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और प्रदेश की सरकार को इस बारे में आगाह करना चाहता हूं। पुलिस में बहुत से जवान शहीद हुए हैं जोकि हमसे सदा-सदा के लिए दूर हो गए हैं लेकिन जिस प्रकार से उनके आश्रितों को नौकरियां मिलनी चाहिए थीं, वह नहीं मिलीं। आज सैंकड़ों पद पुलिस विभाग के अंदर खाली पड़े हुए हैं उसके बारे में भी हम माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, होमगार्ड के लोग जो पूरे प्रदेश के अंदर विकट परिस्थितियों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन प्रदेश सरकार अभी तक नहीं कर रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, मैं उसकी कॉपी आपको दूंगा, उसकी अनुपालना प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि होमगार्ड के अंदर हमारे प्रदेश के जो भाई-बहन हैं जोकि यहां पर होम गार्ड के रूप में पुलिस के बराबर काम करते हैं -- (व्यवधान)--

मुख्य मंत्रीः जो सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड की सैलरी फिक्स की है we are paying that. इसलिए इसमें कोई एतराज की बात नहीं है whatever has been fixed by the court's order, Himachal Pradesh Government is agreed and as on today they are being paid salary as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

27.03.2017/1515/SS-AS/2

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी जी के पास गृह विभाग है तो इन्होंने ही उत्तर देना है। जब आप अपना उत्तर देंगे तो जो-जो भी आपके पास सूचना है

उन सभी सूचनाओं से आप इस हाउस को अवगत करवाएं। जो आप एक बात कह रहे हैं। ---(व्यवधान)--- आप क्या लगे हुए हैं?

Speaker: Please, restrain from direct reply.

श्री महेन्द्र सिंहः आप बैठ कर बात कर रहे हैं, आप क्या लगे हुए हैं? झूठ बोलना, आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? मुझे स्पीकर चेयर ने एलाऊ किया हुआ है। आप मिनिस्टर हैं। As a Minister क्या आपको इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए?

Speaker: Please, don't argue directly.

श्री महेन्द्र सिंहः लाइटली का प्रश्न पैदा नहीं होता। क्या यह लॉ एंड ऑर्डर है? इस प्रकार का अनुशासन आप विधान सभा के अंदर करना चाहते हैं। मंत्री बैठे-बैठे ऐसे कमैंट करते हैं। मंत्री जी, हम आपका आदर करते हैं और आदर को निरादर में मत लो। आदर को आदर समझकर रहो।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि एक ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश के बीच में पैदा हुई है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप डायरैक्ट किसी को अड्रैस न करें।

श्री महेन्द्र सिंहः मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मैंने नियम-62 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव दिया हुआ है लेकिन अभी तक वह लगा नहीं है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर गुंडे तत्वों ने पनवार गांव में जाकर रात को एक बजे किसी का दरवाजा तोड़ा और वहां चोरी की। जब मालिक बाहर निकला तो उसको इस प्रकार से पत्थर मारा कि वह बेहोश हो गया और उसको बेहोशी की हालत में रातोंरात पी0जी0आई0 पहुंचाया गया। आज उसकी बहुत बुरी हालत है। मेरे ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर

शिवद्वाला नामक जगह है। उसमें एक बाबा जी रहते हैं और गऊंए पालते हैं। उनके पास 15 से 20 गऊंए हैं। गौशाला उन्होंने चलाई हुई है। गौमाता की सेवा करते हैं। रात को एक बजे के लगभग कुछ बदमाश लोग आए, उन्होंने अपने मुंह पर काला बुरका डाला हुआ था और रात को साधू को मार-मार बेहोश करके चले गए। उसके पास जितना भी पैसा था उसको लेकर चले गए। उसी प्रकार से तीसरी घटना मेरे ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर हुई। टोरीनाला में एक बाबा जी रहते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2017/1520/केएस/डीसी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी-----

उनके साथ भी रात को आ करके बुरी तरह से मारपीट की और उसके बाद उनका सारा पैसा ले कर चले गए। मुझे लगता है कि आज तक भी पुलिस उन गुंडों को नहीं पकड़ पाई है। क्या इस प्रकार का लॉ एण्ड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश के अंदर है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही निन्दनीय है, दयनीय है। सरकार प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर बनाने में पूर्ण रूप से फेल हुई है । मैं ज्यादा न कहता हुआ आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, लेकिन मैं बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें इतना अंडर ऐस्टिमेट भी न करें कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जितना आप जानते हैं उससे थोड़ा सा कम हम भी जानते हैं कि किस प्रकार से इस माननीय सदन का संचालन किया जाता है। जब आप बोल रहे होते हैं तो हम बीच में कभी नहीं टोकते लेकिन आप मुझे ऐसा कहने वाले कौन होते हैं कि आपने झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है? कौन कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पठानिया जी, मैं जो भी तथ्य इस माननीय सदन में रखता हूं,

Speaker: Please don't argue. ---(interruption)--- Please wind up.

श्री महेन्द्र सिंह : उनको हिमाचल प्रदेश में कोई भी चैलेंज कर लें, यहां पर ब्यूरोक्रेसी बैठी है। हम जो यहां पर कहते हैं वह सोच समझ कर कहते हैं, एक जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप बीच में इस प्रकार की व्यंग्यबाज़ी न करें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

Speaker: For your information, any Hon'ble Minister from the Government side can intervene and speak anything. He can reply on behalf of the Government. ---(interruption)---. The Minister can reply on behalf of the Government.

27.03.2017/1520/केएस/डीसी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने यहां पर वक्तव्य दिया है, वह महज़ कुछ कहना था तो कह दिया जिसमें कोई तथ्य नहीं है, निराधार है। इन्होंने कहा है कि क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस नाकाम है। क्राइम जब होता है तो उसको रोकने के लिए और उसकी तफ़तीश करने के लिए, गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए पुलिस होती है। पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्राइम पहले से कम हुआ है और जो मुकद्दमें दर्ज हुए हैं, उनकी प्रॉपर इन्वैस्टिगेशन हुई है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को अदालतों के द्वारा दंडित किया गया है। इन्होंने निकोटिन माफिया, शराब माफिया की बात की। इनको आजकल चारों तरफ माफिया नज़र आ रहा है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इस साल ऑक्शन के बदले में हमने नया सिस्टम चलाया है, एक कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में कायम की है बेवरिज़ कॉर्पोरेशन के नाम से और यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। पहले क्या होता था कि पांच-दस घराने होते थे जो मिलकर अपनी बोली देते थे और हम उसी में उलझे रहते थे । जब हमने यह बेवरिज़ कॉर्पोरेशन कायम की तो उन लोगों ने उसका बहिष्कार किया और इसको नाकामयाब करने की पूरी-पूरी कोशिश की मगर उसके बावजूद यह कॉर्पोरेशन चली और पिछले वर्ष के अंदर ऑक्शन के अलावा साढ़े-तीन, चार सौ करोड़ नैट प्रॉफिट हिमाचल सरकार को हुआ है। मैंने अखबार में पढ़ा था जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री श्री धूमल जी

को उद्धृत किया गया है कि जो यह कॉर्पोरेशन है उसको जो सप्लाई होती है, वह वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। मेरा रिश्तेदार, मेरा जानने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। In fact the supplies for the first time to the Beverage Corporation is done directly by the producers. There is no middle man in between.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

27.3.2017/1525/av/dc/1

मुख्य मंत्री ---------- **जारी**

और उसके बावजूद उन्होंने फिर भी कहीं गोदाम नहीं दिए। उनके पास पुराने गोदाम थे उन्होंने बैवरेज कार्पोरेशन को गोदाम नहीं दिए और उसको फेल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई मगर कामयाब नहीं हुए। लेकिन हम भविष्य में और भी कामयाब होंगे। हालांकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए हैं कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इससे काफी फर्क पड़ेगा मगर इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि यह बैवरेज कार्पोरेशन पहले से बेहतर काम करेगी। यह स्टेट गवर्नमैंट का एक असैट है, यह कार्पोरेशन स्टेट गवर्नमैंट की है। इस कार्पोरेशन को जो लीकर सप्लाई होती है, it is done directly by the manufacturer. There is nobody in between. मैं आपको यह कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य (श्री महेन्द्र सिंह) ने होम गार्ड के बारे में जिक्र किया जिसका मैंने पहले भी उत्तर दिया है। (---व्यवधान---)

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी अगर इस तरह से एक-एक मैम्बर की बात का जवाब देंगे तो एक ही डिमाण्ड समाप्त नहीं होगी।

मुख्य मंत्री : मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि आप (श्री सुरेश भारद्वाज) इस बात को दोबारा न दोहराएं। आपने (श्री महेन्द्र सिंह) कहा कि यहां पर माफिया है, कौन सा माफिया है? खनन माफिया है या वन माफिया है? आप अपने समय को याद कीजिए और उस

माफिया का संचालन करने वाले सारे लोग आज उधर (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा।) बैठे हुए हैं। सारे तो नहीं मगर उनमें से कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकारें आती / जाती रहती हैं और इस तरह की शब्दावली चलती रहती है। जब हम विपक्ष में थे तो हमारी तरफ से भी इसी तरह के चार्जिज लगते थे कि फलां-फलां वन माफिया या खनन माफिया है। इन बातों में कुछ सच्चाई भी होती है मगर राजनीति में कुछ लोग अपनी बात बढ़ा-चढ़ाकर भी बोलते हैं। इस तरह के आरोप/प्रत्यारोप लगाना कोई ठीक बात नहीं है। We are concerned about many things. हम

27.3.2017/1525/av/dc/2

चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सिज का ठीक से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से खनन या दूसरा कोई अवैध काम करता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि हम उसको सख्ती से रोके और उसका अच्छा नतीजा आज हमारे सामने आया है। आपने जो मुख्य बातें कही थीं मैंने उनका उत्तर दे दिया है। मैंने जो यहां पर कहा है उससे मुझे आशा है कि आपके दिल में जो शक-शुबह था वह दूर हो जायेगा।

27.3.2017/1525/av/dc/3

अध्यक्ष : अभी मांग संख्या 7 पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं इसमें श्री सुरेश भारद्वाज, डॉ0 राजीव बिन्दल, श्री रिखी राम कौंडल, श्री जय राम ठाकुर, श्री बलदेव सिंह तोमर और श्री वीरेन्द्र कंवर भी शामिल हैं। मैं अब श्री सुरेश भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए बीच में उठकर कहा था कि अगर मुख्य मंत्री जी एक-एक मैम्बर की बात का जवाब देने लगेंगे तो यह एक ही मांग पांच दिन में पूरी होगी। हम चाहते हैं कि पूरी-की-पूरी 32 डिमांड्स पर चर्चा हो, 10 डिमाण्ड की तो

हमने प्रायोरिटी दे रखी है। अगर मुख्य मंत्री जी एक-एक बात का जवाब देंगे तो ये सारी डिमाण्ड्ज पूरी नहीं होगी।

Chief Minister: Speaker Sir, in parliamentary democracy --(---interruption---) it is Government's rights to reply there and then, so that the same matter is not repeated again and again.

श्री सुरेश भारद्वाज : यह आपका (श्री राकेश कालिया) काम नहीं है यह स्पीकर को बोलना है। मैं क्या बोलता हूं, क्या नहीं बोलता हूं ---(---व्यवधान---) हां, मैं बार-बार बोलूंगा। (---व्यवधान---) मैं रूल्स के हिसाब से बोलता हूं, तुम्हारी तरह खड़ा होकर नहीं बोलता हूं। मैं रूल्स के अंदर बोलता हूं । (---व्यवधान---) आपको गुस्सा इस बात का है कि आपको स्पीकर या मंत्री नहीं बनाया। इसमें मेरा कसूर नहीं है। (---व्यवधान---)

श्री वर्मा द्वारा जारी

27/03/2017/1530/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

Speaker : (interruption) Everybody sit down please. (interruption) No direct arguments please. Mr. Bhardwaj, Hon'ble Member . . . (interruption) I have asked him. (interruption) Mr. Bhardwaj, Hon'ble Member, I request you to please continue.

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या:7 - पुलिस और सम्बद्ध संगठन इस मांग पर हम चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, जिस प्रकार से माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने बताया कि ये देव भूमि है, बहुत शान्तिप्रिय देश है। लेकिन यहां पर आज जिस प्रकार की स्थितियां हो रही है, आज के समाचार में आपने पढ़ा होगा- शिमला के विक्ट्री टनल के पास अफगानी स्टूडैंट्स आते हैं और उनको

घेरे कर पिटा जाता है। ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि पुलिस का जो वर्चस्व होना चाहिए, जो कानून-व्यवस्था पर डर होना चाहिए, वह यहां नहीं रहा है। इनको माफिया शब्द का प्रयोग करने से तक्लीफ होती है, लेकिन इसी शिमला में एक "युग" नामक बालक को फिरौती के नाम पर उठा दिया गया और फिर बादउ में उसका शव मिला। उसके कंकाल एक पानी के टैंक में पाये गए। मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमें जो मुलज़िम हैं वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि इस केस को यहां से ट्रांस्फर कर दिया जाये, क्योंकि ये डे-टू-डे ट्रायल हो रहा है। उस केस में गर्वनमेंट को डिफेंड करना चाहिए था, कि केस ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई अपीयर ही नहीं होता है। इसी प्रकार से "ध्रुव लखनपाल" नामक का एक युवक सुबह-सुबह भरे बाजार से गुम हो जाता है। उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज़ की जाती है, आई0जी0, ए0डी0जी0पी, लॉ-एण्ड ऑर्डर ने उसमें कहा कि एस0आई0टी0 बनाएंगे, मैं स्वयं उसके लिए उनके पास गया लेकिन कोई एस0आई0टी0 नहीं बनी। वह कहीं पर नहीं मिला और 6 महीने बाद उसका कंकाल मिलता है और जब उसका डी0एन0ए0 टैस्ट होता है तो वह पहचाना जाता है कि यह ध्रुव लखनपाल का है। उसके बारे में कोई छानबीन नहीं की जाती है। ये शिमला की घटनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। जहां पर पुलिस/सरकार का सारा तंत्र मौजूद रहता है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में आई0एस0आई0एस0 के पोस्टर लग जाते हैं, लेकिन उसकी कोई छानबीन नहीं

27/03/2017/1530/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

होती है और न उसका कोई पता चल पाता है। कालाअंब में बारूद पाया जाता है उसकी भी कोई छानबीन नहीं होती है। नाहन में हथियार मिलते हैं, लेकिन आज तक उसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि उसका क्या हुआ है? बंजार में, आज ही एक प्रश्न में उसका उत्तर भी आया है, आई0एस0आई0एस0 का एक संदिग्ध व्यक्ति 6 महीने तक ऑपरेट करता रहता है और 6 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। अब उसको एन0आई0ए0 को सौंप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की अनेकों घटनाएं घट रही है, जिनमें से ये कुछेक उदाहरण हैं जो हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर करते हैं। इसी तरह अनेकों मन्दिरों में चोरियां हो जाती है, उनका पता ही नहीं चलता है। छोटे-छोटे

अपराध तो यहां पर अब इस प्रकार से हो गए हैं, जैसे पहले मैदानी इलाकों में हुआ करते थे। हिमाचल प्रदेश जैसे शान्तिप्रिय प्रदेश में आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी में गाड़ियां चुराने वाला एक गिरोह सक्रिय है, बाहर से गाड़ियां चुरा करके आते हैं, हिमाचल प्रदेश में बेचते हैं। ऐसी अनेकों गाड़ियां मंडी और बल्द्धवाड़ा में पकड़ी गई। इस तरह की 26 गाड़ियां थी उसमें पुलिस के ही एक कर्मचारी को पकड़ा गया है, जो कांस्टेबल था उसको

श्रीमती एन.एस. ....द्वारा जारी।

27/03/2017/1535/ एन0एस0/ए0जी0/1

श्री सुरेश भारद्वाज ----- जारी

संस्पैंड कर दिया गया है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब यहां पर भी यह मामला उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार की इंटरफेयरेंस ऊपर से हो रही है। जो इस बात को उजागर करने वाले लोग हैं, उनको सस्पैंड कर दिया जाता है और उनके ऊपर दबाव डाला जाता है जोकि पुलिस के अपने रिकॉर्ड में भी है। पुलिस का जो रोज़नामचा होता है वह एविडेंस वेल्यू का पक्का सर्टिफिकेट होता है। अगर उसके बारे में कोई चर्चा होती है तो उस व्यक्ति को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऊपर से जो अधिकारी फोन करते हैं, वह मामला उस रोज़नामचे में दर्ज़ है। फिर यह बताया जाता है कि शायद कुछ लोग पुलिस के साथ सम्मिलित हैं। इस प्रकार की अनेकों घटनायें हो रही हैं और ऊपर से अनावश्यक रूप से दबाव डाला जाता है, तब हमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। इनका अधिकार सरकार चलाना और कानून व्यवस्था का पालन करवाने का है तो हमारा अधिकार उस चीज़ को उजागर करना है और इसलिए जनता ने हमें यहां पर भेजा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मांगल गांव, अर्की में है और वहां पर पिंकू राम नाम का व्यक्ति पडयार गांव मांगल का रहने वाला था। उसे मार दिया गया और आज तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए हैं। इस प्रकार की अनेकों घटनायें हो रही हैं। नशे के मामले में भी फिगर्ज़

आये हैं कि वर्ष 2012 में नशे के इतने केसिज़ बने हैं और आज केसिज़ ज्यादा बन गए हैं। यह भी इस बात की रिफलैक्शन है कि आज नशा/ड्रग्ज़ माफिया हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा ऑप्रेट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एस0एस0पी0 वहां पर एफिडेविट दाखिल करता है कि जो नशा पंजाब में आ रहा है उसका ऑरिजिन हिमाचल प्रदेश में है और वहां से आ रहा है। अगर यह बात गलत है तो हमें उस बात को रिवर्ट करना चाहिए। हमने वकीलों की पूरी फौज़ बना रखी है। हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फीस देते हैं। जब कोर्ट में रिवर्ट करने की बात आती है और अगर यह बात गलत है तो फिर यह रिवर्ट क्यों नहीं होता है? अगर यह रिवर्ट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इस बात में सच्चाई है कि नशा यहां से जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि शिमला का जो चारों तरफ का एरिया है, खासकर संजौली, ढली, भट्टाकुफर आदि का जो सराउंडिंग का एरिया

27/03/2017/1535/ एन0एस0/ए0जी0/2

है, उसमें ड्रग्ज़ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे बच्चे इन एरियाज़ में रहते हैं। आपको यह भी मालूम है कि पहाड़ों में जिनके सेब के बगीचे हैं, उनके बच्चे दादा या मां के पास यहां पर रहते हैं। उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल बच्चों पर नहीं होता है। ड्रग्ज़ माफिया यहां पर पहुंचते हैं और उनको पहले छोटी-छोटी चीजें देते हैं और बाद में वे नशे के आदी हो जाते हैं। इस पर शिमला पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। भांग की खेती पर भी संज्ञान लिया है। इस पर शिमला पुलिस ने एक या दो बार संजौली में जागरूकता अभियान भी चलाया है। हमारा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इन सारी घटनाओं को ध्यान में रख कर संज्ञान लिया जाए क्योंकि यह फ्यूचर जेनरेशन के खराब होने का सवाल है जिसके लिए हम सभी को कन्सर्न्ड होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार की घटनाओं को आज नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं इन बातों को आपके ध्यान में लाने के लिए इस माननीय सदन में बता रहा हूं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऑफिशियल फाइलों के द्वारा शायद आप तक नहीं पहुंचती हैं। जब ये बातें हमारे पास पहुंचती हैं तो हम आपको इन बातों का सदन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस को जो एक महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाती है, वह पुराने ग्रेड से दी जा रही है। उन्हें यह तनख्वाह नये ग्रेड से मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल

रही है। कई विभागों में कर्मचारियों को आउटसोर्स से रखा जा रहा है, उन्हें ठेके पर रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब तो पुलिस को भी ठेके पर रखा जा रहा है। कांस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हो रहे हैं। वे 7-8 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे और 8 साल के बाद उनको पक्का किया जाएगा। इससे वे काम नहीं करेंगे। अगर आप आर्मी, पुलिस और पैरा-मिलिटरी फोर्सिज में भी ठेके पर इम्पलायीज़ रखे जायेंगे तो

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

27/3/2017/1540/RKS/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज... जारी

उससे कानून-व्यवस्था को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जो ठेके पर भर्ती किए गए हैं उनको तुरंत रेग्यूलर किया जाए। आईंदा से सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएं कि कम-से-कम जो पुलिस विभाग में हैडकॉंस्टेबल या इससे ऊपर के फोर्स के आदमी हैं, कॉंट्रैक्ट के आधार पर उनकी भर्ती न की जाए। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी के साथ इसमें फायर सर्विसिज़ और होम गार्ड्ज की भी बात आती है। होम गार्ड्ज वालों को प्रोपर रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है। अधिकतर जगह हम होम गार्ड्ज के इम्प्लॉइज को ही ड्यूटी पर तैनात करते हैं। क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स की संख्या कम हैं। हमें होम गार्ड्ज के इम्प्लॉइज को प्रोपर वेतन देना चाहिए। भले ही हम उन्हें रेग्यूलर नहीं कर सकते हैं परन्तु उनके रिम्यूनरेशन बढ़ाए जाएं। होम गार्ड्ज तो होम गार्ड्ज से ही आएगा। लेकिन आजकल जो कम्पनियां आउटसोर्स करके भेज रही हैं और उन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं उनके स्थान पर होम गार्ड्ज के लोग ज्यादा रिलाइबल है और ज्यादा काम करने वाले भी हैं। सिक्योरिटी एजेंसिज़ में इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर मैं शिमला की बात करूं तो शिमला में लिफ्ट के नीचे जो पुल है उसके नीचे

होम गार्ड्ज का दफ्तर है। वह एरिया बहुत बड़ा है और वहां पर बहुत बुरा हाल है। वहां पर रहना मुश्किल काम है। इसलिए इनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए बजट में प्रोपर प्रावधान होना चाहिए।

अभी 3-4 दिन ही गर्मी के प्रारंभ हुए हैं। जंगलों में आग लगने की घटना प्रारंभ होने लगी हैं। इसके लिए फायर सर्विसिज़ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अभी तांगणु गांव में आप लोग भी गए थे और बाकी लोग भी गए थे। ऐसे स्थानों पर पहुंचना मुश्किल काम है। कम-से-कम प्रत्येक स्थान पर सब डविजनल हैड क्वार्टर पर फायर सर्विसिज़ का प्रावधान होना चाहिए। आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, शिमला में बहुत ज्यादा

27/3/2017/1540/RKS/AS/2

सर्दी थी और तीन दिन के भीतर ही तापमान बढ़कर बहुत अधिक हो गया है। आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, पुलिस और इसके जो संगठन हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टोलरैंस की बात की गई है। इसमें विजिलैंस भी आता है। एंटी-क्रप्शन भी इसी का भाग है। इसको स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है। जो इनवेस्टिगेशन अनकों वर्षों तक चलती रही है वह कम समय में पूरी हो जाए। उसमें समयबद्ध एक्शन हो तब तो जीरो टोलरैंस की बात समझ में आएगी अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker: I request to every speaking Hon'ble Member to be brief and speak on the Demand only so that they can speak more and less time. Now, I request Dr. Rajeev Bindal to speak on this Demand.

27/3/2017/1540/RKS/AS/3

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, 'मांग संख्याः 7' अगर कोई विषय ड्रग्ज से संबंधित रखते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसको अदरवाइज लेते हैं। हमारा दायित्व है कि हम सरकार का ध्यान इस दिशा में आकर्षित करें। जब ड्रग्ज माफिया, शराब माफिया की बात आती है तो उसको अपनी ओर लेने का प्रयास करते हैं। अमृतसर में हिमाचल प्रदेश का युवक हेरोईन के साथ पकड़ा जाता है। वह ऊना का रहने वाला है। यह क्या इस बात के लिए काफी नहीं है और

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.03.2017/1545/SLS-AS-1

डॉ0 राजीव बिन्दल...जारी

उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं इसको वाया हिमाचल लेकर आया हूं। वह विषय राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में हैडलाइन बना है। क्या वह हमारी छवि को दागदार करने के लिए काफी नहीं है? माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि लीडर ऑफ अपोजीशन और अपोजीशन के लोग ड्रग माफिया की बात कहकर हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं। यह घटना अमृतसर में हुई और वहां पर यह मामला अख़बारों और मीडिया में खूब चला। यह हिमाचल के लिए कोई गौरव की बात तो नहीं थी। हमें इस बारे में बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। कोई भी नगर या छोटा-बड़ा टाऊनशिप ऐसा नहीं है जिसके अंदर ड्रग को ऑपरेट करने वाले, उसको जगह-जगह पहुंचाने वाले लोग न हों। नेशनल

हाईवे - 72 के किनारे तथा पांवटा और नाहन के बीच में 72 किलो भुक्की एक टायर पंक्चर लगाने वाले की दुकान से बरामद होती है। वह ट्रक ड्राइवरों का और नशे के सौदागरों का परमानैंट अड्डा रहा है। ऐसे कितने अड्डे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि पुलिस को ऐसे अड्डों की जानकारी नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। सौ प्रतिशत लोगों को पुलिस के कर्मचारी जानते हैं कि कौन इसमें लगे हुए हैं। अधिकारी शायद इस बात को अदरवाईज लें परंतु अगर एक दिन आदेश हो तो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी उनको चौबीस घंटे के अंदर हाज़िर कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक शराब की बात है, आपने Beverages Corporation of Himachal Pradesh की बड़ी प्रशंसा की। इसकी ऐसी कौन-सी ज़रूरत आन पड़ी। हम पहले ही 32 कार्पोरेशनों में घाटा उठा रहे हैं फिर एक कार्पोरेशन और बना दी। आपने कहा कि उससे बड़ा प्रॉफिट हो गया। सरकार के ही सारे अधिकारी उसमें लगे हैं और तनख्वाह भी सरकार ही दे रही है जबकि फायदा उसके नाम जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। सिरमौर जिले के 60 परसैंट गांवों में ठेके के अलावा घर में सप्लाई की शराब पहुंच रही है। अगर आप किसी अधिकारी को डिप्यूट करें, हम गांव के लोगों से मिलवा करके और उनके यहां बैठ

27.03.2017/1545/SLS-AS-2

कर देखेंगे कि गांव का व्यक्ति ऑर्डर करेगा और सप्लाई एक घंटे के अंदर उसके घर में पहुंचेगी। इसलिए प्रॉफिट कहां से आएगा? उस बोतल के ऊपर हरियाणा का मार्का लगा हुआ है। वह सारी-की-सारी बॉर्डर एरिया से ही अंदर आ रही है। क्या वह बिना मिलीभगत के आ रही है? कौन उसको लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आ रहा है जबकि सब तरफ़ नाके लगे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है कि केवल एक बोतल या एक पाऊच लेकर आया और उसी की सप्लाई कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह शराब की कार्पोरेशन ही अपने आपमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसके कारण जो पुलिस के लिए काम बढ़ा है, वह एक और बड़ी मुसीबत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि स्टोर नहीं मिलते। जमटा में एक स्टोर है।

वहां पर सौ से लेकर सवा सौ ट्रक चौबीस घंटे हाईवे के ऊपर खड़े हैं क्योंकि उनको शराब अनलोडिंग करने की जगह उपलब्ध नहीं है। एक-एक ट्रक 5 दिन में अनलोड होता है। वह सारा इलाका शराब के नाम से जाना जाने लगा है। कभी उस स्टोर में आटा-दाल रखते होंगे। यही स्थिति बाकी जगहों की भी होगी; मैंने वह नहीं देखी।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी भारद्वाज जी ने बात कही। काला अम्ब में जो जिंदा कारतूस मिले थे,

जारी..श्री गर्ग जी

27/03/2017/1550/RG/DC/1

डॉ. राजीव बिन्दल---जारी

नाहन वाले तो पता लग गए कि किसने किया और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन वह जो 250 कारतूस वहां मिले, आज तक उस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक व्यक्ति भी उसमें नामज़द नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है और सीमा क्षेत्र में इस प्रकार की घटना अपने आप में चिन्ताजनक है।

माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब के थाने में सर्वाधिक मामले दर्ज़ हैं। वहां चोरियों, डकैती, झगड़े इत्यादि वारदातों की संख्या सर्वाधिक है और उसमें भी वहां की माजरा चौकी में सबसे ज्यादा मामले दर्ज़ हैं। चाहे तो आप अपना डाटा निकाल कर देख लें। मैंने इस बारे में विधान सभा में एक प्रश्न भी लगाया था जिसका उत्तर आपने यहां दिया था। माजरा चौकी में एक ए.एस.आई. और थोड़ा-बहुत स्टाफ है। वहां कोई गाड़ी नहीं है, छोटी-मोटी मोटरसाइकिल है। हमने बार-बार इस बारे में आग्रह किया है, प्लानिंग की मीटिंग में भी और पत्र में भी लिखकर दिया है और सरकार इस बात को मानती भी है। इसलिए माजरा का थाना बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। जैसा मैंने कहा कि वहां सर्वाधिक मामले पंजीकृत हो रहे हैं। यदि वहां थाने के हिसाब से सुविधाएं दी जाएं, तब हम वहां वारदातों कों नियंत्रण करने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा वारदातें उस चौकी के अन्तर्गत होती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक अनधिकृत पार्किंग का मामला लाना चाहता हूं। हम शिमला से शोघी तक चलते हैं, तो कम-से-कम डेढ़ सौ ट्रक व गाड़ियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारह महीने/तीस दिन खड़ी रहती हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो पिछले तीन साल से खड़ी हैं, न उनमें टायर है और न ही उनमें स्टयरिंग है। ऐसी गाड़ियां हमारे ट्रैफिक जाम के लिए बहुत मदद करती हैं। लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं करता। वहां से माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी या पुलिस अधिकारी सभी लोग जाते हैं, परन्तु उन्हें किसका डर है? वह अनिधकृत पार्किंग राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं हटती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ढाबे पर 15 मिनट के लिए गाड़ी लगाकर खाना खाने का रुक जाए, तो उसकी गाड़ी में चालान लगा हुआ जरूर मिलता है। यानि वही अधिकारी 15 मिनट रुकने वाले का चालान करता है और वही अधिकारी 15 महीने रुकी हुई गाड़ी को न छेड़ता है और न उसका चालान करता है। ये दो

27/03/2017/1550/RG/DC/2

प्रकार के सिस्टम यहां क्यों हैं? या तो वहां उस स्थानीय थाने की मिलीभगत है या फिर बाहर के लोगों को तंग करने का काम है। सिर्फ यहीं की यह बात नहीं है। यह स्थिति सब जगह है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी केवल एक ऑर्डर से इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी थानों में सड़ी हुई और जंक लगी हुई गाड़ियों के ढेर लगे हैं। क्योंकि वे गाड़ियां किसी-न-किसी मामले में नामजद हैं। इसलिए वे रिलीज नहीं होतीं। थानों की जगह रुक गई है एवं थानों में पार्किंग खत्म हो गई है। इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन थानों को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थान कालाअम्ब है और वहां पिछली सरकार के दौरान थाना बन गया था और उसका लाभ अब जनता को मिल रहा है क्योंकि वहां बहुत केसजि हैं। परन्तु वह पुराने पुलिस चौकी के भवन में ही चल रहा है। वह बहुत छोटा सा स्थान है और वह बॉर्डर एरिया है। वहां क्राईम बहुत ज्यादा है। माता त्रिलोकपुर मंदिर में 15 लाख यात्री दर्शन के लिए आते हैं और वह क्षेत्र उसी थाने के अन्तर्गत पड़ता है। इसलिए उसके लिए स्थान, भवन और वाहनों की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्ताओं ने होमगाड्र्ज की बात कही। जो विषय होमगार्ड का है कि उनको तनख्वाह तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिल गई, लेकिन उनको काम नहीं था। 15 दिन या महीने भर वह खाली बैठता है,

एम.एस. द्वारा जारी

27/03/2017/1555/MS/DC/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी------

उसके बाद उसका नम्बर आता है। जितने दिन उसको काम मिलना चाहिए, उतने दिन उसको काम नहीं मिलता है। इसके कारण वहां पर फ्रस्ट्रेशन लैवल ज्यादा रहता है। जो पुलिस के थाने हैं उनमें साधनों का अभाव है। उनमें गाड़ियां और मोटर साइकिल्ज की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए। जो प्रार्थी होता है पुलिस उसी को कहती है कि गाड़ी ले आओ, हम आपके साथ चलेंगे। जो प्रभावशाली है वह गाड़ी लेकर आता है और उसके प्रभाव का इस्तेमाल होता है।

अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण विषय कहना चाहूंगा जिसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, जहां भी झगड़ा होता है तो जो झगड़ा करने वाला व्यक्ति है वही सबसे पहले जाकर एफ0आई0आर0 दर्ज़ करवाता है और जिसका सिर फटा होता है उसकी बारी बाद में आती है। इस तरह जो काउंटर एफ0आई0आर0 दर्ज़ करने का सिलसिला है इसको हर थाने में प्रमोट करने का काम चला हुआ है।

Speaker: Please wind up. There are still 5 to 6 Members to speak.

डॉ0 राजीव बिन्दलः मैंने पहले ही कहा है कि अंतिम बात करूंगा। ये जो काउंटर एफ0आई0आर0 है इसके बारे में और गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वे थाने की मिली-भगत से तुरन्त 15 मिनट के अंदर काउंटर

एफ0आई0आर0 दर्ज़ करवाते हैं और जिसके साथ ज्यादती हुई होती है उसको रिलीफ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के लोगों तथा महिलाओं के ऊपर बढ़ने वाले अत्याचार हैं और उनके ऊपर जो लगने वाली धाराएं हैं उसके बारे में हम अपने स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दें और उसमें पूरी नेक-नीयती के साथ ही मामले दर्ज़ किए जाएं। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

27/03/2017/1555/MS/DC/2

अध्यक्षः अब श्री रिखी राम कौंडल जी चर्चा में भाग लेंगे

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, मांग संख्या-7 -पुलिस और सम्बद्ध संगठन पर जो कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा चल रही है, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

किसी प्रदेश की कार्य-प्रणाली और सरकार की पारदर्शिता का केवल एक ही लोगों के मन में मापदण्ड गिना जाता है कि हम क्या इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं या नहीं हैं। अगर आम जन-मानस यह महसूस करे कि इस सरकार के होते हुए हम सुरक्षित हैं, कानून-व्यवस्था ठीक होगी, गांव में कोई गुण्डागर्दी नहीं होगी, पुलिस वाले नाजायज किसी को परेशान नहीं करेंगे और जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चलती हैं उनसे नाजायज वसूली न की जाए तो ये सारी कार्य-प्रणाली एक सरकार की पारदर्शिता को दर्शाती है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सरकार को बने हुए चार साल हो गए हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी जगह क्राइम बढ़ा या घटा है। परन्तु अधिकांश जो हमारे संवेदनशील मामले हैं उनमें क्राइम की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2012 में आपने सरकार सम्भाली। वर्ष 2012 में attempt to murder के 53 केस रिपोर्टिड हुए और उसमें वर्ष 2015 तक की फिगर जो सरकार द्वारा आपकी वेबसाइट पर जारी की गई है उसमें बढ़ोत्तरी हुई है और आज इसमें 64 केस रिपोर्टिड हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार कानून-व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से चला रही है? उसके बाद दूसरा उदाहरण आज सारे प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने आपको सुरक्षित नहीं मान रही हैं। इसी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, वहां कानून-व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए वहां लोगों ने बदलाव किया। यही कारण होगा कि आपका भी बदलाव आने वाले समय में होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं रेप के केसिज की थोड़ी बात करना चाहूंगा,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

27.03.2017/1600/जेके/एजी/1

श्री रिखी राम कौंडलः-----जारी------

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य पहले आप अपनी फिक्र करो हमारी फिक्र छोड़ दो।

श्री रिखी राम कौंडलः माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी कुर्सी बड़ी है, वह जाएगी हमारी तो छोटी है चली जाएगी तो भी चिन्ता की कोई बात नहीं है। चिन्ता आपको ज्यादा है हमें नहीं है। रेप के केसिज हिमाचल प्रदेश के अन्दर जब वर्ष 2012 में आपने सरकार सम्भाली थी उस समय 183 थे और आज बढ़कर 244 हो गए। वर्ष 2015 तक आपकी फिगर है और वेबसाईट पर आपकी दी हुई फिगर है। ये तो मैंने फिगर नहीं बनाई है और न ही किसी दूसरे ने बनाई है। अभी वर्ष 2016 की रिपोर्टिंग होनी है और मेरा अपना अनुमान है कि इससे ज्यादा 2 या 3 परसेंट की बढ़ौत्तरी हुई है जो कि मेरी सूचना है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बच्चों के अत्याचार वाले मामले। जब आपने सरकार सम्भाली थी तो उस समय 172 थे और आज 327 मामले हैं। जो हमारा आकलन है। हम जो विपक्ष में हैं जिनको लोगों ने भूमिका दी है कि सरकार की गल्तियों को माननीय सदन के अन्दर उजागर करना है वह हमारा प्राथमिक दायित्व बनता है। उस दायित्व के आधार पर हम आपको बता रहे हैं वर्ष 2012 में 172 केसिज रिपोर्टिड थे जब आपने सरकार सम्भाली थी। यहां तो आप बड़ी ढींगे मारते हैं कि हमने कानून-व्यवस्था ठीक कर दी, हमने इस प्रदेश के अन्दर राम राज्य खड़ा कर दिया है। सरकार की कानून-व्यवस्था पारदर्शी होती है। जिस प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक होती है उस सरकार की सारे देश के अन्दर अच्छी छवि मानी जाती है। उसके बाद assault on woman इसमें ज्यादातर महिलाओं के केस हैं। assault on woman के वर्ष 2012 में 250 केस थे जब आपने सरकार सम्भाली थी। ऐसा है इस प्रदेश के

अन्दर क्राइम कभी न हम रोक सकते हैं और न ही आप लोग रोक सकते हैं। जो क्राइम करने वाले लोग हैं वे तो क्राइम करेंगे लेकिन अगर सरकार का उन पर डर हो तो क्राइम कम हो जाता है। assault on woman के

27.03.2017/1600/जेके/एजी/2

केस वर्ष 2012 में जब आपने सरकार सम्भाली 250 थे और आज 434 हो गए हैं। उसमें डबल बढ़ौत्तरी हुई है। हम कैसे इस सदन के अन्दर कह सकते हैं कि आपने इस प्रदेश में कानून-व्यवस्था ठीक की है? एक्सिडैंट के केसिज क्यों होते हैं? एक्सिडैंट के केसिज इसलिए ज्यादा होते हैं जब ट्रेफिक का कन्ट्रोल पूरा न हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस थानों की स्ट्रैंथ वही है जो शुरू में थी। अगर हम इस प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो हमें पोस्टें सेंक्शन करनी पड़ेगी। थानों की बढ़ौत्तरी करनी पड़ेगी। आज होम गार्डज के माध्यम से सरकार कानून-व्यवस्था को चला रही है। इससे पहले मैंने एक्सिडैंट के केसिज का जिक्र किया other IPC offences उसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ौत्तरी हुई है। उसमें कन्सोलिडेट करके 5250 केसिज वर्ष 2012 में थे जब आपने सरकार सम्भाली थी। अब 7491 केसिज आपकी वेबसाईट के ऊपर रिपोर्टिड हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि किसी सरकार की कानून-व्यवस्था उसकी पारदर्शिता क्राईम अगर कम हो जाए तो गिनी जाती है कि सरकार अच्छा प्रशासन देने वाली सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे शाहतलाई में बाबा बालक नाथ के मेले लगे हैं। बाबा बालक नाथ के मेले वहां सारा साल जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनका एक ही आजीविका का साधन है क्योंकि एक महीना वह मेला लगता है। ऊना से लेकर शाहतलाई तक पुलिस के नाके इतने लगे हैं कि हर जगह वसूली की जा रही है और इस तरह से हमारे शाहतलाई मेले में यात्रियों की संख्या कम हुई है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मैं इस माननीय सदन के अन्दर कोई नया विधायक नहीं हूं, पांचवीं बार इस माननीय सदन के अन्दर आया हूं। हर बार मैंने मेले का प्रबन्ध देखा है लेकिन इस बार बहुत अन्याय हो रहा है और सारे यात्री वहां से वापिस जा रहे हैं। इसके बारे में भी सरकार

ध्यान दें। डी0जी0पी0 साहब यहां पर बैठे हैं। इसका संज्ञान लें कि ऊना से ले करके शाहतलाई तक ट्रेफिक

27.03.2017/1600/जेके/एजी/3

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी) पदासीन हुई ।

पुलिस वाले वहां हर जगह खड़े हैं। जो गलत गाड़ी है उसका तो चालान होना चाहिए लेकिन अगर गलत तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाएं उससे बहुत दुख होता है। हमारे जैसे व्यक्ति ने सारा समय इस सदन के अन्दर लगा दिया और प्रशासन का भी सहयोग रहा। हमने भी प्रशासन को सहयोग दिया। ऐसी बातें हमारे से सहन नहीं होती है। इसके बारे में संज्ञान लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, काफी बातें बिंदल जी ने कह दी, सुरेश भारद्वाज जी ने बड़े डीटेल में कह दी है। उसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो केवलमात्र इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी संभल जाओ अभी थोड़ा सा समय है ।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

27.03.2017/1605/SS-AG/1

श्री रिखी राम कौंडल क्रमागतः

अगर आप कानून-व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो आपकी कानून-व्यवस्था आने वाले चुनाव में लोग ठीक कर देंगे।

सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

27.03.2017/1605/SS-AG/2

सभापतिः माननीय सदस्य, श्री जय राम ठाकुर जी।

श्री जय राम ठाकुरः सभापति महोदया, मांग संख्या-7 पर जो कटौती प्रस्ताव इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये गए हैं, मैं भी उसमें अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि बहुत बातों का यहां पर ज़िक्र हो गया। कानून-व्यवस्था अच्छी हो, यह सबकी चिन्ता का विषय स्वाभाविक रूप से है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था बिल्कुल खराब है। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और मुझे लगता है कि यहां और भी बेहतर ढंग से कानून-व्यवस्था को बनाये रखें, उस दृष्टि से कुछ बातें करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं जब हम यहां बोलते हैं कि सुधार की गुंजाइश है तो उन्हें इस पर भी परेशानी होती है। जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा। जब कहेंगे कि गलत है तभी उसमें ठीक होने की उम्मीद बनेगी।

सभापति महोदया, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टी के कुछ कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में निर्धारित हुए। विपक्ष के नेता, आदरणीय धूमल जी बिलासपुर और कुल्लू गए। लेकिन यह सच्चाई है कि कार्यक्रम में वहां गए तो पार्टी के विधायकों की जेबें कट गईं। उनकी जेब से पर्स निकाला गया, हज़ारों रुपये का नुकसान इस माननीय सदन के विधायकों का हुआ। गोविन्द ठाकुर जी का पर्स खाली मिला। ये बोलते हैं कि बाद में पर्स मिला जो किसी काम का नहीं रहा। महेश्वर सिंह जी और उसके अलावा पार्टी के कई पदाधिकारियों की जेब से जो सामान निकाला जा सकता था वह निकाला गया और हज़ारों रुपये का नुकसान इस दृष्टि से हुआ। अगर हम इसका भी ज़िक्र न करें तो मुझे लगता है कि वह बात ठीक नहीं है। ज़िक्र तो करना पड़ेगा। वे कौन लोग थे? एक गैंग की शेप में थे। हमारा कहने का मतलब यह है। एक दिन पहले यह घटना बिलासपुर में होती है और दूसरे दिन कुल्लू में होती है तो स्वाभाविक रूप में इससे पता लगता है कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। सभापति महोदया, आने वाले समय में विधान सभा के चुनाव आ रहे हैं और विधान

सभा के चुनाव में प्रदेश व देश के नेता यहां आने वाले हैं और जो इस प्रकार का गिरोह है वह किस प्रकार से अपने मकसद को अंजाम देगा इस पर मुझे लगता है कि समय रहते सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा हम महसूस कर रहे हैं कि जहां हम बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है लेकिन उसके बावजूद हमको इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि चम्बा में साहू में पाकिस्तान के झंडे लहराये जाते हैं। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है? चुराह के चरड़ा रोड में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लिखे जाते हैं। यह चिन्ता का विषय है। अगर इसी पर हम जाएं तो चम्बा में जो जम्मू-कश्मीर के साथ लगता इलाका है, जहां पर इस बात की सम्भावना है और 1998 की सतरूंडी की घटना हमारे ध्यान में है, लगभग 35 लोग वहां पर मारे गए थे और 6-7 लोग वहां से अगवा हुए थे। ऐसी परिस्थिति में वहां पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जब वहां पर नारे लिख दिए और पाकिस्तान का झंडा लोगों ने उठाया तो इस बात को लेकर गम्भीरता से जो करना है वह करने की आवश्यकता है। हमारे साथी कह रहे थे कि इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगी शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़-तोड़ कर वहां नीचे फेंकी हुई हैं। लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होती है।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2017/1610/केएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

मेरे विधान सभा क्षेत्र में हम एक पुल का शिलान्यास बजट प्रावधान के साथ करके गए और जिस दिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उस दिन रात को ही उस पुल की शिलान्यास पट्टिका तोड़ दी गई लेकिन आज तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई, कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मंत्री रहते हमने उसका शिलान्यास किया था। यह भी चिन्ता का

विषय है कि प्रधान मंत्री का पुतला जलाया जाता है लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं होती है । वे इस देश के प्रधान मंत्री हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे प्रधान मंत्री को आज देश नहीं बल्कि दुनिया के नेता के रूप में देखा जाता है। उनका पुतला जलाया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है और हिमाचल प्रदेश के सत्तारूढ़ नेताओं का, मुख्य मंत्री का पुतला जलाया जाता है तो तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज होती है। इन बातों को सोचने की आवश्यकता है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में थाची में मैं और ठाकुर गुलाब सिंह जी, हम उस वक्त दोनों मंत्री थे और हमने उस वक्त एक रैस्ट हाऊस की बिल्डिंग का शिलान्यास किया। उसके शिलान्यास की पट्टिका के टुकड़े-टुकड़े कर दिए लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोमगार्ड के सीनियर सैकंडरी स्कूल का शिलान्यास मैंने मंत्री होने के नाते किया उसका भी पत्थर तोड़ कर रख दिया और उसके बावजूद वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाड़ी चौकी सीनियर सैकंडरी स्कूल के भवन का शिलान्यास मैंने 27 मई, 2012 को किया लेकिन कांग्रेस का एक नेता वहां जाता है जिसकी एक बार नहीं बल्कि दो बार जमानत जब्त हुई है, वह कहता है कि मुझे शिलान्यास दोबारा करना है। वहां पर स्कूल के जो अभिभावक हैं, उन्होंने कहा कि शिलान्यास की पट्टिका सामने लगी है लेकिन उसके बावजूद कहता है कि शिलान्यास हो कर रहेगा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उनके शिलान्यास की पट्टिका को उनके सामने तोड़ दिया लेकिन एफ.आई.आर. किसके खिलाफ दर्ज होती है? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी वहां पर उपस्थिति थे उनके खिलाफ होती है। वहां पर कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और जो गलत है वे लोग उसका विरोध कर रहे थे

27.03.2017/1610/केएस/एएस/2

लेकिन उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया। ऊपर से यह भी कहा गया कि विधायक को भी इसमें शामिल किया जाए और उनके खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। ऐसी बातों

पर सोचने की आवश्यकता पड़ती है। मण्डी में गाड़ियां चोरी करने वालों का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इन सारी बातों का जब जिक्र करते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है जिसका सत्तारूढ़ दल के लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसके साथ-साथ क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। जितनी आधुनिकता टैक्नोलोजी के तौर पर पुलिस विभाग को दी जा रही है लेकिन जो इस प्रकार का क्राइम करने वाले लोग हैं, वे उनसे भी आगे जा करके उस तकनीक का तोड़ निकाल कर अपने मकसद को अंजाम देते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में टैक्निकल दृष्टि से पुलिस को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मुझसे पहले यहां पर मेरे साथी महेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि कोई घटना हो जाती है तो पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए जाते हैं, पुलिस वाले के पास गाड़ी नहीं होती वह कहते हैं कि गाड़ी का इन्तज़ाम करो। जो पैसे वाला आदमी है वह दरवाज़े के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और पुलिस वाले उसकी गाड़ी में बैठकर मौके पर जाते हैं और मौके पर जब जाते हैं तो निश्चित रूप से जिसने उनको गाड़ी में पहुंचाया है, पुलिस वाले उसके पक्ष में, थोड़ा किया या ज्यादा किया लेकिन उसके पक्ष में होते ही है क्योंकि वे ऑब्लाइज़ महसूस करते हैं। इसलिए इस बात की भी आवश्यकता है कि पुलिस विभाग में गाड़ियों की उचित व्यवस्था हो। कहीं भी इस प्रकार का क्राइम होता है तो जो मुज़रिम होता है या दूसरा होता है, कम से कम दोनों तरफ से एफ.आई.आर. जो वहां पर दर्ज होती है , उनसे किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशन नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी में बैठकर उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

27.03.2017/1610/केएस/एएस/3

सभापति महोदया, मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि जो इस बार बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें पुलिस वालों को उत्साह देने की दृष्टि से न उनके वेतन में

बढ़ौत्तरी की गई है और न होमगार्ड के जवान जो उनके बराबर ही काम करते हैं, उनके लिए भी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है। ट्रैफिक बढ़ती जा रही है लेकिन उसके बावजूद जितनी पुलिस की संख्या होनी चाहिए थी,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.3.2017/1615/av/as/1

श्री जय राम ठाकुर---------- **जारी**

उतनी न होने के कारण घंटों-घंटों जाम लगने के कारण बदहाली के दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बजट में पुलिस की भर्ती पर और ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग पर और ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। बहुत सारे मंदिरों में चोरी हो गई। आपके यहां शिमला जिला में मंदिरों में चोरी हुई। उसके साथ-साथ कुल्लू में मंदिरों में चोरी हुई और वहां पर आई0एस0आई0एस0 का एजैंट पकड़ा गया। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदया, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.3.2017/1615/av/as/2

सभापति (**श्रीमती आशा कुमारी**) : अब माननीय सदस्य श्री बलदेव सिंह तोमर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमर : सभापति महोदया जी, मांग संख्या : 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे प्रदेश में यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। यहां पर मेरे से पूर्व सदस्य कह रहे थे कि किस तरह से प्रदेश के अंदर शिलान्यास की पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में धूमल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के समय में कुछ शिलान्यास/ उद्घाटन हुए थे। उस समय के मुख्य संसदीय सचिव माननीय सुख राम चौधरी के नाम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पट्टिकाएं लगी थी। लेकिन उन पट्टिकाओं को तोड़ा गया और हमारे बार-बार कहने पर न तो उस बारे में पुलिस विभाग ने कोई एफ0आई0आर0 दर्ज की और न ही आज तक उन पट्टिकाओं को लगाया गया है। उसके विपरीत वर्तमान मुख्य मंत्री जी द्वारा लगाई गई एक पट्टिका अभी टूटी और उसके आठ दिन के अंदर वह पट्टिका दोबारा लगाई गई। इस प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार की कानून-व्यवस्था चली है। पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे युवा मोर्चा के नौजवान साथियों ने लोकतांत्रिक तरीके से एक विरोध प्रदर्शन किया। विधायक प्राथमिकता की स्कीमों का शिलान्यास करने के लिए जनता द्वारा नकारे हुए नेता जब जा रहे थे तो युवाओं ने उनका सड़क के किनारे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। यह सुबह की घटना थी और उसके बाद जब शाम होती है तो नेता पुलिस थाने में जाते हैं। वहां पर तीन घंटे बैठकर जोर-जबरदस्ती से 21 लड़कों पर एफ0आई0आर0 दर्ज करवाते हैं। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता थाने में जाते हैं और वहां कहते हैं कि आप हमारी भी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हमारे साथ भी बद्तमीजी हुई है और उनके लोगों ने हमारे साथ बद्तमीजी की है। लेकिन पुलिस के अधिकारी ने जो कहा उसकी हमारे पास वीडियो रिकार्डिंग भी है। उन अधिकारियों ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है और

27.3.2017/1615/av/as/3

हम आपकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कर सकते। इस प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार की कानून-व्यवस्था चली है। दूसरा वाक्या, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कूंट में एक लिंक रोड बन रही थी और उसमें हमारे किसी सम्बंधी की मशीन लगी थी। वह अपनी जमीन पर सड़क बना रहे थे। उस जमीन के साथ वहां पर एक नेता का सेब का बगीचा है।

उन्होंने कहा कि मेरे बगीचे के बीच से सड़क निकाली जा रही है। पुलिस ने दबाव में तुरंत एफ0आई0आर0 को बाउंड कर दिया और जे0सी0बी0 के मालिक के ऊपर केस बना दिया। 6 दिन तक जे0सी0बी0 पुलिस थाने में रही और उसके बाद रिलीज हुई। पहली बात तो यह है कि पुलिस बिना डिमार्केशन के किसी की मशीन को हर किसी के कहने पर कैसे जब्त कर सकती है? जब एक साल का समय हो गया और कोर्ट में चालान नहीं गया तो हमने कहा कि चालान क्यों नहीं भेज रहे? उसमें पता चला कि जो डिमार्केशन में जमीन निकली वह उस व्यक्ति की जमीन ही नहीं थी जिसने एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई थी। उसकी जमीन किसी और जगह निकलती थी और पुलिस ने बिना किसी वजह के मशीन को 6 दिन तक थाने में रखा। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह के दबाव में आकर काम करेगी तो कानून-व्यवस्था नाम की चीज कहां हो सकती है? एक दूसरी घटना यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बरसात के दिनों में एक नदी में एक नौजवान लड़का और लड़की की लाशें मिली। दोनों लाशें नग्न अवस्था में थी और उनका सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था।

श्री वर्मा द्वारा जार

27/03/2017/1620/टी0सी0वी0-डी0सी0/1

श्री बलदेव सिंह तोमर..... जारी

उसमें एफ.आई.आर. हुई, पोस्टमार्टम हुआ और लगातार उनके पेरेंट्स माननीय मुख्य मंत्री और पुलिस अधिकारियों से भी मिले। लेकिन आज एक साल के बाद भी कोई पता नहीं लग पाया कि उसमें क्या हुआ? उनके मां-बाप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहती है कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है। उसके बाद जब वे लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले,उनसे बात की और थोड़ा दबाव बनाया गया, तो कहा गया कि आपका केस सी0बी0आई0 को दिया गया है। लेकिन अभी तक भी उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है।

दूसरा, जहां तक ड्रग माफिया और शराब की बात है, माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिंदल जी ने ठीक कहा कि आज हर गांव-गाव में शराब पहुंचाई जा रही है। पहले तो अवैध शराब कुछ प्रमुख स्थानों में मिलती थी, लेकिन आज हर गांव में वह अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे हमारे नौज़वान लड़के इसके शिकार हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। एक तरफ पुलिस जबरदस्ती एफ0आई0आर0 दर्ज़ करती हैं और दूसरे तरफ हमारे यहां 23 फरवरी को एक घटना घटी। जिसमें एक लड़के को पीटा जाता है, उसकी गाड़ी तोड़ी जाती है। वह पुलिस में जाता है कि मेरी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाये। पुलिस एम0एल0सी0 करती है और मैडिकल होता है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज़ नहीं हुई है। उसकी पूरी रिपोर्ट है, अखबारों में उसकी ख़बर लगी है, उसकी गाड़ी पूरी टूटी है, लेकिन वह बड़े नेताओं के बेटे हैं इसलिए उनकी एफ0आई0आर0 आज तक दर्ज़ नहीं हुई है।

दूसरी तरफ हमारे ही जिला में पच्छाद थाने में एस0एच0ओ0 की दादागिरी - तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा एनकाऊंटर भी करवा सकता हूं। आज ऐसी कानून-व्यवस्था हमारे जिला के अंदर चली है। चोरी-डकैती की बात यहां पर कही गई। आज पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम पांवटा थाने में हो रहे हैं। पांवटा थाने के अंदर आज दिन में भी अगर आप अपना घर खाली छोड़कर जाओ या ताला लगाकर जाओ, जब आप 2 घंटे में वापिस आएंगे तो आपके घर के ताले टूटें हुए मिलेंगे और

27/03/2017/1620/टी0सी0वी0-डी0सी0/2

सारे-का सारा घर साफ मिलेगा। पूरे जिला के अंदर चोर-डकैती सबसे ज्यादा पांवटा में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहां पर अवैध खन्न का भी बहुत बड़ा कारोबार है, क्योंकि वहां पर बॉर्डर एरिया है, जो वहां पर नदी है वह उत्तर प्रदेश-उतराखण्ड को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश और उतराखण्ड के बहुत सारे ट्रक्स हमारे यहां पर अवैध खन्न कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो क्रशर लगे हुए हैं, उनको भी चैक करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से भी बहुत-सारा अवैध खन्न हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मैलानी जगह है, जहां फॉरेस्ट का एरिया है और वहां बज़री

निकलती है। पिछले दिनों हमने माइनिंग/फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की तो वहां पर उन्होंने तार-बाड़ कर दिया,लेकिन तार-बाड़ किन की हुई, जो छोटे लोग थे, जो महीने में अपनी रोजी-रोटी के लिए एक-आध ट्रक बज़री का निकालते थे, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा कारोबार करते हैं और खन्न माफिया है, उनका आज भी वहां पर धड़ले से काम चल रहा है और पुलिस प्रशासन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आज जिस तरह से कानून-व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर है, उसके बारे में सभी को चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

27/03/2017/1620/टी0सी0वी0-डी0सी0/3

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय सभापति जी, मांग संख्याः 7 के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। आज हमारी युवा पीड़ी को जो नशा पहुंचाया जा रहा है, प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है। अगर हम प्रदेश का सर्वेक्षण करें तो 20 परसेंट से ज्यादा विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेजों के इसकी चपेट में आ चके हैं। ये किसी भी देश और समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिला ऊना में पहले तो एक ही विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो बॉर्डर एरिया था, वहां ज्यादा घटनाएं होती थी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है।

श्रीमती एन.एस. ....द्वारा जारी।

27/03/2017/1625/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री वीरेन्द्र कंवर ----- जारी

इन घटनाओं में कौन लोग शामिल हैं? पुलिस को भी इसका पूरा पता है। सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव टक्का के अंदर शराब और नशा धड़ल्ले से बिक रहा है। वहां के लोगों ने मेरे से जब इस बात की शिकायत की तो मैंने किसी को भी नहीं बताया और मैंने सिर्फ पुलिस को ही बताया। दूसरे दिन उस व्यक्ति की बात मेरे पास फिर से पहुंच जाती है। सभापति महोदया, इससे यह जाहिर होता है कि किस तरह का नेक्सस पुलिस के साथ बना हुआ है। आज इस बात को चैक करने की जरूरत है कि थाने में कितने लोग या जिला में कितने लोग लम्बे समय से वहां पर बैठे हुए हैं? वही लोग इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जितनी भी कैमिस्ट शॉप्स या दूसरी शॉप्स ले लीजिए, उनमें खांसी की दवाई या कैप्सूल के रूप में नशा सरेआम जिला ऊना के अंदर बिक रहा है। कभी-कभी प्रशासन द्वारा यह पकड़ भी ली जाती है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण उसमें ढील दी जा रही है। अब शराब तो आम बात है लेकिन जो नशीला पदार्थ चिट्टा है यह चिन्ता का विषय बना हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदना करना चाहूंगा कि इसको मज़ाक में मत लीजिए कि माफिया इस तरफ (सत्ता पक्ष) से नहीं उस तरफ (विपक्ष) से है। यह विषय गम्भीरता से लेने वाला है। दूसरा, आज प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म करने की जरूरत है। प्रदेश में वन माफिया भी हावी है। पहले तो वे खैर काटने का परमिट लेते थे लेकिन अब तो परमिट लेने की भी जरूरत नहीं है, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। उसको न तो एक्साईज वाले रोक रहे हैं और न ही फोरेस्ट विभाग वाले उनको रोक रहे हैं तथा न ही पुलिस प्रशासन उनको रोक पा रहा है, चाहे आप इनकी जितनी मर्ज़ी शिकायतें कर दो। अगर आप उनकी शिकायत विभाग के पास करते हैं तो उस व्यकित का फोन शिकायतकर्त्ता को आ जाता है कि आपको क्या तकलीफ है? आज प्रदेश के अंदर यह स्थिति बनी हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री

27/03/2017/1625/ एन0एस0/डी0सी0 /2

जी को चुनौती दे करके कहता हूं कि आप कुटलैहड़ के अंदर पता करवाईये कि जहां-जहां खैर कटे हैं वहां पर एक भी खैर का पेड़ मौजूद नहीं है। इन्होंने सारे के सारे काट दिए

हैं और इनका जड़ कटान कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इनको ठेका दे दिया गया है कि प्रदेश के अंदर जंगल चाहिए ही नहीं। आज ऐसी स्थिति हमारे क्षेत्रों के अंदर है। आज खनन माफिया भी प्रदेश में हावी है। खनन की भी वही हालत है। मेरे क्षेत्र की पलाडा-कोखरा पेयजल योजना पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्योंकि वहां पर खनन वालों ने रेत और बज़री छोड़ी ही नहीं है। पिछले वर्ष मैं जिलाधीश महोदय के पास एक लिस्ट दे करके आया था। मैं अभी तक घर पहुंचा ही नहीं था और उनके फोन आने शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जिलाधीश महोदय ने उनको बता दिया कि आपकी शिकायत विधायक करके गए हैं। आज स्थिति यह है कि पलाडा-कोखरा पेयजल योजना अब दूसरी जगह बनाई गई है। वहां पर बाड़बंदी की गई है। लेकिन लोग उसके अंदर भी घुस करके रेत और बजरी को उठा रहे हैं। अब प्रदेश में खैर और जंगल कट गए हैं लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हैं, वे गर्मियों में जल जायेंगे। पिछले वर्ष भी जंगल जले और इस वर्ष भी उनके जलने की तैयारी है क्योंकि मेरे सब-डिवीजन में एक भी फायर स्टेशन नहीं है।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

27/3/2017/1630/RKS/AG/1

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

श्री वीरेन्द्र कंवर.... जारी

अगर नजदीक में फायर स्टेशन होता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हमारे जिला के अंदर सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब दुर्घटनाएं न हों। मैंने पहले भी इस विषय को माननीय सदन के ध्यान में लाया था। मेरे विधान सभा प्रश्न के

उत्तर में बताया गया कि 2 वर्ष के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें साढ़े चार सौ लोग घायल हुए हैं। ऐसा आंकड़ा था कि उनमें से सवा दौ सौ के करीब लोगों की मौत हो गई हैं। बाहर से यहां पर भीड़ आ रही है। पंजाब से लोग ट्रकों, ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों में यहां पर आते हैं। 8-8, 10-10 मोटर साइकिल झुंड के रूप में आते हैं और उन्होंने अपने मोटर साइकिल के सलैंसर भी खोल दिए होते हैं। उन पर चैक लगाने की जरुरत है। जो ब्लैक स्पोट्र्स हैं, मैंने वहां पर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए निवेदन किया था परन्तु पिछले दो वर्षों में एक भी बात पर अमल नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि वहां पर साइन बोड्र्ज लगाए जाएं या स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं अथवा बंगाणा के ट्रैफिक विंग को स्ट्रैंथन किया जाए। ताकि जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इस प्रदेश के अंदर असमाजिक तत्व धनधना रहे हैं। आज सिर्फ असमाजिक तत्व ही नहीं परन्तु जिला चम्बा के अंदर जहां हमारा बोर्डर एरिया है, वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भटियात क्षेत्र के अंदर समोट-टिक्करी के पास 'पाक' के झंडे लहराए गए। समाचार पत्र में यह आया है कि जिन लोगों ने शिकायत की कि 'पाक' के झंडे लहराए जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त भटियात गांव के अंदर श्री रतन चंद शर्मा जी का मर्डर हुए 8-10 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह की जांच उस ओर नहीं बढ़ी है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था की यह स्थिति है। इसके ऊपर हम हाथ के ऊपर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। अगर ऐसी ही

27/3/2017/1630/RKS/AG/2

स्थिति रही तो जैसे हम अन्य प्रदेशों की और इशारा करते हैं कि वहां की कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वैसे ही यह शांतप्रिय हिमाचल प्रदेश उस ओर आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27/3/2017/1630/RKS/AG/2

अध्यक्षः अब श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। Iwould like that you finish your speech within five minutes.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं जिन बातों के ऊपर यहां पर चर्चा करूंगा, यहां पर चीफ सैक्रेटरी, सैक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल पुलिस बैठे होंगे। लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य कानून-व्यवस्था के संबंद्ध में रखूंगा। मैं जो-जो चीजें यहां पर रखूंगा शायद हो सकता है कि कुल्लू-मनाली में जो कानून-व्यवस्था की स्थिति है उसके बाद तुरंत उन सब लोगों का आज ही पुलिस के द्वारा डराने-धमकाने का प्रयास प्रारम्भ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कुल्लू-मनाली पर्यटन नगरी है। यहां पर देश और दुनिया के लोग घुमने आते हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.03.2017/1635/SLS-AG-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर...जारी

लेकिन इस देवभूमि में गत कुछ वर्षों से देह व्यापार का धंधा बहुत ज़ोरों से चल रहा है और यह कहा जाए कि देह व्यापार के नाम से कुछेक मनाली के बड़े होटल व्यवसायी होंगे और कुछ लोग होंगे जिनसे देह व्यापार का काम चल रहा है। हम यह तो नहीं कह सकते कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। दिन-रात पुलिस के लोग घूमते हैं। फिर कभी-कभी औपचारिकता निभाने के लिए किसी को पकड़ा भी जाता है।

मैं मनाली में रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति नरेन्द्र पाल का नाम लूंगा। विशेष तौर पर डायरैक्टर जनरल पुलिस ध्यान दें। उसकी 13 साल की बेटी थी। वह व्यक्ति कहता है कि मेरी 4 बेटियां हैं। जब 4 बेटियां पैदा हुईं तो मैंने कहा कि बेटा नहीं करूंगा, बेटियों को ही

अच्छे से पालूंगा। मनाली में काम करने वाली किसी महिला ने उस 13 साल की बेटी का संबंध किसी 25-26 साल की उम्र के एक व्यक्ति से करवा दिया। माता-पिता ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस स्टेशन ले गए। जब पुलिस स्टेशन ले गए तो जो महिला यह काम करवाने वाली थी, उसको पुलिस इंस्पैक्टर ने कुर्सी पर बिठाया। जो 25-26 साल का लड़का साथ पकड़ा, उसको भी कुर्सी पर बिठाया। वह 13 साल की लड़की भी कुर्सी पर बिठाई और लड़की के माता-पिता, दोनों को साथ में खड़ा रख कर एक अपराधी की तरह उनसे डांट-फटकार की। कहा - तुम बच्चों को तो संभालते नहीं। लड़की को कहा कि तूने जो करना तू कर ले, अगर तुझे ये कभी तंग करेंगे तो तेरे मां-बाप, दोनों को अंदर ठोक दूंगा। उस व्यक्ति ने लिखकर भी दिया और वह कई जगह भटकता रहा। लेकिन अंततः दो साल बीत जाने पर वह यह कहता है कि मेरे घर की हालत अगर आज खराब है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेवार है।

ऐसी अनेक घटनाएं हैं। हम इन घटनाओं के बारे में कहते नहीं थे क्योंकि हमें लगता था कि सुधार आएगा लेकिन सुधार नहीं हुआ।

27.03.2017/1635/SLS-AG-2

इसके बाद दूसरी घटना है। अभी हाल ही में मनाली हॉस्पिटल में एक महिला आई। डॉक्टर को चैक अप करवाया। वह मनाली के सनाध गांव से है। हॉस्पिटल में एक नर्स खड़ी थी। डॉक्टर ने उस महिला को कहा कि आपको इंजैक्शन लगा दिया है फिर भी आप इतनी घबराई क्यों है? आपको कोई बीमारी नहीं है। बाहर आकर जब उस नर्स ने पूछा कि तू इतनी क्यों घबराई है, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू 28-29 साल की जवान लड़की है तो उस लड़की के मुंह से निकला कि मेरे हसबैंड के पास टवेरा गाड़ी है। पिछले कल पुलिस स्टेशन के आगे से उसकी गाड़ी जा रही थी। वहां अंदर से एस.एच.ओ. की पत्नी का कुत्ता निकला और अचानक गाड़ी के नीचे आने के कारण मर गया। पुलिस वाले उस व्यक्ति को

थाने के अंदर ले गए। वहां वह प्यार तो करेंगे नहीं! उसके बाद उस व्यक्ति से कहा कि तू इस कुत्ते के बदले मुझे ऐसा ही कुत्ता लाकर दे। उस व्यक्ति ने मण्डी से खरीद कर बदले में दो कुत्ते दिए। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी घबराया है। यह ख़बर मुझे उड़ती-उड़ती मिली। जब किसी के ज़रिए पता किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस झमेले में मत डालो। मेरी पत्नी के मुंह से यह कैसे निकल गया और बात कहां-से-कहां पहुंच गई। मुझे इस पंगे में मत डालो। मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, मुझे सड़क पर चलना है, मैं पुलिस से पंगा नहीं ले सकता। यह तथ्य है।

तीसरा वाक्या है। एक महिला बाजार में घूम रही थी और पीछे से आकर 3-4 महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। लेकिन पुलिस ने उस पिटाई वाली महिला को सामने कुर्सी पर बिठाकर बड़ी देर तक समझाने की बात कही। वह महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। उसका नाम प्रेमलता है। जब उसने कहा कि मुझे पीछे से आकर मारा है, आप कुछ तो करो, तो उन्होंने कहा कि तू ज्यादा बोलती है, जैसी तेरी जात - वैसी तेरी औक़ात। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के न जाने कितने घटनाक्रम हुए हैं।

एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नेता है जिसने कुल्लू विधान सभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा है। मनाली में ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास एक ऑप्रेटर, एक छोटा आदमी काम

27.03.2017/1635/SLS-AG-3

करता है जो ऑटो वाला है। उसने केवल मात्र इतना कहा - रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग। अब व्यक्ति शराब पीकर निकल रहा था। जब रोहतांग, रोहतांग कहा तो उसने कहा कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। उसने कहा, मैं नहीं जानता। शक्ल सूरत देखकर लगता है कि कोई टूरिस्ट होगा। फिर उसको घसीट कर ले गए। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अंदर उसको 2-4 थप्पड़ मारे।

जारी..श्री गर्ग जी

27/03/2017/1640/RG/AS/1
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर---जारी

तो यह कानून-व्यवस्था की स्थिति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। रात को 1.30-2.00 बजे टैक्सी ऑपरेटर्ज पुलिस स्टेशन गए कि कोई कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी स्थिति है। अब मैं आपको आगे एक और जानकारी देता हूं। जब इन सब बातों को हमने उठाना प्रारम्भ किया, तब उनका एक और कहना हो गया कि अब तो विधायक का नंबर भी लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, 5 मई, 2016 की एक घटना है। उस दिन लगभग 40 ऐसी महिलाएं जो रेहड़ी-फड़ी का काम करती हैं, सुधीर जी ने लिस्ट दी है उसमें सबका नाम है, लेकिन वर्तमान में वे रहेड़ी लगा नहीं पा रही हैं और लिस्ट में कहा गया है कि हमने परमीशन दे दी है। जिस जगह पर वे महिलाएं अपना कारोबार करती थीं, उस जगह की ऑक्शन की और उसके बाद जब वहां रोजगार खदेड़ा जा रहा था, तो क्या वे महिलाएं इतनी बड़ी अपराधी थीं कि पुलिस 12.00 बजे से लेकर शाम 7.00 तक कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए वहां खड़ी रही? वहां मई का पर्यटन सीजन था, दूसरे एन.जी.टी. की मीटिंग थी और पुलिस के अधिकारी एन.जी.टी. की मीटिंग छोड़कर वहां खड़े थे। शाम के 6.00 बजे जब मैं वहां से गुजरा, तो मैंने देखा कि महिलाओं को दिनभर खदेड़ा गया था। मैं अकेला था। वे सब मेरे पास आकर खड़ी हो गईं और कहने लगीं कि पूरे दिन पुलिस और नगर परिषद ने हमें बहुत तंग किया। उनको दिनभर का गुस्सा था इसलिए उन्होंने कुछ नारेबाजी भी की। अन्ततः जब वहां से लोग वापस जाने लगे। यहां तक की हालत क्या हो गई कि एक महिला को मेरे सामने मॉ-बहिन की गाली दी, कहां कि मैं तुझे थप्पड़ मारुंगा। केवल मात्र मैंने अकेले विधायक ने कहा कि हमारे सामने आप हमारी माताओं-बहिनों को ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर उसने कहा कि आप एम.एल.ए. हैं, पढ़े-लिखे होंगे, मैं ऐसा नहीं करुंगा, वैसा नहीं करुंगा। एफ.आई.आर. कराई, 9 लोगों पर एफ.आई.आर. की, दो हम हैं, 6 महिलाएं हैं और वे सब अनुसूचित जाति की हैं। उसके अगले दिन जब 2000

लोगों ने थाने का घेराव किया, कोई भी कानून नहीं तोड़ा, केवल मात्र शहर में चक्कर मारकर आए। उसके बाद कितनी ज्यादती हुई?

Speaker: Please, wind up.

27/03/2017/1640/RG/AS/2

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : बस मैं समाप्त कर रहा हूं। 30 महिलाओं ने डी.एस.पी., मनाली को प्रार्थना-पत्र दिया कि एस.एच.ओ. ने हमसे दुर्व्यवहार किया। लेकिन उसकी कोई एफ.आई.आर. लॉज़ नहीं हुई और न ही कोई ऐक्शन लिया गया। यहां तक जब एक विधायक ने डी.एस.पी. को लिखकर भेजा कि इस पर कोई कार्रवाई करो, हमसे भी दुर्व्यवहार हुआ है। अब जाकर यानि कई महीनों बाद क्या जवाब आता है कि उनको क्लीन चिट दे दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें। Please, wind up.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहूंगा। जब प्रदेश सरकार के विरूद्ध कोई कुछ कहता है या उसका पुतला दहन किया जाता है, तो सब लोगों पर एफ.आई.आर. होती है और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी का कुल्लू, मनाली, पतलीकूहल में पुतला फूंका गया, तो पुलिस ने कोई एफ.आई.आर. लॉज नहीं की। आखिर यह दोहरा मापदण्ड क्यों? अन्त में एक बात कहूंगा। ड्रग माफिया के बारे में आज का समाचार छपा है कि '28 किलो के साथ कुल्लू का एक नौजवान दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा।' नगर में एक विदेशी को चरस का तेल निकालने के लिए पकड़ा। वह कब से यह काम कर रहा था। आज भी लोग एक बात शिवरात्रि के बारे में कहते हैं कि मैंने कहा खूब भांग पी, लेकिन यह भांग कहां से देते हैं? तो वे कहते हैं कि जब मिलती नहीं है, तो पुलिस स्टेशन से लाकर हम देते हैं। वन माफिया का हाल वही है। 400 पेड़ों का अवैध कटान हुआ, लेकिन पकड़ा कौन गया? एक मामूली चौकीदार जिसका घर भी पूरा नहीं है।

Speaker : Please wind up, I will not allow.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन बिन्दुओं पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

27/03/2017/1640/RG/AS/3

अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह, श्री सुरेश भारद्वाज, डॉ. राजीव बिन्दल, श्री रिखी राम कौंडल, श्री जय राम ठाकुर, श्री बलदेव सिंह तोमर, श्री वीरेन्द्र कंवर और श्री गोविन्द ठाकुर ने जो यहां चर्चा की है अब उसका माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

एम.एस. द्वारा जारी

27/3/2017/1645/MS/AS/1

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, many Hon'ble Speakers have spoken that Law & Order is lax, crime rate has risen, smuggling has increased and so on. I want to say that the figures are otherwise. As compared to the earlier years, the crime rate has gone down and the cases which are registered that have been acted upon and the guilty people have been sentenced or are under appeal. This is the factual position. The Government is very aware of this entire matter. Similarly, so far as the drug trade is concerned, smuggling of drugs are concerned, we are conscious of it. It is a constant struggle. We have to vision every day about it. We have been able to arrest many people who are indulging in the smuggling or in supplying of drugs in the Himachal Pradesh

and they are facing trial. Some has gone to Jail, some are under trial. I am satisfied that the Police is doing its best to see the drug racket is smashed in Himachal Pradesh. I don't say, I never claim that we have been able to smash this drug trade hundred percent in the State. But the vigorous action taken by the Law & Order agencies has shown good results. Due to which the smugglers, who were free to enter Himachal Pradesh and do whatever they wanted, is now decreased. I don't say it has totally been eliminated but it has decreased substantially. On the border with Punjab and Haryana we are vigilant about it. So many people have been caught, arrested and they are also facing trial. So much so that our Police even cross over to Punjab area and smashed the places from where they were supplying drugs on the border area and due to which the smuggling of narcotics, medicines and drugs have been eliminated from that area. But the factual position is that this requires constant vision. With the

27/3/2017/1645/MS/AS/2

change of Government in Punjab, the new Government of Punjab is taking action against the drug mafia in Punjab and our operation has further eased because of that. Earlier the smugglers of Punjab area used to enter in Himachal Pradesh to do smuggling from one place to another without any fear. They had the patronage to do it. But with the change of Government in Punjab, the Punjab Government has now taken action against all the drug mafias there and due to that our task here has been also lessened to a great extent.

Continue in Hindi by JS

27.03.2017/1650/जेके/डीसी/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी-----

जैसे पहले खुल कर आते थे अब इतनी तादाद में नहीं आते हैं। आते हैं मगर इतनी तादाद में नहीं आते हैं। इस तादाद में पहले पंजाब के ड्रग, स्मगलर और जो नारकोटिक्स की हमारे यहां पर स्मगलिंग होती थी उसमें बहुत कमी आई है। मगर हमें फिर भी विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, चौकस रहने की आवश्यकता है ताकि कोई एक भी व्यक्ति जो ड्रग्ज लेकर हिमाचल आता है वह यहां पर पकड़ा जाए और उसके कार्यभार को खत्म किया जा सके। वह तो नेटवर्क होता है। हमारे यहां भी नेटवर्क होता है जिसमें नोज़वान लड़के हैं, बेरोजगार लोग है उसमें हिमाचल के लोग हैं जिनको वे अंगेंज करते हैं। जिनके जरिए वे लोग स्मगलिंग करते हैं। उनको पकड़ा गया है। मैं यहां पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। मुझे यह पता है कि वे कौन हैं? जो पकड़े गए वे कौन हैं? उनके घर के पते भी हमें मालूम है। हमें यह भी पता है कि वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। यह सब पता है। हम उस वक्त तक जब तक उनको अदालत में सजा नहीं हो जाती we are not able to reveal the names. कानून-व्यवस्था पहले से बेहतर है। निरन्तर यहां पर चौकसी रखी जा रही है। कई दफा जब सजाएं होती हैं और ज्यादा लोगा कन्विक्ट होते हैं उसका यह मतलब नहीं है कि कानून व्यवस्था खराब हुई है या पहले से ज्यादा क्राइम हुए हैं। इसका यह कारण है कि better investigation and vision of Police in the matters, we have more conviction rate now than earlier. जो पहले छूट जाते थे आज वे पुलिस की पकड़ में आते हैं और अदालतों में जाते हैं फिर उनको कन्विक्शन होती है। अगर कन्विक्शन रेट बढ़ती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा क्राईम हो रहा है। It shows better investigation, better co-ordination and cases are properly prepared which results in convictions. यह मैं आपको कहना चाहता हूं। जहां तक ड्रग मैन्ज़ की बात है, we have to be vigilant. अभी किसी ने पंजाब हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया कि पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने एफिडेविट दिया कि जो

ड्रग्ज है वह कहीं नाहन से आ रही है। मगर उसी एफिडेविट में नीचे यह लिखा गया है कि हमने इन्वैस्टिगेशन किया कि जो नाम व पता दिया गया था कि फ्लां जगह से ड्रग लिया है।

27.03.2017/1650/जेके/डीसी/2

पांवटा साहिब में वहां तहकीकात करने पर ऐसी कोई कम्पनी नहीं पाई गई। आपने सलैक्टिव फिगर बताई है। उसी एफिडेविट में ऊपर कहा है कि हिमाचल प्रदेश से यह ड्रग आता है उसके बारे में तो आप कह रहे हैं और उसी एफिडेविट में नीचे जो कहा है 'on investigation, we did not find any such company', जो कि वहां पर मैंशन की गई है। यह बात है। मैं नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश से ड्रग स्मगलिंग नहीं हो रही है। हो रही होगी मगर उसमें रोक लगी है। अब लोग पहले से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि आज पुलिस विजिलेंट की वजह से वे डरते हैं कि पकड़े जाएंगे। हम छूटेंगे नहीं और हमको सजा होगी। यहां पर अभी होम गार्डज के बारे में कहा गया कि होम गार्डज को वेतन कम मिलता है। यह गलत बात है। होम गार्डज को वही वेतन मिलता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। उसी तारीख से नया वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको यहां पर मिल रहा है। आपने यहां पर कहा कि कॉंट्रैक्ट के ऊपर पुलिस रखी गई है। वह गलत है। There is no question of that. जो पुलिस भर्ती होती है उनका पे स्केल जो पुलिस का होता है उसके मुताबिक ही उनको वेतन मिलता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

27.03.2017/1655/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

पुलिस में कोई कंट्रेक्ट पर नहीं रखा जाता। कई विभागों में इस वक्त कई लोग कंट्रेक्ट पर काम करते हैं, उस व्यवस्था को भी हम धीरे-धीरे खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग जो कंट्रेक्ट पर हैं उनको रेगुलर किया जा रहा है और इस व्यवस्था को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यह व्यवस्था आज की नहीं है बल्कि पहले से चल रही है। इसी तरह से

पुलिस के अंदर मैं कैटेगॉरिकली कहना चाहता हूं कि all the constables are regular, nobody is taken on Contract Basis. अभी स्पैसिफिक केसिज़ बताए गए, वे नोट कर लिये गए हैं। **We will see. I am sure that many of these cases mentioned by the Hon'ble Members are already under investigation . मगर अगर नहीं हैं तो हम देखेंगे कि जो मामले यहां पर स्पैसिफिकली आपने बताए हैं they will be looked into; investigated and जो गिल्टी होगा, उसको निश्चित रूप से कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी।** वैसे तो मैंने लम्बी स्पीच तैयार की थी giving facts and figures of everything but in totality I conclude by saying that Law and Order is in control and Police has been able to contain crime. The criminals and people those who are indulged in crime are facing the consequences of law. ये मैं आपको कहना चाहता हूं। The performance of the Police has increased and is much better than earlier time. I am satisfied with this. At the same time there is need for more vigilance. यह कहना काफी नहीं है कि पुलिस क्राइम काबू में है, इसके लिए बराबर 24 घंटे चौकसी की ज़रूरत है। विजीलैंस की ज़रूरत है। सतर्क होने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि हम कानून-व्यवस्था को कायम रखें। स्मलिंग किसी भी प्रकार की है चाहे वह चरस की हो या किसी और चीज़ की हो, उसको सख्ती से रोका जाए। ड्रग्ज़ जो स्टेट के अंदर आते हैं उनको रोका ही नहीं जाए बल्कि जो उसमें संलिप्त हैं चाहे वे हिमाचल के लोग हैं या चाहे बाहर के लोग हैं उन सबको सख्त-से-सख्त सजा मिले। उनको पकड़ा जाए, और भी ज्यादा चौकसी के साथ पकड़ा जाए, यह पुलिस का ध्येय है।

27.03.2017/1655/SS-DC/2

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं कि Law and Order is proper, there is no decline in the Law and Order situation. In fact I have got all figures with me which I can quote hereby कि किस वर्ष में कितने क्राइम हुए हैं, कैसे-कैसे क्राइम हुए हैं। उनको देखकर मालूम होता

है कि there has been substantial decline in crime and specially there had been better investigation of cases and more people have been convicted for the crimes.

Regarding law and order situation in the State, I would like to say that the law and order situation in the State is fully under control. The Government is committed to the safety of properties of the residents of the State and their security.

During the last ten years the most crime prone year was 2011 when 18,875 criminal cases were registered. In the last four years (2013-2016) a total of 67325 cases have been registered whereas in comparison during the period 2009-2012, a total of 69,039 cases were registered which is 1714 more than the last four years.

Annual average registration of crime for the period 2008-2012 was 17416 whereas for the period 2013-2016 it was 16831.

During the last four years the State witnesses a total of 442 murders, whereas during the preceding four years the figure was 498. During 2013-2016 the average annual murder reported was 110, whereas during 2008-2012 the annual average was 125 murders. As is evident the last four years have seen a significant reduction in murders in the State.

27.03.2017/1655/SS-DC/3

Culpable homicide during the last four years was 25, whereas in the preceding four years there were 35 cases. We have seen reduction of 28 per cent under this head.

During last four years a total of 2501 cases of thefts were registered whereas during the preceding four years, the figures were 3470. During 2013 to 2016 the

annual average of theft cases was 625, whereas during 2008 to 2012 the annual average was 924, which shows drastic reduction in the theft cases during last four years.

During last four years a total of 2811 cases of burglaries were registered, whereas during the preceding four years, the number of burglaries were 3152. During 2013 to 2016 the annual average of burglary cases was 702, whereas during 2008 to 2012 the annual average was 785. Thus significant reduction in burglaries was witnessed during the last four years.

During last four year a total of 4,463 cases of Hurt and Rioting were registered whereas during the preceding four years, the figures of cases under these heads were 5,503. During 2013 to 2016 the annual average of Hurt and Rioting cases was 1,115, whereas during 2008 to 2012 the annual average was 1,393. This also shows reduction in the Hurt and Rioting case during last four years.

Government is particularly conscious of the security of women. Due to our efforts like opening 5 Women Police Stations and posting of women in every police station a sense of security to the women of the State has been achieved encouraging them to report crimes freely.

Effective crackdown against the forest smugglers, mining mafia and smugglers of illicit liquor have shows remarkable results. A huge increase in the number of case have been achieved.

During last four years a total of 2,726 cases under ND&PS Act were registered whereas during the preceding four years, there were 2,152 cases. During 2013

27.03.2017/1655/SS-DC/4

to 2016 the annual average of ND&PS cases was 681, whereas during 2008 to 2012 the annual average was 505. As is evident the last four years have seen a significant increase (27%) in the registration of cases under ND&PS Act. Strengthening of the Narcotics Wing and effective policing has led to increase

in the detection of cases under ND&PS Act during the last 4 years. Special drives in our border areas have also been very effective.

During last four years1332.8 Kg Charas, 41.9 Kg Opium, 4309 Kg Poppy husk, 94.6 Kg Ganja, 2,37,091 capsules, 3,20,147 tablets and 15,551 bottles of syrup have been seized from 3162 accused (3134 Indian and 28 foreigner) .

During last four years a total 23,162 Challans under Mines & Minerals Act have been made and fine of Rs. 10.78 crores realized from the offenders, whereas during preceding four years the number of challans were 4,782 and fine was Rs. 1.80 Crore. During 2013 to 2016 the annual average of challans under Mines & Minerals Act were 5,790, whereas during 2009 to 2012 the annual average was 1,195. During 2013 to 2016 the annual average of fine under Mines & Minerals Act was Rs. 2.69 crores, where during 2009 to 2012, the annual average of fine was 0.45 crores. Thus there was significant increase in the action under Mines & Minerals Act during last four years.

Himachal Pradesh has excelled in the implementation of the Crime & Criminal Tracking Networking System as compared to the other states. CCTNS has been implemented in all 127 police stations of the State which will help in the detection and investigation of crime in future. Under this system many online facilities are being provided to the general public which includes registration of FIRs through the police posts.

Steps have been taken to fill up vacancies in the police at all ranks.

06 new police stations (i.e 05 Women Police Stations in Shimla, Kangra, Mandi, Kullu and Baddi and 01 Cyber Police Station at Shimla) have been created.

27.03.2017/1655/SS-DC/5

06 Police Posts have been upgraded as full-fledged Police Stations and 14 new Police Posts have been created.

04 SDPO offices at Jawalaji, Haroli, Padhar and Bhawanagar have been created in the state.

During year 2015, 800 posts of constables have been filled up.

During year 2016, 1500 posts of constables (i.e. 1200 Male and 300 Female) have been filled up. Recruitment process has been completed and their basic training is on.

In order to achieve the goal of 20% women in HP Police, 16 Female Sub-Inspectors have been recruited during 2016.

27 new light vehicles and 33 motor cycles were purchased to improve mobility of our police. During current year, proposals for providing Rs. 6.50 crores (5.85 crores Central Share plus (+) 0.65 crores State Share) under Modernization of Police Forces have been approved by the Governmnet of India. Out of Rs. 5.85 crores of Central share, Rs. 0.44 crore has been released to OFB for weapons and Rs. 4.95 crore released to the State Government. The matter is under consideration for obtaining budgetary support, and administrative approval & expenditure sanction for this amount.

We have continuously tried to modernize our police force with respect to training as well as technical capabilities.

Crime is at its lowest in the last 4 years and the people feel safe and secure due to effective enforcement of law.

Regarding Fire Department, I would like to say that during last 4 years since this Government has come into power:

18 new Fire Posts have been established and made functional in the State.

175 posts of Firemen, 25 posts of Leading Firemen, 54 posts of Driver-cum-Pump Operator have been created/ sanctioned.

27.03.2017/1655/SS-DC/6

36 new Fire Fighting Vehicles have been purchased in order to strengthen the Fire Services in the State.

During the period from 2013-2016 the State Government has sanctioned an amount of Rs.11.52 Crore for purchasing Fire Fighting Equipments and Vehicles.

During the year 2016, 2760 fire incidents were attended and 320 Rescue calls were received by the Fire Services Department throughout the State. With the best efforts of the department, the property worth Rs. 94.53 Crore approximately has been saved in the State.

In Baddi, Mandi, Manali and Kangra the work of construction of new Fire Buildings are under active process. For the Financial Year 2017-18 approximately Rs. 50.87 Crore have been kept in various heads of Fire Department.

The State Government is considering to open five new Fire Posts at Kawar, Dadda-Sibha, Patlikulh, Karsog and Shillai during the Financial Year 2017-18.

The State Government is determined to fill up 30 posts of Firemen and 35 posts of Driver-cum- Pump Operator during the Financial Year 2017-18.

In view of above it will not be appropriate, in the public interest, to cut the budget of the Department of Fire Services.

Regarding Home Guards Department, I would like to say that during the last 4 years since this Government has come into power:

A Company Comprising of 99 Home Guards Volunteers was opened at Chopal Sub Division in September,2014.

The remuneration of Home Guard volunteers has been enhanced from Rs. 225/- to Rs. 592/- on which an expenditure of Rs. 118 crore was incurred.

The Department has procured 4 Rescue Vans to be stationed at Mandi, Dharamshala, Shimla and Chamba.

27.03.2017/1655/SS-DC/7

The Department has also procured 08 Motorcycles and 12 Bolero Jeeps.

In pursuance of the role of Home Guards organization, the department has been undertaking socio-economic and welfare activities in the State such as cleanliness drives, blood donation camps and disasters training camps from time to time.

02 buildings comprising of administrative block and barrack block have been constructed at Central Training Institute Sargheen, Shimla. The construction of Hostel block has started and construction of residential block will be started soon at the same institute.

The construction of Battalions Office buildings has started or will be started soon at the following places:

1. 7th BN. Kullu.(work in progress)
2. 8th BN.Chamba.
3. 10th BN. Hamirpur
4. 11th BN. Solan (work in progress)
5. 12th BN. Una.
6. Company office building at Karsog
7. 11th Battalion Training Centre premises at Kunihar

The services of Home Guard volunteers have been utilized during the Lok Sabha & Vidhan Sabah Elections outside the State at Karnatakka, Delhi, Haryana and Uttrakhand etc.

For the Financial Year 2017-18 approximately 41.87 Crore have been kept in various heads of Home Guards and Civil Defence Department.

In view of above it will not be appropriate, in the public interest, to cut the budget of the Department of Home Guards and Civil Defence.

Thank you very much, Sir. इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लें।

27.03.2017/1655/SS-DC/8

अध्यक्षः तो माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, विपक्ष की तरफ से विभिन्न माननीय सदस्यों ने वर्तमान सरकार में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और जो अनेकों घोटाले हुए हैं उनकी बात कही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका सही उत्तर नहीं दिया है इस करके हम अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्षः क्या आप (श्री महेन्द्र सिंह) सब की ओर से बोल रहे हैं या अपनी ओर से बोल रहे हैं?

माननीय सदस्यगण (विपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सब की ओर से।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2017/1700/केएस/एजी/1

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, डॉ0 राजीव बिन्दल, रिखी राम कौंडल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर और श्री वीरेन्द्र कंवर के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

(प्रस्ताव गिर गया)
(कटौती प्रस्ताव अस्वीकार)

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-7 पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अन्तर्गत राजस्व और

पूंजी के निमित्त क्रमशः 11,11,98,66,000 एवं 45,35,00,000 रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

27.03.2017/1700/केएस/एजी/2

मांग संख्या- 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

अध्यक्षः अब मैं मांग संख्या- 9 जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित है, को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त क्रमशः मु0 16,01,65,30,000 एवं 67,28,00,000/- रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

इस पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, डॉ0 राजीव बिन्दल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर, गोविन्द राम शर्मा और श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी की ओर से छः कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं उन्हें इनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं?

माननीय सदस्यगणः प्रस्तुत हुआ समझें।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ समझे गए जो इस प्रकार हैः-

<u>मांग संख्याः 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</u>

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्याः

<u>नीति का अननुमोदन</u> 9

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

27.03.2017/1700/केएस/एजी/3

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री महेश्वर सिंह,
डॉ0 राजीव बिन्दल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
श्री गोविन्द राम शर्मा,
श्री कृष्ण लाल ठाकुर।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।

2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन।

3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन।

4. सरकार की प्रदेश में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोलने की नीति का अननुमोदन।

2. <u>सांकेतिक कटौती</u>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

27.03.2017/1700/केएस/एजी/4

श्री महेन्द्र सिंहः

1. मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तीरा, मनदीप एवं चौलथरा के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता ।

2. मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि को सदुपयोग न कर पाने में सरकार की असफलता ।

अध्यक्ष : मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं। इसमें सर्वप्रथम श्री महेन्द्र सिंह जी से आग्रह करुंगा कि वे चर्चा में भाग लें लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संक्षेप में बोलें ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिले और जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव पर फैसला किया जाए।

27.03.2017/1700/केएस/एजी/5

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-9 पर जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने दिया हुआ है, कटौती प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से ही होते हैं।

कितना समय बोलना है, कितना नहीं बोलना है, वैसे इस पर तो पाबन्दी नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी आपने जो आदेश किए हैं, इनकी अनुपालना की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग हमारे प्रदेश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो जनाज़ा इन साढ़े चार सालों में निकला है, उससे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश जहां ऐसा कभी नहीं हुआ करता था कि हमारे जो पी.एच.सीज़. हैं, सब सैंटर्ज़ हैं, सी.एच.सीज़ हैं, रूरल हॉस्पिटल्ज़ हैं, रैफरल हॉस्पिटल्ज़ हैं, सिविल हॉस्पिटल्ज़ व अन्य बड़े-बड़े हॉस्पिटल्ज़ हैं, उन सभी की आज ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर पैदा हो चुकी है कि केवल मात्र रैफर का काम शुरू हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मुख्य मंत्री जी अनेकों जगह नई-नई संस्थाएं खोलने जा रहे हैं और जो नए संस्थान खुलते हैं वहां पर रेश्नेलाइजेशन से डॉक्टर लगाए जा रहे हैं, कहीं पैरा मैडिकल स्टाफ के लोग लगाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पी.एच.सीज़. हैं जिनके पास अपने भवन नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी....

27.3.2017/1705/av/ag/1

श्री महेन्द्र सिंह---------- जारी

बहुत सारे ऐसे पी0एच0सीज0 हैं जो छोटे-छोटे खोको में चले हुए हैं। जब खोको में पी0एच0सीज0 चलेंगे और वहां पर डॉक्टर / पैरा मैडिकल स्टाफ के बैठने का स्थान नहीं होगा, दवाइयां या दूसरे उपकरण नहीं होंगे तो हम यह कैसे महसूस कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता कर रहा है। प्रदेश में अनेकों ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनके भवनों का निर्माण कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था। लेकिन साढ़े चार साल का वक्त बीत गया और इतना समय बीत जाने के बाद भी उन संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी बताएं कि

उन संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम इतनी दवाइयां मुफ्त में दे रहे हैं और कोई स्वास्थ्य संस्थान ऐसा नहीं है जहां पर दवाइयों की कमी है। आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति है, विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी स्वास्थ्य इकाइयां हैं वहां पर केवल दवाइयों का ही अभाव नहीं बल्कि वहां पर तो न डॉक्टर है, न नर्स है और न कोई फार्मासिस्ट है। कुछ पी0एच0सीज ऐसे हैं जहां पर चपड़ासी भी नहीं है। (---व्यवधान---) मैं पी0एच0सी0 चोलगढ़ की बात कर रहा हूं। प्रदेश के अंदर जहां-जहां पर स्वास्थ्य संस्थान हैं वहां उनके चारों ओर गंदगी-ही-गंदगी है। आज पूरे प्रदेश और देश में माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ अभियान चलाया हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थान ऐसे हैं जहां उनके चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपने तो कई स्वास्थ्य संस्थानों में अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए कुछ स्टाफ आउट सोर्स किया हुआ है। आज प्रदेश के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर जो आउट सोर्स करके भर्तियां की हुई हैं उसके क्या कारण है? इन संस्थानों के अंदर अगर हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की विधिवत रूप से भर्ती की गई होती तो

27.3.2017/1705/av/ag/2

अच्छा होता लेकिन आप आउट सोर्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रदेश में डॉक्टर्स और पैरा मैडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। इस बारे में इसी हाऊस में मेरा प्रश्न लगा था। उस प्रश्न के उत्तर में आपने माना है कि इस प्रदेश में डॉक्टर और पैरा मैडिकल स्टाफ की 10091 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। एक छोटे से प्रदेश के अंदर अगर स्वास्थ्य विभाग में 10091 पोस्टें खाली पड़ी हो तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ठीक तरीके से चला हुआ है। माननीय मंत्री जी, आपको भारत सरकार से पैसा मिल रहा है। आपको नेशनल रूरल हैल्थ मिशन का पैसा आ रहा है। आपको इस साल के लिए 330 करोड़ रुपये की राशि आई है जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए हाइएस्ट अमाऊंट है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 60.50 करोड़ रुपये जो भारत सरकार ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने यहां हिमाचल प्रदेश के मरीजों के लिए फ्री ऑफ

कॉस्ट दवाइयां देने के लिए दिया है, उन पैंसों से आपने कितनी दवाइयां खरीदी है? अगर उन पैंसों से दवाइयां खरीदी है तो उन दवाइयों का आपने कहां-कहां आबंटन किया है? यहां पर इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं क्योंकि आप कहते हैं कि हम प्रदेश में अच्छे-अच्छे मैडिकल संस्थान खोल रहे हैं। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को तीन मैडिकल संस्थान दिए हुए हैं। उन तीन मैडिकल कालेज में केवल नाहन का मैडिकल कालेज चलना शुरू हुआ है। हमीरपुर और चम्बा का मैडिकल कालेज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार प्रति मैडिकल कालेज के लिए दो-दो सौ करोड़ रुपये देने के लिए तैयार बैठी हुई है लेकिन यहां से डी0पी0आर0 कौन भेजेगा? वह डी0पी0आर0 हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भेजनी है। यहां से डी0पी0आर0 जायेगी तब जाकर हमारे प्रदेश को भारत सरकार से धनराशि मिलेगी लेकिन आप डी0पी0आर0 नहीं भेज रहे हैं। यहां शिमला कैंसर युनिट और मंडी कैंसर युनिट के लिए पैसा दिया हुआ है। बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि मण्डी आपका गृह जिला है, गृह जिला होने के बावजूद भी आप वहां के बारे में नहीं सोचते। भारत सरकार की तरफ से, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी कि तरफ से कैंसर युनिट के लिए पैसा आ रहा है मगर

श्री वर्मा द्वारा जारी

27/03/2017/1710/टी0सी0वी0-ए0एस0/1

श्री महेन्द्र सिंह ..... जारी

आप उसकी डी0पी0आर नहीं भेज रहे हैं, आप उसको ठण्ड़े बस्ते में डाल रहे हैं। कभी कहते है, हमारे पास यहां जगह नहीं है, कभी कहते हैं, हमारे पास वहां जगह नहीं हैं। कभी कहते हैं हम इसको नेर चौक में खोलेंगे और कभी कहते हैं मंगरोटू में खोलेंगे। अगर उसकी डी0पी0आर0 जाती तो जितनी आप डी0पी0आर0 बनाकर भेजते, भारत सरकार उतना पैसा आपको देने के लिए तैयार थी। हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार की तरफ से ट्रामा सेंटर मिले हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए और भी अनेकों स्कीमों के लिए धनराशि भारत सरकार की ओर से मिली हुई है, लेकिन माननीय मंत्री जी आप भारत सरकार के दिए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहते हैं। आप भारत सरकार की दी हुई

योजना को हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित नहीं करना चाहते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरा काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि जब-जब भी आप जिस मंत्रालय के मंत्री बनते हैं, वहां पर आप कुछ-न-कुछ नया काम करके जाते हैं। आपने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आई0जी0एम0सी0 में स्थान दे दिया। आपने एक मांडव कंपनी को यहां पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की अनुमति दे दी। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वही मांडव इंडस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 'डी टाईप' का सिलेंडर 160 रूपये में टांडा मेडिकल कॉलेज में देती है, वही मांडव इंडस्स्ट्री दूसरे हॉस्पिटल में डी- टाईप का सिलेंडर 175 रूपये में देती है। वही मांडव इंडस्ट्री जो आपके आई0जी0एम0सी0 और तीन हॉस्पिटल्स के लिए 205 रूपये में डी टाईप का सिलेंडर देती है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आपसे पूछ रही है। आप उनको प्लांट लगाने के लिए जगह दे रहे हैं, आप उनको हर प्रकार की सुविधा आई0जी0एम0सी0 में दे रहे हैं। लेकिन आपने वहां जो 160-175 और 205 रूपये का सिलेंडर मिलता था, आपने उसको मांडव इंडस्ट्री को आई0जी0एम0सी0 में 255 रूपये कर दिया। इस प्रकार की अनेकों दूसरी सप्लाई आप उनसे ले रहे हैं। इसके लिए जो टेंडर हुआ है उसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि ठाकुर कौल सिंह जी जो अनियमितताएं आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुई है --- (व्यवधान)--- ये प्रश्नों के उत्तर हैं, ये महेन्द्र सिंह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमने प्रश्न किए हुए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर हैं और उन उत्तरों में लिखा हुआ

27/03/2017/1710/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

है, न कि महेन्द्र सिंह अपनी ओर से बोल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप धर्मपुर गए थे, आपने धर्मपुर का एक दिन का दौरा किया था। आप वहां पर अनेकों घोषणाएं करके आ गए कि हम सिविल हॉस्पिटल सिंधोल/धर्मपुर को 100 बैडिड कर देंगे। मैं आप से पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि उसकी नोटिफिकेशन हुई हैं या नहीं हुई हैं? अगर नहीं हुई हैं तो आप झूठी घोषणाएं करने वाले मंत्री साबित हो रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई बीमार होता है, यदि वह गांव से उठता है तो पी0एच0सी0 में आता है, पी0एच0सी0 वाला उसको रैफरल हॉस्पिटल को

रैफर कर देता है और रैफरल हॉस्पिटल वाला कुछ नहीं करता है, वह एक इंजैक्शन लगाता है और कहता है कि आई0जी0एम0सी0 या पी0जी0आई0/टांडा मैडिकल कॉलेज चले जाओ। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं। माननीय मुख्य जी अभी कह रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हम कांट्रेक्ट पर नहीं कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर क्लास-वन ऑफिसर हैं। डॉक्टर रोगी के लिए भगवान समान होता है। आप डॉक्टरों की भर्ती कांट्रेक्ट बेसिज़ पर कर रहे हैं। आप डॉक्टरों की भर्ती रेगुलर बेसिज़ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर रेगुलर बेसिज़ पर डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, कोई वज़ह नहीं है कि कोई डॉक्टर हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्व करने के लिए न आए। वह आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर इसलिए डॉक्टर नहीं आ रहे है, क्योंकि आपकी नीतियां नेक नहीं हैं। आज अनेकों उपकरण हॉस्पिटलों में बेकार पड़े हुए हैं। वहां पर उन उपकरणों को चलाने वाला कोई नहीं हैं। आपके करोड़ों के उपकरण आई0जी0एम0सी0/टाढ़ा मैडिकल कॉलेज में पड़े हुए हैं। आपके करोड़ों के उपकरण मण्डी जोनल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपके लाखों के उपकरण पी0एच0सीज़ और सी0एच0सीज़ में पड़े हुए हैं। उन उपकरणों को चलाने के लिए जो व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी, उस व्यवस्था को करने में आप असफल रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम आउटसोर्स करते चले जाएंगे। आउटसोर्स पर बाहर के प्रदेशों के लोगों को लाएंगे और उनसे यहां पर काम करवाएंगे। कुमारहट्टी में जो मैडिकल कॉलेज चला हुआ है,

श्रीमती एन.एस. ....द्वारा जारी।

27/03/2017/1715/एन0एस0/ए0एस0/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

उस मेडिकल कॉलेज में जो फीस है और वहां पर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, आप उसका कम्पेरिज़न क्यों नहीं करते हैं? आपके कुम्हारहट्टी के मेडिकल कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है? आप पता कीजिए कि हरियाणा, पंजाब का फी स्ट्रक्चर क्या है? मैं

आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा का फी स्ट्रक्चर कम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज चला हुआ है, उसका फी स्ट्रक्चर आपने ज्यादा रखा हुआ है? आपके ऊपर यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामी की वजह से आज एक ऐसा वातावरण पूरे प्रदेश में खड़ा हो चुका है। आज लोगों को ऐसे इंजैक्शन दिये जा रहे हैं जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। मेरे क्षेत्र की एक बेटी जिसकी डिलीवरी होनी थी, उसको मंडी अस्पताल में आप्रेशन टेबल के ऊपर एक ऐसा इंजैक्शन दिया गया जिससे तड़फ-तड़फ कर उसकी जान चली गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आपको इस बात का पता होना चाहिए क्योंकि आप जिला मण्डी से संबंध रखते हैं। आपको मण्डी में स्वास्थ्य विभाग को अच्छी सुविधा देनी चाहिए थी। आप ई0एस0आई0 के मेडिकल कॉलेज जो कि नेरचौक में है, उसको चलाने में भी नाकाम रहे हैं। मण्डी के लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आप चाहे जितने मर्जी टुर लगाते रहो, ये टुर आपके टुर के रूप में ही रह जायेंगे। यह आपके अलविदा के टुर होंगे और यह आपके काम नहीं आएंगे। ठाकुर कौल सिंह जी मैं बड़े दावे के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

27/03/2017/1715/एन0एस0/ए0एस0/2

अध्यक्षः अब मांग संख्याः 9 पर श्री महेश्वर सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्याः 9 के प्रति कुछ कमियां माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्री जी बीच में टोका-टोकी न करें। आपको तो पूरा समय मिलेगा, तब आप पूरा जबाव देना। मैंने इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है। जो मांगे रखी गई हैं और जिस पर हमारे कटौती प्रस्ताव आए हैं, मैं उस संदर्भ में इस माननीय सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सत्यता है। मैं शुरू में ही इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपने

खाली पदों को भरने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। जितने आप स्वीकृत करते गए उतने स्वास्थ्य संस्थान और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ते गये। यह संख्या इतनी बढ़ायी गई कि आपका किया हुआ काम व्यर्थ हो गया। जब आप एक-एक ब्लॉक में प्राईमरी हैल्थ सैंटर छः-छः खोल देंगे तब यह सर्वनाश तो होगा ही। बिना स्टॉफ के अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कुल्लू के हॉस्पिटल में आज ऑर्थो सर्ज़न नहीं है। मंत्री जी के क्षेत्र के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग और सिराज़ क्षेत्र के लोग जो कुल्लू जोनल हॉस्पिटल में आते थे, अब सबको मण्डी जाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक डॉक्टर भेजा था जिसने कुछ दिन काटे। वह पहले बिलासपुर से निकाला गया था और अब रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग के लिए टाण्डा मेडिकल कॉलेज चला गया है। हम आज भी बिना ऑर्थो सर्जन के हैं। जब ऐसी मूलभूत सुविधायें जोनल हॉस्पिटल में नहीं होगी तो क्या हालत होगी? लैब-टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्ज़ की कमी में कई मशीनें पड़ी हुई हैं। अब आप यह मत पूछना कि कहां-कहां पड़ी हुई हैं? क्योंकि प्रश्न के जबाव में यह आया हुआ है। कम-से-कम 20 से 26 एक्स-रे मशीनें ऐसी हैं जो इन टैक्नीशियन्ज़ के अभाव में खड़ी हैं। फिर आप कहेंगे कि कहां-कहां पर खाली हैं? मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगा कि जितनी चादर होती है, उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन चादर छोटी है और सरकार ने पांव ज्यादा पसार दिये हैं। फिर कमी तो होगी ही। कमी क्यों नहीं होगी? आज यह

27/03/2017/1715/एन0एस0/ए0एस0/3

स्थिति है। आप ऐसा मत कहिए कि हर जगह स्टॉफ मौजूद है। प्रदेश में स्टॉफ की बुरी हालत है। सफाई की हालत खराब है। क्योंकि सफाई कर्मचारी के कैडर को डैड घोषित कर दिया गया है। अब यह कैडर ही डैड है। आप सदर क्षेत्रों में तो सफाई का प्रबन्ध कर देंगे

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

27/3/2017/1720/RKS/DC/1

श्री महेश्वर सिंह ... जारी

लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार के संस्थान हैं उनकी सफाई कौन करेगा? वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं इन चीजों पर ज्यादा न कहता हुआ कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, शिमला में महिलाओं के लिए अलग हॉस्पिटल है। मैं आपके माध्यम से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या वहां पर बर्थ वेटिंग रूम है? क्यों नहीं है? सारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिलिकेटिड केस हैं, उस हौस्पिटल में आ रहे हैं। वहां पर कहीं भी रहना का ठिकाना नहीं है। डॉक्टर यह कहते हैं कि जब महिला को लेबर पेन शुरू हो जाएगी तो हॉस्पिटल ले आना। क्या यह संभव है कि उस वक्त महिला को गांव से उठाकर यहां लाया जाए? यह एक मात्र हॉस्पिटल महिलाओं के लिए है। कुछ दिन पहले की जो दर्दनाक घटनाएं हैं उनका जिक्र माननीय सुरेश भारद्धाज जी ने यहां पर किया था। एक गर्भवती महिला की कुछ कॉम्पलिकेशन्ज थी। उसको आई.जी.एम.सी. रेफर कर दिया गया। उस महिला को कोई एम्बुलैंस नहीं दी गई। उसका पति उसे अपनी गाड़ी में लेकर गया। वहां पर उसका टैस्ट हुआ और कहा गया कि बच्चे की हार्ट बीट है। यह 6 मार्च की बात है। वापिस लाए, वह कहते रहे कि सिजेरियन कर दीजिए। महिला दर्द से कराह रही थी लेकिन किसी ने उसकी खबर नहीं ली। दूसरे दिन फिर उस महिला को रेफर किया गया। दूसरे दिन 7 तारीख को कहा गया कि बच्चा मर चुका है। अब आप अनुमान लगाइए एक गर्भवती महिला 18 घंटे पेन से कराह रही है और मृत्त बच्चे को अपनी कोख में उठाकर चल रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इसकी छानबीन होगी। मुझे नहीं मालूम कि छानबीन हुई या नहीं हुई। जब मृत्त बच्चा घोषित हो गया और हार्ट बीट नहीं है तो उन्होंने उसको डीलिवरी का इंजैक्शन लगाया। इसको कंफर्म कीजिए। उस महिला की जान जा सकती थी परन्तु भगवान का लाख शुक्र है कि वह बच गई। आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बर्थ वेटिंग रूम की सुविधा जोनल

हॉस्पिटल मंडी में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम-से-कम जिला अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा को उपलब्ध करवाइए।

27/3/2017/1720/RKS/DC/2

मैंने एक सुझाव दिया था कि कुल्लू में हनोगी माता मंदिर की सराएं के लिए जगह कुल्लू के प्रशासन ने दान स्वरूप दी है। वह जगह अस्पताल के नजदीक है। उसका चार्ज़ डी.सी. मंडी के पास है। कृपया वह चार्ज़ डी.सी. कुल्लू को दे दीजिए। वहां पर बर्थ वेटिंग सुविधा का भी हो जाएगा और परिजनों को रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। मैंने आई.जी.एम.सी. की बात उठाई थी। लेकिन पता नहीं किस बुद्धिमान ने उस प्रश्न का उत्तर तैयार किया। उत्तर में कहा गया कि केवल 5,000 इस प्रकार के केस रेफर होकर आते हैं। सिरमौर जिला के 19 केस बताए गए। मैंने यह भी पूछा था कि 19 केस एक दिन के हैं या एक वर्ष के हैं। जबकि सत्यता यह है कि लोगों को पी.जी.आई. में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। मैं केंद्रीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जब से उन्होंने एक ओ. एस.बी. तैनात किया है, लोगों को कुछ राहत मिली है। ठहरने को कोई ठिकाना नहीं मिलता है। लोगों को अनहाइजीनिक जगहों में रहना पड़ता है। आपका कहना था कि यहां पर पी.डब्ल्यू.डी. के पास सराएं हैं और वहां का जे.ई. बहुत अच्छा काम कर रहा है। यह सत्यता नहीं है। इसकी जांच कर लीजिए। नीडी लोगों को कमरा नहीं मिलता है। वहां भी सिफारिशें चलती हैं। जब हम स्वास्थ्य विभाग के पास जाते हैं तो हमें यह जवाब मिलता है कि हमारे पास सराएं नहीं है और आप लोक निर्माण विभाग से बात करो। जबकि यह सराएं स्वास्थ्य विभाग की होनी चाहिए थी। वहां जगह है। वहां सस्ती डोरमैट्रीज़ बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आपने भवनों की बात कही उनकी बुरी हालत है। मैं मानता हूं कि पहले तो एक पी.डब्ल्यू.डी. एजेंसी अकेली थी परन्तु अब दो एजेंसी और पैदा कर दी गई है। एक BSNL और दूसरी HIMUDA I इनको भवन बनाने के लिए ठेके पर दिए हैं। करोड़ों रुपये अनसपैंट पड़ा हुआ है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.03.2017/1725/SLS-DC-1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप इंक्वायरी कर लीजिए। यह पैसा ख़र्च क्यों नहीं होता? पैसा मिलने में कोई कमी नहीं है। जैसा यहां कहा गया, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन से भी पैसा आया। प्रश्न यह है कि कब-कब से बिल्डिंग्ज नहीं बनीं। मैं जरी का उदाहरण देना चाहूंगा। जरी प्राइमरी हैल्थ सैंटर है। वहां डॉक्टर्ज़ और स्टॉफ के रैजिडैंस ज़र्ज़र अवस्था में है। मैं आज भी आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब रिज़्वी जी यहां थे, उस समय 20 लाख रुपया डॉक्टर्ज़ और स्टॉफ के क्वार्टर्ज़ की रिपेयर और दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए दिया गया। वहां जगह की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक मैडम वहां पर बैठी है। सारी रिपोर्ट बी.एम.ओ. को देनी है। पैसा 2013-14 में आ गया। उसके बाद 4.00 लाख रुपया अगले साल आया। फिर 3.00 लाख रुपया और आया। वहां 27.00 लाख रुपया पड़ा है लेकिन एक पत्थर नहीं लगा। अंततोगत्वा उस मैडम ने यह लिख दिया कि यहां जगह उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी वहां कई बार गए हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या यह कथन सत्यता पर आधारित है? जगह है, फिर अनुशंसा क्यों नहीं होती? क्योंकि मैडम वहां रहती नहीं है। इतनी लिब्रटी है कि वह 25 किलोमीटर रोज़ महोल जाकर अपने घर में आराम करती है; होमसिक है। नियमों में प्रावधान है कि किराये पर रहना है। मैंने आपसे शिकायत की। न जाने आप भी क्यों उसको संरक्षण देते हैं। यह आपकी बात है। कौन देता है, मुझे मालूम नहीं। उसके अंतर्गत एक सब-सैंटर आता है। निदेशक महोदय यहीं बैठे हैं। ये हमारे सी.एम.ओ. रह चुके हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि वह जगह ठीक नहीं है। वहां सब-सैंटर बिल्डिंग के लिए 45.00 लाख रुपया पड़ा है। वहां का नाम गजमोड़ है और वह अरतोचा पंचायत में है। यह 45.00 लाख रुपया 2 साल से पड़ा है। वह साइट ठीक नहीं थी।

हमने एक आदमी को मोटिवेट करके जगह एक्सचेंज करवा दी और वह जगह सूटेबल पाई गई। अब कोई कहता है कि कैबिनेट ने निर्णय लेना है क्योंकि जगह बदलनी है। कोई कहता है कि कोई एम.ओ.यू. साईन होना है। दो वर्ष हो गए लेकिन एक फूटी कौड़ी ख़र्च नहीं

27.03.2017/1725/SLS-DC-2

हुई। जो मैंने 27.00 लाख रुपया कहा, अंततागत्वा उसको भी उन्होंने यह कहकर, कि जगह नहीं है, अब कम्युनिटी हैल्थ सैंटर के लिए कहा। वह बिल्डिंग भी नई बन रही है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री जी, इन कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करिए ताकि कहीं-न-कहीं दूसरा पत्थर लगे और यह पैसा ख़र्च हो।

अंत में मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपका ध्यान बंजार हॉस्पिटल की ओर ले जाना चाहूंगा। बंजार हॉस्पिटल के लिए 15.00 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। वह आज से नहीं, वर्षों से हो रहा है। आज से 6 वर्ष पहले वहां के उस समय के विधायक और मंत्री श्री खिमी राम जी के कर-कमलों द्वारा शिलान्यास हो गया। वह शिलान्यास काफी नहीं था क्योंकि उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर मंत्री महोदय ने पिछले साल शिलान्यास कर दिया। आज आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या कहीं निर्माण हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? हॉस्पिटल का यह सारा काम लोक निर्माण विभाग के पास है। ख़र्च केवल 8.00 लाख रुपया हुआ। वह संभवतः ड्रांइग बगैरहः तैयार करने पर ख़र्च हुआ है। लेकिन मौक़े पर एक पत्थर नहीं लगा। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जब आप गए थे तो आपने कहा था अगली बार आऊंगा तो यहां पर भवन दिखना चाहिए। वहां भवन तो छोड़ों, ईंट नहीं दिख रही है। कारण क्या है।...(व्यवधान)... डिसमैंटल काहे के, वह खाली जगह पर बने हैं। डिसमैंटल तो तब होंगे अगर चरणबद्ध निर्माण होना है। असली बात यह है कि कुछ प्रभावशाली लोगों का एनक्रोचमैंट वहां हुआ है, उस एनक्रोचमैंट को हटाने में वर्तमान

सरकार विफल रही है। आप आज उस एनक्रोचमैंट को उठाओ, कल को वहां निर्माण शुरू हो सकता है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो निर्माण कहां से होगा, ऐसी स्थिति है। रैवन्यु भी आपके ही पास है।

जारी..श्री गर्ग जी

27/03/2017/1730/RG/AG/1

श्री महेश्वर सिंह---जारी

जब राजस्व विभाग भी माननीय मंत्री जी के पास है, तो फिर कौन डिमारकेशन करवाएगा और ऐनक्रोचमेंट से छुटकारा दिलवाएगा? जहां गरीबों की ऐनक्रोचमेंट होती है, तो सारा राजस्व विभाग सुबह को ही दौड़ जाता है और जब प्रभावशालियों की होती है, तो आराम से सो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

27/03/2017/1730/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर हमने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है, इसके बारे में माननीय महेन्द्र सिंह जी और श्री महेश्वर सिंह जी ने विस्तार से अपनी बात यहां रखी है। वास्तव में मुझे लगता है कि सरकार की कोई स्वास्थ्य नीति है ही नहीं। अगर कोई नीति इसकी बनाई गई है या कभी प्रदेश की विधान सभा में रखी गई है, तो माननीय मंत्री जी इस बारे में बता दें। क्योंकि आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके लिए कोई नियम नहीं है। जब जहां मर्जी होती है, वहां घोषणा कर देते हैं कि

यहां पी.एच.सी. खोल दी, चाहे वहां डॉक्टर लगे या न लगे, वहां फार्मासिस्ट हो या न हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहां हो या न हो। इस बात की कोई चिन्ता नहीं रहती। एक बात सिर्फ यह होती है कि यहां पर हमारा फट्टा लग गया है और पी.एच.सी. खोल दी गई है। इसके अतिरिक्त किस आधार पर बाकी अस्पताल खुल रहे हैं और उनके खोलने का पैमाना क्या है? इस बारे में कहीं कोई गाइडलाईन्ज या नीति दिखाई नहीं देती। हिमाचल प्रदेश लगभग 70,000,000 की जनसंख्या वाला प्रदेश है और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज यहां पांच मैडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के पैसे, उनकी अनुमति एवं उनके समर्थन से हुई है। श्रम मंत्रालय द्वारा नेर चौक में छठे स्वास्थ्य संस्थान, मैडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है, तो वह भी माननीय मंत्री जी और सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। 'ऐम्ज' पाईप लाईन में है। यदि ये उसकी जमीन उपलब्ध करवा दें, तो केन्द्र सरकार उसका शिलान्यस करने के लिए तैयार बैठी है। इतने सारे मैडिकल कॉलेज तो इन्होंने खोल दिए हैं, लेकिन उनमें फैकल्टी आज एक में भी नहीं मिल रही है। जो दो मैडिकल कॉलेज आई.जी.एम.सी. और टांडा चल रहे हैं उनमें भी स्टाफ की कमी होती जा रही है क्योंकि जब एम.सी.आई. किसी कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए यहां आती है, तो इन दोनों कॉलेज से फैकल्टी वहां पहुंचा दी जाती है, दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों से वहां स्टाफ को डिप्यूट कर दिया जाता है। आज हालात ये हो गए हैं कि जो हमारे दो प्रिमीयर इन्स्टीटियुशन्ज टांडा और आई.जी.एम.सी. के हैं, उन दोनों की डिटेरियोरेशन होती जा रही है। आई.जी.एम.सी. में फैकल्टी तो एक तरफ, यहां स्टाफ नहीं है। जब

27/03/2017/1730/RG/AG/3

जरूरत पड़ती है, तो नाहन को यहां से एक ऑर्डर कर दिया जाता है और सारे-के-सारे लैब टैक्नीशियन्ज को बदलकर कभी नेर चौक भेज दिया जाता है, कभी नाहन और कभी चंबा भेज दिया जाता है। चंबा में पिछले साल भर से प्रिंसीपल नियुक्त किया हुआ है, उसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं हो रहा है। इसके कारण आज स्थिति यह हो गई है कि आई.जी.एम.सी. भी अब रैफरल हास्पिटल टाईप बनता जा रहा है। क्योंकि यहां के नियम भी साथ में बदल दिए हैं। दोनों कॉलेज का एक कॉडर था, फिर दोनों का कॉडर अलग हुआ और अब रूल्ज भी बदल दिए हैं। जो नए कॉलेज खुल रहे हैं उनमें फैकल्टी की आयु

65 वर्ष होगी और आई.जी.एम.सी. या टांडा में जो रहेंगे, उनकी 62 वर्ष आयु होगी। अब ये दो प्रकार के हो गए हैं जिसका नतीजा हो रहा है कि

एम.एस. द्वारा जारी

27/03/2017/1735/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी-------

पिछली साल आई0जी0एम0सी0 से 10 या 12 लोग रिटायर हुए हैं। वे सारे कम्पीटैंट डॉक्टर्ज थे और एच0ओ0डीज0 या प्रोफेसर रैंक के थे। उनमें से एक ने भी हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजिज को ऑप्ट नहीं किया और सब प्राइवेट कॉलेजिज में चले गए, जिसका जिक्र यहां हो रहा था। वे आज कुम्हारहट्टी का जो प्राइवेट कॉलेज है वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर उन्होंने रि-एम्प्लॉयमैंट पर जाना है और फिर दूर भी जाना है तो उनको अधिक पैसे पर प्राइवेट कॉलेजिज ज्यादा सहुलियत वाले नज़र आते हैं जहां से वे हररोज शिमला आ-जा भी सकते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इन नियमों में एकरूपता लाइए। इसमें दो चीजें हैं। फैकल्टी आपको चाहिए उसके लिए आपको उम्र बढ़ानी है। पूरे देश में 65 वर्ष डॉक्टर्ज की रिटायरमैंट उम्र रखी गई है लेकिन हिमाचल में एक प्रैशर है कि प्रमोशन्ज रूक जाएंगी इसलिए उम्र बढ़नी नहीं चाहिए। पहले प्रमोट कर दो और जब वे प्रमोट हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि पीछे वालों को रोक दो और आगे के लिए बढ़ा दो। ऐसा चलता रहता है लेकिन तीन कॉलेजिज के लिए 65 साल और दो कॉलेजिज के लिए 62 साल रिटायरमैंट एज़ है और उसका नतीजा यह है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजिज हैं ये भी खाली होते जा रहे हैं। इस साल जुलाई में आई0जी0एम0सी0 से लगभग 10-12 सीनियर प्रोफेसर/ फैकल्टी मैम्बर्ज रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद आई0जी0एम0सी0 और डिटेरियोरेशन में चली जाएगी। तो इस हालात में हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हमें अगर प्रौपर हैल्थ सर्विसिज प्रदेश की जनता को प्रदान करनी है तो इस विषय में गम्भीरता से विचार करना होगा। हम स्टाफ की या तो एक्सपैंशन करे। फैकल्टी आपको मिल ही नहीं रही है। आप दिल्ली में भी जाकर

इंटरव्यु कर रहे हैं लेकिन जो बाकी स्टाफ है वह स्टाफ नहीं है। ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थियेटर में जो ओ0टी0एज0 होते हैं वे कहीं भी नहीं मिलेंगे। यहां पर इतना बड़ा रिजनल अस्पताल दीन दयाल उपाध्याय है लेकिन उसमें ओ0टी0ए0 नहीं मिलेगा। वहां जो फार्मासिस्ट और कुछ स्टाफ नर्सिज वगैरह ट्रेंड किए हुए हैं वे ही ओ0टी0ए0 का काम करते हैं। ऐसी हालत है क्योंकि आप प्रौपर एप्वायंटमैंट नहीं कर रहे हैं। आपके पास इतने संस्थान हैं और उन संस्थानों में

27/03/2017/1735/MS/AG/2

आपने फार्मासिस्ट, ओ0टी0ए0 और स्टाफ नर्सिज को ट्रेनिंग दे रखी है तो कृपया जो फंक्शनल पोस्ट्स हैं उनको भरने की दिशा में भी विचार करें और उनको प्रौपर भरें क्योंकि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा। उसकी जगह आप किसी अन्य व्यक्ति को वहां नहीं बिठा सकते। जो फंक्शनल पोस्ट्स हैं कम-से-कम उनको तो भरिये। बाकी आप टॉप एडमिनिस्ट्रेशन तो बना देंगे जबकि उनके बगैर काम चल सकता है। वन विभाग में पी0सी0सी0एफ0 एक भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। एडिशनल चीफ सैक्रेटरी यदि एक या दो होंगे तब भी प्रदेश चलेगा लेकिन यदि डॉक्टर्ज, ओ0टी0एज0 और स्टाफ नर्सिज इत्यादि की फंक्शनल पोस्ट्स नहीं होंगी या टीचर्ज नहीं होंगे तो संस्थान नहीं चलेगा। इसलिए उस पर विचार करने की आवश्यकता है और प्रौपर नियुक्तियां होनी चाहिए। कई स्थानों पर नियुक्तियां हो रही हैं लेकिन वे बैकडोर नियुक्तियां हो रही हैं। हमारे ही लोगों ने कुछ कम्पनियां बना दी हैं। उनसे आउटसोर्स पर आप स्टाफ मांगते हैं। वे अनट्रेंड स्टाफ भेजते हैं और उनको हम नियुक्त कर देते हैं। फिर उनकी डिमाण्ड आती है कि इनको आर0के0एस0 में नियमित कर दो और फिर आर0के0एस0 के बाद इनको स्टाफ में लगा दो। इस तरह से जो मैरिट है वह टोटल इग्नोर हो जाएगी। क्योंकि प्रौपर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। बैकडोर से ठेके पर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। उसके कारण सारी स्वास्थ्य सेवाएं भी नीचे जा रही हैं। इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।

सुपर स्पैशलिटी के लिए भारत सरकार से आपको पैसा मिला है। कई बार युनियन हैल्थ मिनिस्टर कह चुके हैं कि उसका शिलान्यास करना है उसको शुरू कीजिए, बनाइए लेकिन उसके लिए बार-बार केवल मीटिंग्ज होती हैं। उसके लिए कभी स्थान मल्याणा में

ढूंढा जाता है और कभी कहीं और ढूंढा जाता है। आप सुपर स्पैशलिटी मल्याणा में 15-20 किलोमीटर के अंतर पर ले जाएंगे और मेडिकल, एनीस्थिसिया और सर्जरी विभाग आई0जी0एम0सी0 में रहेंगे तथा लेबोरेटरीज भी आपकी यहीं पर रहेगी तो कैसे होगा? या तो आप सारी-की-सारी चीजें मल्याणा में ले जाइए ताकि वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक का स्टाफ/डॉक्टर्ज सबकुछ वहीं हो। यहां पर मेडिसन में कार्डयिक का कोई मरीज दाखिल होता है और उसको यदि सुपर स्पैशलिटी की जरूरत पड़ती है तो आप

27/03/2017/1735/MS/AG/3

गाड़ी भगाते हुए ऐसे कन्जैशन में जब संजौली होते हुए जाना भी मुश्किल होता है, उसको आप मल्याणा पहुंचाएंगे तो जैसे महेश्वर सिंह जी ने के0एन0एच0 की बात बताई थी वह आई0जी0एम0सी0 के गेट पर ही हो जाएगी। माननीय मंत्री जी जब विपक्ष में थे तब भी मैंने एक सुझाव दिया था कि के0एन0एच0 के गायनाकॉलोजी विभाग को आप आई0जी0एम0सी0 में ले जाइए।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

27.03.2017/1740/जेके/एएस/1

श्री सुरेश भारद्वाजः------**जारी**--------

डैंटल तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन वहां ले जाएंगे तो वहां पर सारी सुविधाएं मिलेगी। बच्चा कई बार आई0जी0एम0सी0 में होता है और माँ के0एन0एच0 में होती है। माननीय मंत्री जी की स्टेटमैंट रिकॉर्ड में है। इन्होंने कहा था कि वहां पर गेट के पास इतनी ज्यादा भीड़ होती है अगर गाड़ी आएगी तो गेट के पास ही महिलाओं की डीलिवरी हो जाएगी। यह आपकी बात रिकार्ड में है जब आपने विपक्ष में रहते हुए कहा था। देखिए आज ऐसी अवस्था है कि आपके जो इमरजैंसी के डॉक्टर्ज हैं वे सीधे आई0जी0एम0सी0 से के0एन0एच0 नहीं

जा सकते क्योंकि उनको परमिट लेना पड़ता है। वे घूम करके संजौली होते हुए के0एन0एच0 जाएंगे। वहां पर इमरजैंसी है लेकिन वहां पर इमरजैंसी कॉल पर डॉक्टर नहीं पहुंच पाता है। अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पर आप विचार करिए कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपरली दी जा सकती है। आप बहुत सारी चीजें दे भी रहे हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं कि पिछली बार मैंने लीवर के लिए एक यहां पर डीमाण्ड की थी आपने वह डेढ़ करोड़ की मशीन वहां पर लगा दी है। जब आप उसका उदघाटन करेंगे तो कृपया मुझे भी आप बुला लीजिए। मैं भी आपके साथ आऊंगा। लेकिन जो चीजें नहीं होती हैं, उन चीजों पर अगर विचार इकट्ठा करेंगे तो उससे ज्यादा सुविधाएं हमको मिलेंगी। आई0जी0एम0सी0 हमारा प्रीमियर हॉस्पिटल है। हमारे लिए यह बहुत ही गर्व व खुशी की बात है कि आज आई0जी0एम0सी0 का जो प्रोडक्ट है वह पी0जी0आई0 का डायरैक्टर बना है। आई0जी0एम0सी0 से उन्होंने ग्रेजुएशन क्वालिफाई की वे आज पी0जी0आई0 में हैं। दिल्ली के एम्ज में भी हिमाचल का डॉक्टर डायरैक्टर बना है और पी0जी0आई0 में भी हिमाचल का डायरैक्टर बना है। हमारी केन्द्र की सरकार व स्वास्थ्य मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा जी को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन आई0जी0एम0सी0 का प्रोडक्ट भी दुनिया के टॉप मोस्ट कोरनिया के सर्जन में डॉ0 जगत राम का नाम है। आई0जी0एम0सी0 बहुत अच्छा संस्थान है। लेकिन इसकी डिटेरियोरेशन हम स्वयं

27.03.2017/1740/जेके/एएस/2

करते जा रहे हैं। हमने सारी लेबोरेटरीज की सारी सर्विसिज़ प्राईवेट हाथों में सौंप दी है। वे जब रिपोर्ट देते हैं तो जिसको जुकाम होता है उसको केंसर डिक्लेयर कर देते हैं और सम्बन्धित व्यक्ति रिपोर्ट लेते ही अधमरा हो जाता है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर ठीक कहा कि सफाई कर्मचारी यहां पर भी आऊट सोर्स में आ रहे हैं। आऊट सोर्स की कम्पनी जिसकी होती है उस हिसाब से वह अप्वाईंट हो जाती है और आऊट सोर्स के सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। लेकिन जो बाहर की सारी चीजें हैं वे उतना ही करते हैं

जितना कॉंट्रेक्ट है, उसके अलावा वे एक भी तिनका उठाते नहीं है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने भी यहां पर कहा था और मैंने भी कहा था कि आई0जी0एम0सी0 को ऑटोनमस इन्स्टिच्यूट बनाया जाए। अभी भी आप ही पैसा देते हैं। जब इन्स्टिच्यूट बनेगा तब भी आप ही पैसा देंगे। थोड़ी सी फंक्शनल ऑटोनॉमी हो जाएगी और इसका स्टेटस बढ़ जाएगा। इसमें फेकल्टी बगैरह अच्छी लाने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तब कहा था कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे परन्तु यूनिवर्सिटी आई0जी0एम0सी0 तो नहीं बनेंगी। अगर इसको आपको ले जाना है तो ले जाईए। लेकिन आई0जी0एम0सी0 के स्टेटस को बढ़ाने पर विचार करिए ताकि यहां पर जो पेशैंट्स सारे प्रदेश भर से आते हैं, उनको सुविधाएं मिल सके। शिमला इन्टरनेशन टूरिस्ट डैस्टिनेशन है। यहां पर सारी दुनिया भर से पेशैंट आते हैं। अगर आई0जी0एम0सी0 अच्छी सर्विसिज़ देता है तो आपकी सेवाओं का दुनिया भर में डंका बजता है। छोटे से स्थान पर जो इन्स्टिच्यूशन होगा वह तो वहां का नाम दे देगा लेकिन शिमला में जो सर्विसिज़ दी जाएगी, वह सारी दुनियां में आपका नाम रोशन करेगी इसलिए उसके ऊपर आप विचार करिए। अगर हो सकता है तो आप ट्रॉमा सेन्टर जो सेंक्शन हुआ है जिसका पैसा सेन्टर से आया है। उस ट्रॉमा सेन्टर को जहां पर आपने जगह परपोज़ की है वह बेसमैंट में है। जब साल-डेढ़ साल बाद वह तैयार हो कर आएगा उसका कोई बहुत लाभ नहीं होगा और न ही वह वहां पर प्रॉपर जगह मिलेगी, क्योंकि उसके चार ऑप्रेशन थियेटर

27.03.2017/1740/जेके/एएस/3

चाहिए। दो कमरे आप बेसमैंट में ईयरमार्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का एक या दो मंजिल ट्रॉमा सेन्टर के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा और जनता के लिए भी सुविधाजनक होगा क्योंकि वह सड़क के साथ है। उनकी पार्किंग बगैरह का वहां पर प्रॉपर

साधन बन गया है। वह पैसा जो इतने सालों से आया है उसका उपयोग इसी काम के लिए करें

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

27.03.2017/1745/SS-AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

तो ज्यादा बेहतर ट्रॉमा सैंटर वहां पर बनेगा।

दूसरा, मैं शिमला की दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर बहुत बड़ा शिमला हो गया है और छोटी-छोटी बीमारी के लिए आई0जी0एम0सी0 या डी0डी0यू0 चले जाते हैं क्योंकि छोटी बीमारी होने की सूरत में उसे दिखाने के लिए आपके पास डिस्पैंसरी तक नहीं है। एक-दो स्थानों पर हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप हर वार्ड में एक डिस्पैंसरी, सब-सैंटर या पी0एच0सी0 का प्रावधान कर सकें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर वह सम्भव नहीं हुआ तो क्लब में दो-तीन जगह पर ऐसे स्थान निकाल दिये जाएं जहां पर 5 से 10 हजार की आबादी है। वहां पर अगर पी0एच0सी0 बन जाए तो उसका लाभ होगा। संजौली में आप कभी जायेंगे तो आते-जाते देखना कि चौंक पर म्युनिसिपल कारपोरेशन की बिल्डिंग है। ऊपर ऐसी बिल्डिंग में शायद पी0एच0सी0 तो क्या मुझे लगता है कि कोई छोटी-से-छोटी चीज़ भी नहीं हो सकती।

Speaker: Please wind up.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए उस बिल्डिंग को म्युनिसिपल कमेटी से आप ले लें, उसको बनाएं। मैं वहां गया था और मैंने कहा था कि अगर थोड़ा बहुत विधायक निधि से ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसमें से धनराशि दे दूंगा। लेकिन विधायक निधि से पूरी बिल्डिंग नहीं बन सकती। निचली मंजिल में कारपोरेशन के

अपने इम्प्लॉई रहते हैं। उसका प्रबंध कहीं इधर-उधर हो जाए तो वहां बहुत बड़ी जनसंख्या है, उससे आई0जी0एम0सी0 का प्रैशर कम हो जायेगा। इस दिशा में अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो दवाइयां हैं, दवाइयों के लिए अमृत फॉरमेसी शायद आपने टांडा में शुरू करनी है, उसकी आई0जी0एम0सी0 में बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि यहां बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको बता सकता हूं।

27.03.2017/1745/SS-AS/2

ओ0टी0 में आपके पूरी लिस्ट सर्जिकल आईटम्ज़ की लिखी जाती है। कितनी आईटम्ज़ ओ0टी0 के अंदर यूज होती हैं इसकी आप ज़रा जांच करवाईये। वे आईटम्ज़ स्पैसिफिक दुकानों से लेनी पड़ती हैं तब जाकर ऑपरेशन होता है वरना ऑपरेशन के लिए टाल-मटोल होता है। एक तरफ डॉक्टर्ज़ कहते हैं, मैं आज भी स्टेटमैंट पढ़ रहा था कि आपने मेडी-पर्सन ऐक्ट पर कुछ नहीं किया है, हमारे साथ मारपीट होती है और आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो जनता और मरीज़ों के साथ होता है उसका क्या इलाज है क्योंकि उनके खिलाफ हम कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? गवर्नमैंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्ज़ हैं वे कुछ भी करें लेकिन उनके खिलाफ सर्विसिज़ के संबंध में कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और कोई साधन हमारे पास नहीं है। अब एक नई स्वास्थ्य नीति केन्द्रीय सरकार की आई है, उसमें शायद ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। अगर उसके अनुसार कुछ कर सकें तो ठीक है। हम यह भी मानते हैं कि डॉक्टर्ज़ को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि वे अगर सुरक्षित रहेंगे तभी वे काम कर पायेंगे। कई बार बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो उसमें कोई किसी प्रकार की गलती हो जाती है। क्योंकि जो मरीज़ आते हैं उसके तीमारदार समझते हैं कि उनका मरीज ही सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में कुछ घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन यह रेसीप्रोकल है। दोनों तरफ की समस्याओं को समझकर अगर उचित नीति बनायेंगे तो उसका ज्यादा लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

27.03.2017/1745/SS-AS/3

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर जी अपनी बात कहेंगे।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 पर जो कटौती प्रस्ताव यहां विपक्ष की ओर से हम सब लोगों ने दिये हैं उसमें हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें विस्तार से हो गईं और इसके अलावा बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी बजट भाषण और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कुछ बातों का ज़िक्र कर चुका हूं। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही सैंसटिव विभाग है और सीधा मानव के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें मुझे लगता है कि

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2017/1750/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

सोचने की आवश्यकता है कि जो चीजें हम करने की स्थिति में बन पा रहे हैं उसमें हम बेहतरीन करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो वर्तमान सरकार का एक तरीका बन गया है कि संस्थान खोलो और संस्थान खोलने के लिए जो-जो भी किया जा सकता है, किया जा रहा है लेकिन संस्थान खोलने के बाद वह चलना जरूरी है, इस बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जिक्र हो रहा है कि हमने इन चार सालों में हिमाचल प्रदेश में 2100 सिविल हॉस्पिटल, 34 सी.एच.सी., 96 पी.एच.सी. और 29 हैल्थ सब सैंटर खोले।

आप खोलते जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन संस्थानों को चलाने की जो आवश्यकता है, स्टाफ की आवश्यकता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरह से आगे दौड़, पीछे चौड़। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में देखता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज की तारीख में चार पी.एच.सीज़. खोली है, चारों में ताले लगे हुए हैं। जिनमें बागा चनोगी है, कलनी है, खोलानाल है और हैरानी तब होती है कि उद्घाटन कर दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पता नहीं होता कि उस संस्थान का उद्घाटन कर दिया गया है। फट्टे लगा दिए गए हैं और फट्टे लगाने के बाद जहां पर डॉक्टर बैठना चाहिए था, वहां पर ताला लगा हुआ है और एक वर्ष नहीं, तीन-तीन वर्षों से ताले लगे हुए हैं। यह अपने आप में आपकी सरकार की कार्य पद्धति पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। अब रुकिए, बहुत हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार भी आपने जाते-जाते यह खूब किया था लेकिन आपको राजनीतिक दृष्टि से उसका फायदा नहीं हो पाया। आप सत्ता में थे, सत्ता से विपक्ष में आ गए। जो घोषणाएं की जा रही हैं उनको अब लोग गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके और संस्थानों की घोषणाएं मत करिए। आप लोग कहते हैं कि कोई संस्थान बन्द करवाना है तो आप लिख कर दे दीजिए। हमने क्यों लिख करके देना है? लोग खुद आपको लिख करके देंगें क्योंकि जो आपकी सरकार कर रही है, लोग आपकी सरकार को ही बन्द करने के लिए लिख करके दे देंगें। यह स्थिति आने वाली है।

27.03.2017/1750/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे रैफरल हॉस्पिटल्ज़ हैं जहां पर नॉर्मज़ के मुताबिक स्टाफिंग होनी चाहिए थी, वहां उसके मुताबिक नहीं हो पा रही है। सिर्फ संस्थान चलता रहे, जहां चार डॉक्टर्ज़ की पोस्टें हैं, जहां पांच डॉक्टर्ज़ की पोस्टें हैं, वहां पर एक आदमी है और जब हम यहां से इस बारे में प्रश्न पूछते हैं कि आपने संस्थान खोला लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है तो कहते हैं कि पोस्टें क्रिएट कर दी गई है। अध्यक्ष

महोदय, मैं इस बारे में पहले भी बोल चुका हूं कि पोस्टें क्रिएट करने के लिए कागज लगता है लेकिन पोस्टें भरने के लिए आदमी लगता है। यह कोई जवाब नहीं बनता है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में इसकी वजह से चरमरा गई है। मैडिकल कॉलेज की बात आ रही है, मैडिकल कॉलेज आई.जी.एम.सी. है, मैडिकल कॉलेज टांडा है, एक नया मैडिकल कॉलेज नाहन में खुला । मन्शा तो आप इस बात की भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमने चम्बा और हमीरपुर में भी खोलना है। केन्द्र की ओर से जो मदद की जा सकती है, उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि दो संस्थान जिसका जिक्र हमारे से पूर्व वक्ताओं ने किया, आई.जी.एम.सी. का किया, टांडा मैडिकल कॉलेज का जिक्र किया, हम उन दोनों को भी ठीक प्रकार से चलाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.3.2017/1755/av/dc/1

श्री जय राम ठाकुर ---------- **जारी**

सारी चीजों को लेकर सोचने की आवश्यकता है। हमें संस्थान खोलने की बजाय उनको चलाने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर विचार करने की जरुरत है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रोब्लम आ रही है क्योंकि संस्थान के नाम पर फट्टा तो लगा दिया जाता है मगर उपचार करने के लिए वहां पर डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर है तो उसके साथ दूसरी वांछित सुविधाएं, दवाइयां या पैरा मैडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं होता। यहां पर हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे कि एक महिला पहले कुल्लू होस्पिटल में एडमिट होती है, वहां से उसको मण्डी रैफर कर दिया जाता है। उसकी डीलिवरी होने वाली थी मगर मंडी के अस्पताल में भी उसकी डीलिवरी नहीं हो पाई। अल्टिमैटली उस इन्दु नाम की महिला को वहां से उसके पति को डिस्चार्ज करके ले जाना पड़ा और एक प्राइवेट

होस्पिटल में उपचार करवाना पड़ा। उन्होंने इस बारे में मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा है। उन्होंने अपनी सारी शिकायत लिखी है और यहां हमारे पास भी भेजी हुई है। हम यह नहीं कहते कि हर जगह ऐसा है, मगर उसके बावजूद भी जो गम्भीरता स्वास्थ्य विभाग को चलाने के लिए इस सरकार की ओर से दर्शाई जानी चाहिए, उसमें कमी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम संस्थान तो अन्धाधुन्ध खोलते जा रहे हैं मगर संस्थान चलाने के लिए जो स्टाफ और सुविधा की जरुरत है, वह नहीं मिल रही है। हम नेरचौक, मंडी के मैडिकल कालेज का इंतजार कर रहे हैं। पहले पिछले साल खोलने के लिए बोल रहे थे और बाद में इस साल के लिए कहा जा रहा था। अगस्त माह तक आपकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण होनी चाहिए मगर उसके बावजूद भी हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं। वहां पर जो फैकल्टी चाहिए वह फैकल्टी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मंडी में कैंसर युनिट के लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मदद की है मगर उसके बावजूद भी वहां सारी चीजें जिस तेज गति से होनी चाहिए वह उस तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम यहां पर बोल सकते हैं लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि स्वास्थ्य

27.3.2017/1755/av/dc/2

विभाग को सबसे बड़ा नुकसान इस वजह से हो रहा है कि हम संस्थान खोलते जा रहे हैं मगर उनको चलाने के लिए गम्भीरता से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जो कि उस दिशा में करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस वजह से बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर स्टाफ नहीं है। इस बात पर सरकार गम्भीरता से विचार करें। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बाते कही हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.3.2017/1755/av/dc/3

Speaker : Now Dr. Rajeev Bindal Ji may also speak but you cannot speak Cut Motion, you can speak on Demand only because you have not presented Cut Motion yourself. You were absent at that time.

डॉ0राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द सुझाव माननीय मंत्री जी के लिए रखूंगा। माननीय मंत्री जी अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें जहां इम्प्रूवमैंट की जरुरत या गुंजाइश लगती है केवल उतना ही विषय रखूंगा और स्पष्ट शब्दों में केवल सुझाव के रूप में कुछ कहूंगा। दिनांक 25 दिसम्बर, 2010 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर *अटल स्वास्थ्य सेवा* शुरू हुई थी जो यहां पर अभी 108 नेशनल एम्बुलैंस के नाम से चल रही है। यह बहुत ही बेहतरीन सेवा है और पिछले सात सालों में लगभग आठ लाख से अधिक मरीज इस सेवा ने उठाये हैं। इसको थोड़ा स्ट्रैन्थन करने के लिए मेरे दो-तीन सुझाव हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

27/03/2017/1800/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

डॉ0 राजीव बिंदल..... जारी

जब यह सेवा शुरू हुई थी, तो ऐसा प्रयास किया गया था कि 30 मिनट इसका रीचिंग टाईम हो और बहुत स्थानों पर तो अभी भी ये एंबुलैंस 10-15 मिनट में पहुंचती है। लेकिन माननीय मंत्री जी एक टॉपोग्राफिक ड्राईंग पूरे हिमाचल की ड्रॉ कर लें और उसको ड्रॉ करके जो-जो स्टेशन्ज आते हैं,उन स्टेशन्ज़ के ऊपर एंबुलैंस सर्विस के लिए स्पेशल स्थान क्रियेट करें। उसको किसी पी0एच0सी0/सी0ए0सी0 में रखने के वज़ाय उस स्थान पर रखें और उसमें ड्राईवर के लिए जिसको पाइलट कहते हैं के लिए रहने की व्यवस्था हो। ये लम्बे

समय तक चलने वाली योजना है और इससे जनता को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, जैसा अभी मिल रहा है।

दूसरा, वर्ष 2010 में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी और ये स्वास्थ्य बीमा योजना भी बहुत कारगर सिद्व हुई है और अभी भी अच्छे से काम कर रही है। मेरा इसमें सुझाव है, माननीय मंत्री जी सिरमौर आये थे, उस दिन भी मैंने ये सुझाव दिया था कि बी0पी0एल0 की सूचियों में लगातार बदलाव हो रहा है। पंचायतों में जनरल हाऊस हुए और नये बी0पी0एल0 की लिस्टें बनी हैं। जो लोग नये बी0पी0एल0 बने है, उनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं हैं। जब यह योजना बनी थी, तो ऐसा तय हुआ था कि हम हर साल या 2 साल के पश्चात् स्मार्ट कार्ड बनाएंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कंपनी को आदेश दें, ताकि नई सूचियों के हिसाब से स्मार्ट कार्ड बन सकें। वह बी0पी0एल0 का कार्ड लेकर हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, उनको वहां पर सहायता नहीं मिलती। इसका भी बहुत अच्छा लाभ इन लोगों को मिलेगा।

एक छोटा-सा इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमने अपने समय में एक क्लर्क को पी0जी0आई0 में लगाया था, वह अच्छा काम कर रहा है। आप भी उससे काम ले रहे हैं। परन्तु उसको आईडैंटिफाई करने को वहां पर कोई जगह नहीं है। एक छोटा-सा खोका हमारी सरकार पी0जी0आई0 में ले करके उसके ऊपर स्वास्थ्य बीमा का बोर्ड लगाया जाये। ताकि जिसको भी स्वास्थ्य बीमा के लिए मद्द चाहिए, वह वहां कांटेक्ट कर सके, क्योंकि उसकी जानकारी के अभाव में जो लोग वहां जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता।

27/03/2017/1800/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

तीसरा, जो कैंसर के रोगी हैं, उनके लिए आपने इस बार भी डिक्लेयर किया है और पहले से भी कहा था, जो लाभ उनको मिल रहा है वह अच्छा है, लेकिन सभी कैंसर के रोगियों को वह लाभ नहीं मिल रहा है जो आप उनको देना चाहते हैं। आप उनको आने-जाने का किराया देते हैं, वह जानकारी के अभाव में उनको नहीं मिल रहा है। उसकी जानकारी के लिए हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अंदर अगर हम डिस्पले बोर्ड लगा दें कि

कैंसर का रोगी कैसे किराये को अपने लिए प्राप्त कर सकता है, तो इससे उसको सुविधा होगी। साथ ही कैंसर के रोगी का इलाज़ कैंसर इंस्टीच्यूट में करते समय वहां पर भी पूरी जानकारी डिस्पले कर दें। यदि संभव हो तो छोटा-सा हैंड बिल, जब उसकी पर्ची बने, उसके साथ उसकी जानकारी के लिए दे दें। उससे उसको लाभ मिलेगा।

"बेटी है अनमोल" इस योजना पर आपका भी व्यक्तिगत एम्फेसिस बहुत रहा है। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय में यह योजना शुरू हुई थी और बहुत कारगर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस योजना के लिए और टयूबरक्लोसिस के लिए

श्रीमती एन.एस. ....द्वारा जारी।

27/03/2017/1805/एन0एस0/ए0जी0/1

डॉ0 राजीव बिन्दल ----- जारी

आप विशेष एम्फेसिज़ दे रहे हैं, उसके लिए पब्लिक पार्टीसिपेशन को बढ़ाने का प्रयास करें। इस योजना को स्कूलों में नीचे तक उतारने की जरुरत है। अगर दोनों योजनायें नीचे तक उतरेंगी तो अवश्य हमें इसका लाभ मिलेगा। यह लाभ हमें सही अर्थ में मिल सकेगा। आपने प्रदेश में बेहतर सेवाएं देने के लिए नये संस्थान खोले हैं, उनका स्वागत है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो संस्थान सब-डिवीजनल लैबल पर खोले गए हैं, उनको अवश्य मजबूती प्रदान करें। उनमें किसी तरह की कमजोरी न रहे। उदाहरण के लिए राजगढ़, शिलाई, ददाहू, सरांहा आदि जो स्थान है और इन स्थानों में चिकित्सकों व पैरा-मेडिकल की कमी हो जाती है तो सिविल हॉस्पिटल और बाकी अस्पतालों में इसका दबाव बढ़ता है तथा जब चिकित्सकों पर दबाव बढ़ता है तो क्वालिटी में कमी आती है। आप इसको अपने लैबल पर इग्जामिन करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य

विभाग में अलग-अलग प्रकार से कर्मचारियों को रखा गया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आज रखा बल्कि हम लोगों ने भी रखा है और हमारे से पहले आप थे आपने भी रखा है। इन सोसाइटीज़ में कर्मचारी हैं। टुबर्क्यलोसिस सोसाइटी, एडज़ कंट्रोल सोसाइटी, लेपरेसी सोसाइटी और आर0के0एस सोसाइटी है, इन सोसाइटीज़ में भिन्न-भिन्न कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों के लिए एक नीति बना करके इनको एक अम्बरेला के नीचे लाने की जरुरत है। कोई कर्मचारी 20 साल से लगा है, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और कोई पांच साल पहले लगा है, उसको लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो आउटसोसिंग का पैटर्न है उसके अंदर भी हमारा यह मानना है कि आप चाहे आर0के0एस0 सोसाइटी को स्ट्रैन्थन कर लें या फिर किसी एक सोसाइटी को स्ट्रैन्थन कर लें या कॉन्ट्रैक्चुअल पैटर्न के ऊपर, जो सरकार बाकी सभी विभागों में कर रही है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको सच में ही क्रेडिट मिलेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लगे हैं, चाहे वे 5 साल या 6साल से लगे हैं उनके लिए जो सरकार की नीति हो उसके

27/03/2017/1805/एन0एस0/ए0जी0/2

ऊपर वे रेग्यूलर होंगे तो पूरे सन्तोष के साथ वे काम करेंगे। मेरा मानना है कि अगर हम सबके लिए एक ही नीति का निर्धारण करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी आउटसोर्सिंग के बजाए कॉन्ट्रेक्चुअल पर अगर करेंगे तो वह भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ कंपनियां आउटसोर्सिंग में अच्छा काम कर रही हैं और कुछ कंपनियां नहीं कर रही हैं। उसका वैड नेम सरकार और इनके ऊपर आता है। मैं एक बहुत छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, शायद कारगर हो जाए। हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग तैयार हो रहे हैं, जो बी0एस0सी0 (टैक्नोलॉजी) कर रहे हैं। हमारे यह स्टूडैंटस आई0जी0एम0सी0 और टाण्डा से निकल रहे हैं। इनकी सबसे पहली डिमांड पी0जी0आई0 में है। हम उनको यहां पर नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां पर उनकी सैलरी कम है। अगर हम उनकी सैलरी नहीं बढाएंगे तो हम उनको नहीं रोक पायेंगे। न ही हम ओ0टी0ए0 को रोक पायेंगे। इसकी एक कैटेगिरी बी0एस0सी0(टैक्नोलॉजी) है,

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनकी सैलरी को एनहांस करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बहुत अनुभवी है और सबसे सीनियर पोलीटिशयन्ज़ में से है। हम जब तक कॉलेजों में स्पैशलिस्ट की संख्या नहीं बढ़ायेंगे, एम0डी0, एम0एस0 और एम0सी0एच0 तथा डी0एम0 में अगर हम स्टूडैंटस की संख्या नहीं बढ़ायेंगे तो हम प्रदेश में अच्छी सर्विसिज़ देने में कामयाब नहीं होंगे। जब हमारी सरकार थी और हमें समय मिला तो उस समय एम0डी0 और एम0एस0 की 39 सीटें थीं, उन्हें बढ़ा करके हमने 149 तक कर पाये थे। आपने भी 7-8 सीटें अभी हाल ही में बढ़ाई हैं।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

27/3/2017/1810/RKS/AS/1

डॉ0 राजीव बिन्दल... जारी

मैं उसी दिन प्रैस में पढ़ रहा था। 39 सीटें बढ़ी हैं यह बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। जो हमारी स्थिति है, हम इसको सीधा-सीधा 350 पर ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15,000 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमें इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जो सहायता राशियां हैं उन पर व्यक्तिगत इंटरस्ट लिया जाए तो वे हो जाएंगी, नहीं तो लॉअर लैवल से केवल क्वारी लगकर वापिस आ जाएगी। चाहे वह ट्रॉमा सैंटर, सुपर स्पेशियलिटी या महिलाओं के चिकित्सालय की बात हो। जहां पर महिलाओं के लिए चिकित्सालय बने हैं, वे महिलाओं के चिकित्सालय के रूप में उपयोग नहीं हो रहे हैं। वे चिकित्सालय अदरवाइज उपयोग हो रहे हैं। उसके कारण भी परेशानी होती है। मैंने सुझाव के रूप में आपको कुछ

बातें बतानी थी। यह आपका अनुभव भी है और आपका ज्ञान भी है। आशा है आप इन बातों पर गौर करेंगे।

27/3/2017/1810/RKS/AS/2

अध्यक्षः अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 9 -'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से स्वास्थ्य पर अपनी बात को रखा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। क्योंकि हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही दूर-दराज क्षेत्र है। साथ में यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। कनैक्टिविटी के हिसाब से और सभी प्रकार से यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने कई बार विधान सभा प्रश्न के माध्यम से यह बात रखी है। हमारे क्षेत्र में एकमात्र सी.एच.सी. शिलाई में है। वह हमारा केन्द्र बिन्दू पड़ता है। उसमें लगभग 200-300 ओ.पी.डीज. हर रोज होती हैं। वहां पर वर्तमान में दो ही डॉक्टर्ज हैं और अन्य स्टाफ भी बहुत कम है। वहां पर कम-से-कम पांच डॉक्टर्ज की पोस्टें होनी चाहिए। वहां पर डैंटिस्ट डॉक्टर की भी बहुत आवश्यकता है। वहां पर जो मशीनें लगी हुई हैं उनको कोई लाभ नहीं है। मशीनों में जंग लग रहा है। X-ray की मशीन वहां पर लगी हुई है लेकिन टैक्निशियन नहीं है। X-ray के लिए पांवटा जाना पड़ता है। पांवटा आने का मतलब है कि लोगों को वहां पर ठहरना भी पड़ेगा और उनका ज्यादा खर्चा भी होगा। वर्ष 2012 में माननीय धूमल जी ने एक नया भवन बनाने का शिलान्यास किया था। 50 लाख रुपये अभी भी पी.डब्ल्यू.डी. के पास डिपोजिट पड़े हुए हैं। पांच वर्ष का समय बीत गया परन्तु अभी तक भवन बनाने के लिए टैंडर नहीं हुआ है। कृपया आप उस ओर भी ध्यान दें। दूसरा, हमारे विधान सभा क्षेत्र में 8 पी.एच.सीज. हैं। अभी एक-दो पी. एच.सीज. में डॉक्टर्ज आए हैं जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके बावजूद जाखना पी. एच.सी. में कोई डॉक्टर्ज नहीं हैं। वहां पर

मात्र दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। क्यारीगुना पी. एच.सी. में अभी परसों ही एक डॉक्टर आई है। लेकिन इसके अलावा वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। पी. एच.सी. रोनाहाट, पी. एच.सी. नैनीधार में एक-एक डॉक्टर हैं लेकिन उसके अलावा कोई स्टाफ नहीं है। शिलाई हॉस्पिटल में कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है। कृपया आप वहां पर कोई-न-कोई व्यवस्था कीजिए। हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 27 हैल्थ सब सैंटर्ज हैं जिसमें से 17 हैल्थ सब

27/3/2017/1810/RKS/AS/3

सैंटर्ज बंद पड़े हैं। वहां पर कोई मेल/ फीमेल हैल्थ वर्कर्ज नहीं हैं। अभी परसों ही एक बिल्डिंग गुमट का उद्घाटन किया गया लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ है। उस उद्घाटन का क्या फायदा जहां पर कोई स्टाफ नहीं है। दूसरा, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने बात कही कि पी.जी.आई में जो समस्याएं आती हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यहां से बहुत सारे मरीज पी.जी.आई. जाते हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.03.2017/1815/SLS-AS-1

श्री बलदेव सिंह तोमर...जारी

उनको वहां पर जो दिक्कतें होती हैं, उसके लिए अगर स्वास्थ्य विभाग या प्रदेश सरकार की ओर से कोई कर्मचारी वहां पर रोगियों का मार्ग दर्शन कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके तो उसका बड़ा लाभ होगा। शिलाई से हमारे सारे रोगी पांवटा साहिब के लिए रैफर किए जाते हैं। पांवटा में माननीय धूमल जी की बदौलत 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना है। उस हॉस्पिटल में ऑप्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वह बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लेबर रूम है, ओ.टी. है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। वह 4 विधान सभा क्षेत्रों

का केंद्रस्थल है। पांवटा में ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण रोज कोई-न-कोई दुर्घटना घटती है। इस कारण वहां ट्रौमा सैंटर की बड़ी आवश्यकता है। यह बात यहां पहले भी रखी गई है। अगर आप यहां से केंद्र सरकार को रिकोमैंडेशन भेजेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से ट्रौमा सैंटर की आवश्यकता पूरी होगी। वहां जो हॉस्पिटल बना है, उसमें डॉक्टर्ज़ टॉप फ्लोर पर बैठ रहे हैं जहां पेशैंट्स को पहुंचने में दिक्कत आती है। उसके लिए वहां लिफ्ट की आवश्यकता है। पिछली बार भी यह बात यहां उठी थी लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है। कृपा करके वहां लिफ्ट की व्यवस्था करें।

हमारे क्षेत्र में सरकार की ओर से मैडिकल कैंप लगते हैं जिनमें दिल्ली के आकाश हॉस्पिटल से डॉक्टर्ज़ की टीम आती है। शायद यह सभी जगह लग रहे हैं। सिरमौर में शिलाई और राजगढ़ में ऐसे कैंप लगे थे। मेरा निवेदन है कि जब ये कैंप शिलाई में लगते हैं तो वहां पर इतनी व्यवस्था नहीं है; वहां पर कोई ओ.टी. भी नहीं है। डॉक्टर्ज़ आते हैं और वहां ऑप्रेशन करके चले जाते हैं। उसके बाद रोगी को जो दिक्कत आती है उसके लिए उन्हें शिमला या चण्डीगढ़ रैफर किया जाता है। इस तरह उनको इंप्रूव करने में बड़ी समस्या होती है। इसलिए आप चैक करें कि जहां पर ऐसे कैंप्स लगते हैं वहां उस हॉस्पिटल में वांछित सुविधाएं हैं या नहीं? इसका कृप्या आप ध्यान रखें।

27.03.2017/1815/SLS-AS-2

आपसे मेरा निवेदन है कि जो हमारे दूर-दराज़ के क्षेत्र हैं वहां पर आप जगह-जगह संस्थान खोलने के बजाये जो बीच में एक संस्थान पड़ता है, उसको स्ट्रैंथन करने की कोशिश करें ताकि वहां पर एक्स-रे हो, डॉक्टर्ज़ हों, फार्मासिस्ट्ज हों ताकि वहां पर जो भी आस-पास से लोग आएं, उनको ठीक सुविधा मिल सके। सभी जगह संस्थान खोलने से, जहां केवल ताले लटके हों, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दें ताकि वहां पर भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री के. एल. ठाकुर जी इस मांग पर चर्चा करेंगे। ...(व्यवधान)...नहीं हैं।

अब श्री गोविन्द राम शर्मा जी इस मांग पर चर्चा करेंगे।

27.03.2017/1815/SLS-AS-3

श्री गोविन्द राम शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या : 9 पर दिए गए कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने प्रदेश और अपने-अपने क्षेत्र की बात यहां पर रखी। उसी दृष्टि में मैं भी कुछ बातें अपने जिला से संबंधित तथा अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं को आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जारी..श्री गर्ग जी

27/03/2017/1820/RG/DC/1

श्री गोविन्द राम शर्मा---जारी

स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क समाज के लिए अति आवश्यक हैं और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी सरकार हो, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत से डॉक्टर्ज और पैरा मैडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं, लेकिन जो हमारा जिले का अस्पताल है जिसमें न केवल सोलन जिला बल्कि वह सिरमौर जिले के भी दो विधान सभा क्षेत्र पच्छाद और श्री रेणुकाजी को भी फीड करता है। मैं एक दिन जब सोलन गया, तो इत्तफाक से कुछ रोगी वहां थे। मैं वहां अस्पताल चला गया। मैंने अस्पताल में जब सी.एम.ओ. और एम.एस. साहब से कुछ डॉक्टर्ज की चर्चा की, तो मैं सुनकर हैरान हो गया कि डॉक्टर्ज तो वहां पूरे 22 हैं, लेकिन जिस-जिस विभाग के डॉक्टर्ज वहां होने चाहिए, वे वहां नहीं थे। वहां विशेषज्ञ के 10 स्वीकृत पद हैं,

एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्ज के 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एम.बी.बी.एस. के वहां केवल मात्र दो डॉक्टर्ज हैं और जो आवश्यक हैं जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ की वहां बहुत आवश्यकता है, वह वहां नहीं है। इसी प्रकार वहां रेडियोलॉजिस्ट की बहुत आवश्यकता है, लेकिन वहां नहीं है। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ का भी जिक्र किया, तो वहां 35 पद हैं और 35 भरे हुए हैं। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि हमें लेबर रूम के लिए 6 और नर्स चाहिए। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उसके लिए कोई स्पेशल, यदि और जगह भी कुछ होता होगा, तो वहां के लिए 6 नर्स की स्वीकृति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करुंगा कि जब अस्पताल में सौ बैड थे तब डॉक्टर्ज के 21 पद स्वीकृत थे, लेकिन अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है और वह दो सौ बिस्तरों का अस्पताल हो गया है, परन्तु अब भी वहां डॉक्टर्ज के 22 पद स्वीकृत हैं। इसलिए उसमें भी बढ़ौत्तरी होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि उसमें भी बढ़ौत्तरी की जाए। इसके अतिरिक्त नर्सिंग एवं पैरा-मैडिकल स्टाफ में भी भर्ती करने की कृपा करें। इसी प्रकार से ऐक्स-रे तकनीशियन के तीन पद स्वीकृत हैं, परन्तु वहां केवल मात्र एक ही है। वह अस्पताल बहुत बड़ा है और बहुत से चुनाव क्षेत्रों से लोग इसमें अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। लैब टैक्नीशियन के तीन स्वीकृत पद हैं, लेकिन एक ही भरा है और दो पद खाली हैं। अभी माननीय मंत्री जी उठकर बाहर चले गए। चलिए, लेकिन स्टाफ कार्यवाही को नोट कर रहा है। इसी प्रकार से आपने वहां सी.एम.ओ. और एम.एस.

27/03/2017/1820/RG/DC/2

के स्टाफ को अलग कर दिया है। वहां जो एम.एस. का स्टाफ है उसमें 6 क्लर्क्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी भरा हुआ नहीं है। जब हम कुछ काम के लिए वहां गए, वहां गुप्ता साहब हैं, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक भी क्लेरीकल स्टाफ नहीं है। तो इसकी चिन्ता भी तो सरकार को करनी चाहिए। आप बहुत से अस्पताल खोल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, आप खोलें, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन खोलने से पहले जहां-जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां यह तो देखिए कि क्या वहां डॉक्टर या पैरा-मैडिकल स्टाफ है। वह कहीं पर नहीं है। बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो डॉक्टर यदि पोस्ट है, तो उसको मेरे चुनाव क्षेत्र अर्की में डिप्युट कर

देते हैं। अर्की में डॉक्टर्ज के 8 स्वीकृत पद हैं, एक बी.एम.ओ. है। हमारी सरकार के समय में वे सारे-के-सारे पद भरे हुए थे क्योंकि वह मुख्यालय था, लेकिन

एम.एस. द्वारा जारी

27/03/2017/1825/MS/DC/1

श्री गोविन्द राम शर्मा जारी------

जब मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि 5 पद वहां भर दिए गए हैं। उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि पिछले 4 सालों से वहां 2 और 3 डॉक्टर्ज थे। अब 2 डॉक्टर्ज की बढ़ोत्तरी हुई है इसके लिए मंत्री जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। मेरा कुनिहार का जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्ज के 6 पद स्वीकृत थे लेकिन अब वहां पद कम कर दिए गए हैं और केवलमात्र 2 डॉक्टर्ज हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वहां भी डॉक्टर्ज की कमी को दूर किया जाए क्योंकि वहां पर न केवल अर्की चुनाव क्षेत्र के लोग बल्कि सोलन, कसौली और कुछ दून चुनाव क्षेत्र के लोग भी उपचार के लिए आते हैं। इसलिए वहां पर जो डॉक्टर्ज के पद खाली हैं उनको आप तुरन्त भरने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों को इससे लाभ मिल सके। इसी तरह से फील्ड में फिमेल हैल्थ वर्कर और मेल हैल्थ वर्कर के पद भी मेरे चुनाव क्षेत्र में काफी खाली पड़े हुए हैं। कल ही मैं बेरल पंचायत में गया था। यह मेरी सबसे इंटीरियर पंचायत है जहां दरियापार में सुन्दर नगर लगता है। उसी पंचायत में आदरणीय मंत्री जी भी महीना-डेढ़ महीना पहले पहुंचे हुए थे। वहां के लोगों ने इनसे खाली पदों को भरने की बात की थी और इन्होंने वहां जनता को आश्वासन भी दिया था लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि कल जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि जो स्टाफ के लोग वहां लगे हुए थे उनको भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और वहां ताला लगा हुआ था। आदरणीय मंत्री जी आप बेरल पंचायत में गए थे और आपने वहां यह भी कहा था कि जो वहां स्टाफ की कमी है उसको पूरी करेंगे। कल जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां स्वास्थ्य उप-केन्द्र में ताला लगा

हुआ था। जब मैंने प्रधानों और उप-प्रधानों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य उप-केन्द्र अब शिफ्ट हो गया है लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यहां जो भी कमी होगी उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप कृपा करके देखें कि यह कैसे शिफ्ट हो गया है क्योंकि आपको पता है कि यह अति पिछड़ी हुई पंचायत है। सड़क तो मैंने वहां पक्की

27/03/2017/1825/MS/DC/2

करवा दी थी लेकिन अगर वहां डॉक्टर्ज न पहुंचे और बस न चले तो बड़े दुःख की बात है। मैंने वहां के लिए बस हेतु यहां विधान सभा में प्रश्न किया था। मंत्री जी मैंने आपसे यह भी निवेदन करना है कि जब आप बेरल गए थे तो आप बेरल से होते हुए बाघा-कंदर होते हुए आए। वहां पर कोई पी0एच0सी0 नहीं है। वहां बाघा या बेरल में कहीं भी पी0एच0सी0 खुल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यदि आप पी0एच0सी0 नहीं कर सकते तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां से ई0एस0आई0 अस्पताल के लिए रिकॉमेंडेशन दे दीजिए। ई0एस0आई0 केन्द्र से मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि मैं उसको केन्द्र से करवा लूंगा। जो भी आप देना चाहते हैं, चाहे पी0एच0सी0 दे दीजिए या पी0एच0सी0 नहीं देना चाहते तो ई0एस0आई0 अस्पताल के लिए रिकॉमेंडेशन दे दीजिए। मेरा केवल निवेदन है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां यदि कुछ स्टाफ होगा तो उससे वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी तरह से सारमा एक पंचायत है। यह सबसे आखिरी पंचायत है और यह भी बहुत कठिन एरिया है। उसमें भी स्वास्थ्य उप-केन्द्र में स्टाफ नहीं है। वैसे अन्य भी कई जगहों पर स्टाफ नहीं है। उसमें कम-से-कम जो फीमेल हैल्थ वर्कर या मेल हैल्थ वर्कर है यदि दो में से एक भी हो जाए तो इसका वहां के लोगों को लाभ होगा। मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस तरफ भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहां के लोगों को लाभ मिलेगा और मैं समझता हूं आपको मेरे चुनाव क्षेत्र का सबकुछ पता है। अभी जो आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में एक पी0एच0सी0 दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन आपकी घोषणा के मुताबिक यदि वहां पर डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ भी आ जाए तो धन्यवादी रहूंगा। इसके साथ-साथ जो इंटीरियर का क्षेत्र है, जैसे जय नगर या ऊपर कुहर का क्षेत्र है, यदि वहां पर भी पी0एच0सी0 खुल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27/03/2017/1825/MS/DC/3

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार जी बोलेंगे। Ruling Members can speak on Demands but not on Cut Motion. आप मांग पर बोलिए, आप कटमोशन पर नहीं बोल सकते।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की डिमाण्ड पर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

27.03.2017/1830/जेके/एजी/1

श्री कुलदीप कुमारः----**जारी**-----

हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। रूरल एरिया में रहती है और हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल टोपोग्राफी भी काफी डिफिकल्ट है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा लोगों तक पहुंचाना भी डिफिकल्ट है। लेकिन आज सरकार ने सभी को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जो पग उठाए हैं, वे काफी सराहनीय है। इन हालातों में हिमाचल प्रदेश में तीन-चार सालों में जो स्वास्थ्य सेवाओं का एक्सपैंशन हुआ है वह भी बहुत सराहनीय है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री काफी अनुभवी हैं जिनको यह विभाग मिला है। उन्होंने अपने तुजुर्बे के हिसाब से इस विभाग को काफी गति दी है। आप इसे साबित कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं मेरे कई माननीय दोस्तों ने इसकी सराहना भी की है कि यहां पर काफी संस्थान खुले हैं और उसके लिए धन्यवाद भी किया है। कुछ कमियों को भी यहां पर उजागर किया है या अपने इलाके में स्वास्थ्य संस्थान खोलने की मांग रखी है। हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। कभी ऐसा समय था कि यहां पर कोई मैडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था। हॉस्पिटल दूसरे प्रदेशों में हुआ करते थे। अगर कोई मरीज बच गया तो उसको चण्डीगढ़ तक पहुंचा दिया करते थे, पहले हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य

व्यवस्था यह थी। आज हम भाग्यशाली हैं, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 6 मैडिकल कॉलेज और एक डैंटल कॉलेज, 77 हॉस्पिटल, 88 कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर, 17 ई0एस0आई0 डिस्पैंसरीज़, 532 पी0एच0सीज0 और 2080 हैल्थ सब सेन्टर्ज हिमाचल प्रदेश में कार्यरत्त हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिन्तित है और कितने पग उठा रही है। अभी इस बजट में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है वर्ष 2017-18 में 109.70 करोड़ बजट सरकार ने इस विभाग को दिया है और इसमें काफी बढ़ौत्तरी की है ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ-साथ अगर आप हिसाब लगाएं तो हिमाचल प्रदेश में जो डैथ रेट है वह 6.6 है जबकि नेशनल रेट 6.5 है। वह भी यहां पर बराबर ही है।

27.03.2017/1830/जेके/एजी/2

चाईल्ड मोर्टेलिटी रेट 11 है और नेशनल चाईल्ड मोर्टेलिटी रेट भी 11 है । इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं । इसी के साथ-साथ यहां पर

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

27.03.2017/1835/SS-AG/1

श्री कुलदीप कुमार क्रमागतः

पिछले सालों में आपने देखा होगा कि जो सरकार ने प्रयत्न किये हैं, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवैंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डाइबिटीज शुरू हुआ। उसमें 2016-17 में 874894 लोगों का चैक अप किया गया। जोकि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की चिन्ता को दर्शाता है। इसके साथ-साथ जो नेशनल प्रोग्राम

ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनैस है --(व्यवधान)-- मैंने आपको हैल्थ इंडीकेटर बताए। कितना बढ़िया स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। आप इसमें क्या चाहते हैं? मंत्री जी, इसका जवाब देंगे और आपकी तसल्ली करवायेंगे। चिन्ता मत करो। मैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां बता रहा हूं। इसमें अच्छे कामों की प्रशंसा करो और जो कमियां हैं उसको बताओ। मैं सरकार के अच्छे कामों और उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहा हूं। जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनैस है इसमें 2016-17 में 16072 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किये गए और 15921 लैंसिज़ लगाये गये। 576 बच्चों को मुफ्त चश्मे लगाये गए। इसी के साथ-साथ मुफ्त दवा नीति के अन्तर्गत 56 दवाएं मुफ्त बांटने के लिए और 10 उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाने की भी अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ-साथ मंडी, टांडा, धर्मपुर, चम्बा, ऊना, बिलासपुर और नाहन में बिगड़े हुए क्षय रोग का तुरन्त पता लगाने के लिए सी0वी0एन0ए0टी0 मशीनें भी लगाई गईं ताकि क्षय रोग की तुरन्त जांच हो सके। --(व्यवधान)-- आप मेरी बात सुन लो। हमने आप सबको बोलने दिया। आपको खुशी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग ने इतनी बढ़िया तरक्की की है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सरकारी स्कूलों और गवर्नमैंट एडिड स्कूलों व आंगनबाड़ी बच्चे-बच्चियों सब की जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 161 मोबाईल हैल्थ टीम का गठन किया है और 2017 तक 9 हजार बच्चों की जांच की गई है। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ मंडी, धर्मशाला, सोलन, कुल्लू में डायलेसिज़ सुविधाओं को आरम्भ किया गया जोकि हमारे हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थी। ऊना, सिरमौर, बिलासपुर, शिमला में यह सेवा जल्दी ही शुरू होने जा रही है।

27.03.2017/1835/SS-AG/2

--(व्यवधान)-- बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। यह आपके सामने आ जायेगा। जनवरी, 2017 तक 102 जननी एम्बुलैंस सेवा आरम्भ की गई। इसके अंतर्गत 105630 लाभान्वित हुए। ये सारी जो बातें हैं वे इंडीकेटर हैं जिससे कि सारे हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं

की जानकारी ले सकते हैं कि कहां तक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है। माननीय मंत्री जी प्रयासरत हैं। यह बात ठीक है जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से यहां पर नए स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं और इतनी एक्सपैंशन हुई है उसके अन्तर्गत डॉक्टर्ज़, पैरा-मेडिकल स्टाफ को लगाना ज़रूरी है। उसके लिए सरकार दिन-रात प्रयासरत है। यहां यह परेशानी ज़रूर होती है। यह कहने की बातें हैं लेकिन जब डॉक्टर ट्रेनिंग करके आयेगा, एम0बी0बी0एस0 करके आयेगा, तभी लगेगा। यह तो नहीं है कि यहां पर लोग पकड़े और लगा दिये।

जारी श्रीमती के0एस0

27.03.2017/1840/केएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमार जारी---

पूरी ट्रेनिंग करेंगें, पैरा मैडिकल स्टाफ ट्रेनिंग करेगा, नर्सिज़ ट्रेनिंग करेंगी, ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर तैयार करने पड़ेंगें। इसके साथ-साथ डॉक्टर्ज़ के इंटरव्यू सरकार कर रही है ताकि हमारे जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनमें उनकी भर्ती की जाए । हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहां पर प्लेन के लोग, दूसरे प्रदेशों के डॉक्टर यहां आने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि सभी संस्थानों में पदों को भरा जाए। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करुंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूं कि तीन-चार सालों में हमारे अम्ब में एक सब डिविज़न हैड क्वार्टर है और ऊना का पहले यह दूसरा सब डिविज़न हैड क्वार्टर हुआ करता था । आधा ऊना जिला उस एरिया में पड़ता था । वहां पर आज तक सिविल हॉस्पिटल नहीं था। वहां पर एक कम्युनिटी हैल्थ सैंटर था। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि वहां पर सिविल हॉस्पिटल खोला और लगभग 5 करोड़ रु0 की बिल्डिंग भी दी। उसका उद्घाटन भी हो गया है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि सिविल हॉस्पिटल अम्ब में पूरे डॉक्टर हैं, पूरा पैरा मैडिकल

स्टाफ दिया है और वहां की जनता की वे सेवा कर रहे हैं। ऊना और अम्ब के सैंटर में एक दुसाड़ा गांव पड़ता है वहां पी.एच.सी. हुआ करती थी और ऊना और अम्ब के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई सहूलियत नहीं थी। मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का जिन्होंने वहां की पी.एच.सी. को अपग्रेड करके वहां पर बिल्डिंग के लिए ढाई करोड़ दिया । वहां बिल्डिंग का काम चला हुआ है और वहां पर एम्बुलैंस भी दी।

श्री महेन्द्र सिंहः कुलदीप जी, आप विपक्ष का समय ले रहे हैं।

श्री कुलदीप कुमारः मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात रख रहा हूं तब भी आपको तकलीफ हो रही है? महेन्द्र सिंह जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं अपने क्षेत्र चिन्तपुरनी की बात कर रहा हूं। माता चिन्तपुरनी का सभी मान करते हैं पता नहीं आपको क्या तकलीफ़ होती है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत एक्सिडैंट्स होते हैं

27.03.2017/1840/केएस/एएस/2

और एम्बुलैंस का वहां की जनता को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में इंटिरियर में चकसरांय नामक जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत दिक्कत थी। वहां पर पी.एच.सी. दी और वहां पर उसका उद्घाटन करके चालू कर दिया। पहले सिर्फ अनाऊंसमैंट्स ही होती थी लेकिन अब पी.एच.सी. भी खुली और डॉक्टर भी वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक मांग रखना चाहूंगा ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.3.2017/1845/av/as/1

श्री कुलदीप कुमार---------- जारी

माननीय मंत्री जी, आपने देखा है। हमारे चिन्तपूर्णी में (---व्यवधान---) अब मांग की बात आई तो आप (श्री महेन्द्र सिंह) (---व्यवधान---) चिन्तपूर्णी में बाजार को क्रोस करके सिविल होस्पिटल है। वहां पर बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एम्बुलैंस और डॉक्टर दे दिए हैं। कुछ डॉक्टर कम है, वह आपने पूरे कर देना लेकिन सिविल होस्पिटल का फूली युटिलाईज नहीं हो रहा है। वहां चिन्तपूर्णी में श्रद्धालु लोग 12 महीने चले रहते हैं। आज भी देखें तो वहां पर लाइनें लगी हैं। वहां अगर किसी मरीज को सिविल होस्पिटल ले जाना पड़े तो आप बाजार से क्रोस नहीं कर सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि चिन्तपूर्णी में जहां मल्टी पर्पज पार्किंग प्रोजैक्ट का काम चला है वहीं पर इसकी व्यवस्था कर दें ताकि लोगों को सुविधा हो सके और जनता उसका फायदा उठा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया। मैं इस मांग के पक्ष में बोल रहा हूं, धन्यवाद।

27.3.2017/1845/av/as/2

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (---व्यवधान---)

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कट-मोशन पर केवल विपक्ष की तरफ से बोलते हैं। आप तो पक्ष की तरफ के माननीय सदस्यों को अलाऊ कर रहे हैं। इसलिए हम बाहर जा रहे हैं।

Speaker: They have already given the names. ..(Interruption)..

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : आप लोग (विपक्ष) अपनी बात रख सकते हैं तो पक्ष के लोग क्यों नहीं रख सकते? आप अपने समय में बोलते रहें। यह कन्वैंशन आपके समय से चली आई है। आप बाहर जाकर लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से वॉकआऊट करके चले गये।)

अध्यक्ष : मैं इस माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि मेरे पास पक्ष की तरफ से पांच नाम आए थे। लेकिन मैंने सिर्फ दो को ही 5-5 मिनट के लिए अलाऊ किया है। उनमें से एक सदस्य बोल चुके हैं और एक बोल रहे हैं। इसमें क्या है? Every Hon'ble Member can speak on this. अभी जो विपक्ष की तरफ से ऑब्जैक्शन हो रहा था मुझे नहीं पता कि वॉकआऊट किस वजह से किया।। don't understand. मैं इसलिए कह रहा हूं कि । must clarify that any Member, even from Ruling, can speak on the Demand. There is no harm.

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में मांग संख्या : 9-पर चर्चा हो रही है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि एक ऐसा समय भी था जब हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा का नामोनिशान नहीं था। गांव में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और अस्पताल नहीं थे। डीलिवरी इत्यादि के केस केवल दाइयों पर निर्भर होते थे। मुझे याद है बैजनाथ में लंगु से दाई लानी पड़ती थी। वहां पर कोई होस्पिटल नहीं था। इसी तरह से हमारा जो छोटा भंगाल का क्षेत्र है वहां पर भी कोई पी0एच0सी0 एम्बुलैंस और डॉक्टर नहीं थे। बैजनाथ के

27.3.2017/1845/av/as/3

लोगों को इन्जैक्शन लगवाने के लिए भी पालमपुर या धर्मशाला जाना पड़ता था। लेकिन जैसे-जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें आती रहीं। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री बनें, इस बार ठाकुर कौल सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री है और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्थान हुआ है। इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। आज प्रदेश में 5-5 किलोमीटर की दूरी पर एक पी0एच0सी0 है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पी0एच0सी0 में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और चपड़ासी होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में दयोल में एक नई पी0एच0सी0 खुली।

श्री वर्मा द्वारा जारी

27/03/2017/1850/टी0सी0वी0-डी0सी0/1

श्री किशोरी लाल..... जारी

वहां डॉक्टर अप्वाईंट हुआ है, वहां पर पीयन अप्वाईंट है, वहां पर फार्मासिस्ट है। इस तरह से मेरी जितनी पी0एच0सीज़ हैं, उन सब में डॉक्टर तैनात हैं। बैजनाथ हॉस्पिटल में डॉक्टर की 8 पोस्टें हैं और वहां 8 डॉक्टर हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बैजनाथ हॉस्पिटल को जो 50 बैडिड हॉस्पिटल है, उसको 100 बैडडि करने का आश्वासन दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हॉस्पिटल शीघ्र ही 100 बैडों का होगा और वहां के लोगों को उपचार करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कभी समय था कि लोगों का ट्रीटमेंट ही नहीं होता था। अगर हार्ट की बीमारी होती थी, तो कहते थे कि "मूठ" आ गई और आदमी मर गया, लेकिन आज सरकार की अच्छी कारगुजारी से कम-से-कम डाईग्नोज़ तो होता है। आज हॉस्पिटल्ज़ में लैबोरेटरीज़ हैं, सारे टैस्ट वहां होते है और टैस्ट होने के बाद ही लोगों का इलाज़ होता है। आज अच्छा इलाज उन गरीब लोगों को मिल रहा है, जिनको डॉक्टर मुहैया नहीं होते थे। आज सरकारी हॉस्पिटल्ज़ में उनका मुफ़्त इलाज़ हो रहा है। कई लोग टी0बी0 से मर जाते थे। आज टी0बी0 मुक्त हिमाचल प्रदेश बना है, तो किसकी बदौलत-कांग्रेस पार्टी की सरकारों की बदौलत बना है। आज विपक्ष के साथी उठकर बाहर चले गये हैं। ये अपने व़क्त को याद करें। इन्होंने कौन-सा हॉस्पिटल खोला है। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कौन-सी तरक्की की है। ये सिर्फ हाला डाल देते हैं। इस तरफ कह देते हैं कि इनका नाक 'कडैरा' है, अपना नाक तो सीधा कर लें। इन्होंने कौन-सा काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज गांव-गांव में हैल्थ सब-सेंटर हैं। वहां पर मेल/फीमेल हैल्थ वर्कर काम कर रहे हैं। लोगों को उसका सीधा लाभ मिल रहा है और इनको कष्ट हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में क्यों आगे बढ़ा है? हमें खुशी है, हिमाचल प्रदेश सरकार, आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कांगड़ा के टांडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमें दिया है, जिसका सारा लाभ कांगड़ा ही नहीं

पड़ौसी जिले भी उठा रहे हैं। इसकी जितने सराहना की जाये, उतनी कम है। इनको पेट में मरोड़ इसलिए हो

27/03/2017/1850/टी0सी0वी0-डी0सी0/2

रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में जो "108 जननी सुरक्षा योजना" है, वह गर्भवती महिलाओं को उनको घर से ले जाती है और डिलीवरी के पश्चात् उनको मुफ़्त घर में छोड़कर आती हैं। इसलिए ये जो काम हिमाचल प्रदेश सरकार ने किए हैं, बहुत बेहतरीन काम स्वास्थ्य विभाग में किये हैं। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल रहा है। मैं इस मांग का पूरा समर्थन करता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जो भावना जगा रही है, उससे लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। जय हिन्द , जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

अध्यक्षः अब इस चर्चा का माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी इस चर्चा का उत्तर कल दे देते हैं, क्योंकि अभी और सदस्य भी बोलने चाहते हैं। सर, मेरा निवेदन यह है कि यह अच्छा रहेगा कि मैं विपक्ष के सामने जवाब दूं। ताकि उन्होंने जो मामले उठाए हैं, उनका मैं ठीक तरीके से रिप्लाई दे सकूं।

अध्यक्षः अब राम कुमार जी बोलेंगे।

27/03/2017/1850/टी0सी0वी0-डी0सी0/3

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस दिन से

सदन चला है विपक्ष का एक ही रोना रहा है, चाहे वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात हो, चाहे बजट का विरोध करने की बात हो। अब कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी सभी विपक्ष के सदस्य उन्हीं बातों को रिपीट रहे हैं। इनके पास बोलने के लिए नया कुछ नहीं है, खाली विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बीच-बीच में भी इनको जवाब देते रहे हैं। जब माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था

श्रीमती एन.एस. ....द्वारा जारी।

27/03/2017/1855/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री राम कुमार ----- जारी

इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, खाली विरोध कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बीच-बीच में जबाव दिया है। जब माननीय महेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब केंद्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी, उस समय मण्डी में ई0एस0आई0 हॉस्पिटल में ट्रॉमा सैंटर 900 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया था। जिसको चलाने के लिए इन्होंने (विपक्ष) इन्कार कर दिया था। जो इसकी बकाया राशि पड़ी थी, इनकी सरकार ने उस बकाया राशि को देने से मना कर दिया था। तीन साल केंद्र में भाजपा की सरकार को बने हुए हो गये हैं। माननीय गुलाम नबी आजाद जो यू0पी0ए0 सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने तीन मेडिकल कॉलेज सिरमौर, हमीरपुर और चम्बा में हिमाचल प्रदेश को दिए थे। जिसमें से सिरमौर का मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है और बाकी दो मेडिकल कॉलेज यह अभी तक शुरू नहीं करवा पाये हैं। प्रदेश सरकार ने चार वर्ष के कार्यकाल में जरुरत और डिस्टैंस के हिसाब से तथा आबादी के हिसाब से जो अस्पताल

खोले है, पी0एच0सीज0, सी0एच0सीज0 और सब-हैल्थ सैंटर खोले हैं, उनका ये (विपक्ष) अंदर रोज विरोध कर रहे हैं। बाहर जा करके लोगों को ये जबाव देते हैं कि हम तो विपक्ष में है इसलिए हमें बोलना पड़ता है। ऐसा जबाव ये बाहर लोगों को देते हैं। मेरे हिसाब से यह बड़ी शर्मनाक बात है। जो भी सरकार बनती है, वह जनता की भलाई के लिए बनती है। जनता को जिन सुविधाओं की जरुरत होती है सरकार को निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। माननीय वीरभद्र जी की सरकार पूरी निष्ठा, पूरी आस्था से लोगों की मांग पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र में इससे पहले कोई सी0एच0सी0 नहीं थी। माननीय राजा साहब और माननीय कौल सिंह जी ने मेरे क्षेत्र में सी0एच0सी0 खोली है। मेरा क्षेत्र दो भागों में बंटा है। एक पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा मैदानी क्षेत्र। इन्होंने एक सी0एच0सी0 पहाड़ी क्षेत्र चण्डी में और दूसरी बद्दी के मैदानी इलाके में दी है। इसके साथ ही माननीय राजा साहब का पीछे जब नालागढ़ का दौरे पर थे तो मेरे

27/03/2017/1855/ एन0एस0/डी0सी0 /2

एडज्वाईनिंग एरिया में जो पुराना दून क्षेत्र रामशहर का पड़ता है, वहां पर भी इन्होंने सी0एच0सी0 दी है और इसकी नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। मेरे क्षेत्र से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुनिहार क्षेत्र पड़ता है, इन्होंने वहां पर भी सी0एच0सी0 दी है। वहां पर लोगों ने अपना चन्दा इक्ट्ठा करके बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनवाया है, उसका भी माननीय राजा साहब ने उद्घाटन किया है। सी0एच0सी0 के साथ-साथ मेरे क्षेत्र में इन्होंने बाबा हरिपुर में एक पी0एच0सी0 दी है, उसका शिलान्यास अभी 26 तारीख को होना था जो कि पोस्टपोन हो गया है। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में जो पुराने समय के हैल्थ सब-सैंटर चल रहे थे, वहां पर भवन नहीं थे, उनमें हैल्थ सब-सैंटर, चढियार और त्रिंगाला आदि के भवन निर्माण के लिए भी पैसा दिया है। इनका भवन निर्माण हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने रामपुर सब-सैंटर के भवन निर्माण के लिए भी पैसा दिया है, इसका भी काम शुरू होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को पूछना चाहता हूं कि क्या यह डिवेल्पमैंट नहीं है? क्या यहां के लोगों को हैल्थ सुविधाओं की जरुरत नहीं थी? निश्चित तौर पर यहां के लोगों

को इन सुविधाओं की जरुरत थी। यहां के लोगों को आठ-आठ किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, वहां पर इन सुविधाओं की मांग थी। माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जहां पर दूरी के हिसाब से जरुरत है, आप वहां सुविधाएं मांगेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उनको पूरा करूंगा। इसके अतिरिक्त हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी है, वर्ल्ड में टोरेंटो के बाद बद्दी का नाम फार्मास्युिटिकल के तौर पर वर्ल्ड मानचित्र में आता है। वहां पर लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार (भाजपा) सरकार से मांग की थी, जो कि एक वर्ष पहल बद्दी क्षेत्र में आए थे, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और फार्मास्युिटीकल के लोगों ने मांग की थी कि आप यहां पर एक 'बल्क ड्रग पार्क' की घोषणा करें। अध्यक्ष महोदय, उसकी घोषणा हुए भी एक साल का समय हो गया है। प्रदेश सरकार की डयूटी उसके लिए जमीन उपलब्ध करवाने की थी। उन्होंने उस समय कहा कि जैसे ही आप जमीन उपलब्ध करवायेंगे तो हम तुरन्त इसकी नोटिफिकेशन करवा देंगे

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

27/3/2017/1900/RKS/AG/1

श्री राम कुमार... जारी

लेकिन एक वर्ष बीत गया जो चीजें केंद्र सरकार ने देनी थी या केंद्र सरकार द्वारा खोली जानी थी वे इनको नज़र नहीं आती है। बल्क ड्रग पार्क का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जबकि प्रदेश सरकार ने 1000 बीघा जमीन नालागढ़ में उपलब्ध करवा दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि जमीन कम है। इंडस्ट्री विभाग ने 900 बीघा और जमीन का चयन कर लिया है। प्रदेश सरकार और जमीन देने के लिए तैयार है परन्तु कार्य तो शुरू हो।

अध्यक्षः माननीय सदस्य 7 बज चुके हैं, how long would you like to speak?

श्री राम कुमारः सर, मैं तीन मिनट और बोलूंगा।

अध्यक्षः इस माननीय सदन की बैठक 5 मिनट और बढ़ाई जाती है।

श्री राम कुमारः सर, धन्यवाद। भारत सरकार में हमारे प्रदेश के श्री नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। सोलन जिला सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर एक ई.एस.आई. की मांग की जाती तो इससे सोलन जिला को बड़ा फायदा होता। मैंने पिछले सदन में मांग उठाई थी कि आम जनता को आपातकालीन सेवाओं के लिए ई.एस.आई. बद्दी में खोला जाए। आपातकालीन सेवा के लिए तो यह खुल गया लेकिन आम जनता की आम बीमारी की ओ.पी.डी. के लिए नहीं खोला गया। मैं चाहता हूं कि मेरे विपक्ष के दोस्त केंद्र सरकार से मांग करें कि ई.एस.आई. बद्दी को पी.जी.आई. की तर्ज पर सभी बीमारियों के उपचार के लिए खोलने का प्रयास करें। एम्ज़ जो हमें बिलासपुर के लिए मिला था उसके लिए प्रदेश सरकार ने भूमि उपलब्ध करवा दी है। लेकिन उसका कार्य अभी तक आप शुरू नहीं करवा पाए। जो बातें प्रदेश सरकार के विरुद्ध आप करते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यह कर दिया, वह कर दिया, मैंने बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में लाई हैं। जो संस्थान केंद्र से हमें मिले हैं या हमने उनके लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई है उनका कार्य शुरू करवाने के लिए केंद्र पर

27/3/2017/1900/RKS/AG/2

उनका कार्य शुरू करवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस मांग का समर्थन करता हूं। जय हिंद।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी इस मांग संख्या पर कल जवाब देंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 28 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **श्री सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 27 मार्च, 2017 **सचिव ।**